

वैश्विक संवाद

8.3

17 भाषाओं में एक वर्ष में 3 अंक

नैन्सी फ्रेजर के साथ समाजशास्त्र पर बातचीत

क्रिस्टिन शिकर्ट

लोकतंत्र को चुनौती

होके ब्रंकहोस्ट
किश्चियन फूच्स
एंड्रिया सिल्वा-तापिया
हर्लेगिबे न्दलोरु
गेरासिमोस कौउजेलिस
हरियाती अब्दुल करीम
एस्तेबान टोरेस कस्तानोस
एमी ऑस्टिन होलम्स
पीटर वाहल

स्मृति में : अनिबाल क्विजनो

निकोलस लिंग
रेक्वेल सोसा एलिज़ागा

निर्धनता का सामना

जोशुआ बडलैण्डर
वसिलिस एसापोग्लू
जुलियाना मार्टिनेज फ्रेंजोनी
फैबियन केसल
मुस्तफा कोक

सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य

सुजाता पटेल

पोलैंड में समाजशास्त्र

मार्टा बुकोलक
जेन ज़ारास्ती
जुलियसज़ गरडावस्की
एडम ग्रोजेविकी
वेरा ट्रेप्पमन्न
कटारज्याना देबस्का
सारा हेर्जिस्का
जुस्तयना कोस्सिंस्का
कामिल ट्रेपका
मासीज रडूला

पत्रिका



International
Sociological
Association
ISA

अंक 8 / क्रमांक 3 / दिसम्बर 2018
<http://globaldialogue.isa-sociology.org/>

GD



> संपादकीय

दुनिया भर के कई देशों में, लोकतांत्रिक सस्थाओं और प्रक्रियाओं को चुनौतियों और दबाव में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। युवा और पुराने लोकतंत्रों में समान रूप से सत्तावादी प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है : शीर्ष नीचे नेतृत्व दुबारा प्रमुखता प्राप्त करता है, राष्ट्रवाद बढ़ रहा है और राजनैतिक अधिकारों पर प्रतिबंधों से नागरिक समाज कमजोर हुआ है। विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमले हुए हैं। वैश्विक संवाद के इस अंक को प्रारम्भ करने वाले साक्षात्कार में, आज की सबसे प्रसिद्ध और विचारोत्तेजक नारीवादी विचारकों में से एक, नैन्सी फ्रेजर इस विकासक्रम के कुछ पहलुओं को उठाती है जब वे अधिक समावेश नारीवादी आंदोलन के निर्माण पर प्रश्न करती है और 99 प्रतिशत के लिए नारीवाद पर उनके विचारों पर चर्चा करती हैं।

“लोकतंत्र को चुनौती” पर हमारे प्रथम निबन्ध संग्रह में आलेख दुनिया के विशिष्ट हिस्सों में रंगभेद पश्चात के दक्षिण अफ्रीका में स्थिति से लेकर ग्रीस जैसे देश में मितव्ययता की राजनीति की चुनौती और मिश्र की क्रांतियों के वर्णनों में से महिलाओं का विलोपन से लोकतंत्र किस प्रकार से दबाव में हैं, की जांच करते हैं। जहां लेखक नये घटनाक्रमों जैसे पूंजीवाद में सत्तावादी मोड़ का वर्णन और विश्लेषण करते हैं, वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उद्देश्य वाली अवधारणाओं और विचारों का भी मूल्यांकन करते हैं।

मई 2018 में, पेरू और लेटिन अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित समाजशास्त्री अनिबाल विवजानों का 87 वर्ष की आयु पर निधन हो गया। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और “शक्ति की औपनिवेशिकता” पर उनकी अवधारणा पर उनके कार्य ने दुनिया भर के समाजशास्त्रियों की पीढ़ियों को प्रभावित किया है। उनके दो करीबी सहयोगी और मित्र उनके जीवन में झांकते हैं और उनकी

विरासत का जश्न मनाते हैं।

“निर्धनता का सामना” शीर्षक वाले हमारे दूसरे निबन्ध संग्रह में, हमने निर्धनता की विभिन्न अभिव्यंजनाओं का विश्लेषण करने वाले आलेखों को एकत्रित किया है। ये लेख ग्रीस में मितव्ययता की राजनीति का प्रभाव से लेकर दोस्ताना राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बावजूद लेटिन अमेरिका में निर्धन महिलाओं की बढ़ती संख्या के बारे में हैं। दुनिया भर से छह लेखकों को निर्धनता के विशिष्ट प्रादेशिक विकास एवं इसके विरुद्ध नीतियों द्वारा सामना किये जाने वाले अवरोधों पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित किया गया।

वैश्विक आधुनिकताओं पर अपने लेख में सुजाता पटेल, भारत की एक प्रमुख समाजशास्त्री, वैश्वीकृत विश्व में इस सिद्धान्त की प्रकृति और अंतर्वस्तु पर चर्चा करती हैं। वे बहुल आधुनिकताओं की इस अवधारणा और इसकी आलोचनाओं पर ऐतिहासिक और सैद्धान्तिक अर्न्तदृष्टि प्रदान करती हैं।

प्रारम्भ से, पोलिश विचारकों ने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसलिए यह अंक पोलैंड के इतिहास पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लेकिन यह सिर्फ इतिहास नहीं है जिसने हमें इस देश पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया बल्कि वह उनका ज्वलंत समाजशास्त्र था जो हमारे समय के कई मुद्दों पर आज संलग्न है। लेख पाठकों को वर्तमान शोध जैसे युवा असुरक्षित श्रमिकों पर अध्ययन, पोलिस के हालिया मतदान व्यवहार के साथ-साथ पोलिश सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन और उनका आज के समाजशास्त्र पर प्रभाव से रूबरू करवाते हैं। ■

ब्रिजिट ऑलेनबाकर और क्लॉस डोरे,
वैश्विक संवाद के संपादक

- वैश्विक संवाद आई.एस.ए वेबसाइट पर 17 भाषाओं में देखा जा सकता है।
- प्रस्तुतियाँ <globaldialogue.isa@gmail.com> पर भेजी जा सकती है।

isa International
Sociological
Association

**GLOBAL
DIALOGUE**



> संपादक मण्डल

संपादक : ब्रिजित ऑलेनबॉकर, क्लॉस डोरे

सह-सम्पादक : जोहाना ग्रबनर, क्रिस्टीन शिकर्ट

सहयोगी सम्पादक : अर्पणा सुन्दर

प्रबंधन संपादक : लोला बुसुतिल, अगस्त बागा

सलाहकार : माइकल बुरावे

मीडिया सलाहकार : गुस्तावो तनीगुती

परामर्श संपादक :

साडी हनाफी, ज्योफी प्लियर्स, फिलोमिन गुतिरेज, एलोइजा मार्टिन, सावाको शिराहेस, इजाबेला बरलिनका, तोबा बेन्सकी, चिह—जुए जे चेन, जेन फिट्ज, कोइची हासेगावा, हिरोशी इशिदा, ग्रेस खुनो, एलिसन लोकोन्तो, सुसन मेकडेनियल, एलिना ओइनास, लोरा ओसो कैसास, बंडाना पुर्कायस्था, रोहडा रेडॉक, मौनीर सैदानी, आयसे सकतांबर, सेली स्कालोन, नाजानीन शाहरोकनी।

क्षेत्रीय संपादक

अरब दुनिया : साडी हनाफी, मौनीर सैदानी।

अर्जेंटीना : जुआन इग्नासियो पियोवानी, एलेक्जेंड्रा ओतामेंडी, पिलर पी पुइग, मार्टिन उर्दुसन।

बंगलादेश : हबीबुल हक खंडकर, हसन महमूद, जुवेल राणा, यूएस रोकेंय अख्तर, तूफिका सुल्ताना, असिफ बिन अली, खैरून नाहर, काजी फदिया एशा, हेलल उदीन, मुहिमिन चौधरी, मोहम्मद यूनुस अली।

ब्राजील : गुस्तावो तानिगुती एंड्रेजा गली, लुकास अमरल ओलिविरा, बेनो वार्कन, एंजेलो मार्टिन्स जूनियर, दिमित्री सेबॉनीनी फर्नांडीस।

फ्रांस/स्पेन : लोला बुसुतिल

भारत : रश्मि जैन, ज्योति सिडना, प्रज्ञा शर्मा, निधी बंसल।

इंडोनेशिया : कमांतो सुनार्तो, हरि नुग्रोहो, लूसिया रतीह, कुसुमादेवी, फिना इद्रियती, इंदेरा रत्ना इरावती पट्टिनसारानी, बेनेडिक्टस हरि जूलियावान, मोहम्मद शोहीबुद्दीन, डोमिंगस एलसीड ली, एंटोनियस एरियो सेतो हार्डजाना, डायना तेरेसा पाकासी, नुरुल ऐनी, गेगेर रियांतो, आदित्य प्रदान सेतियादी।

ईरान : रेयहाने जावदी, नियाश डॉलाती, सिना बस्तानी, सैयद मोहम्मद मुतालेबी, वाहिद लेन्जानगदे।

जापान : सतोमी यामामोतो, सारा मेहारा, मसातका एगुची, यूको मसुई, रिहो तनाका, मेरी यायामोतो, कओरी हाचिया, अयाना कानेयुकी, एरिका कुगा, काया ओजावा, त्सुकासा शिबागकी, मिचियाकी युआसा, रिकुहो बाबा।

कजाकस्तान : अइगुल जाबिरोवा, बायन र्मागमबेट, आदिल रोदियोनोव, अल्माश त्लेसपयेवा, कुआनिश टेल, अलमागुल मुस्सीना, अकनूर ईमानकुल।

पोलैंड : जेकब बारस्जेवस्की, इवोना बोजादजिजेवा, कतार्जीना देवस्का, पोलिना दोमागलस्का, करजिस्तोफ गुबांस्की, सारा हरस्जींस्का, जुस्तिना कोसिंस्का, लुकजा लांगे, एडम मुलर, जोफिया पेन्जा—गेबलर, अन्ना वांडजेल, जासेक जिच।

रोमानिया : कोसिमा रुधिनिस, राइसा—गेब्रियला जमीफिरेस्कू, लूसियाना एनास्तोसोई, एड्रियाना लेविनीया बुलामाक, क्रिस्चयन चीरा, देनिसा दान, डायना एलेक्सेंड्रा डुमित्रेस्कू, राडू डुमिस्ट्रेस्कू, युलिआन गेबर, एलेक्सांड्रा इरिमि—एना, बियांका मिहायला, एंड्रिया एलेना मोल्दोवीनु, रासेस—मिहाई मुसत, ओना—एलेना नेग्रिया, मिओआरा पराशिव, एलिना क्रिस्टीना पॉन, कोद्रुत पिनजारू, सुसाना मरिया पोपा, एड्रियाना सोहोदोलानु, एलेना ट्युडर।

रूस : एलेना ज्दवोम्यस्लोवा, अनास्तासिया दौर, वेलेंटीना इसाएवा।

ताईवान : जिंग—माओ हो।

तुर्की : गुल कोरबासियोग्लू, इरमक एवरेन।



दुनिया के कई हिस्सों में लोकतंत्र दबाव में है। इस परिचर्चा में आठ समाजशास्त्री विभिन्न देशों में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों को उजागर करते हैं और चर्चा करते हैं कि लोग कैसे अधिक लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं एवं समकालीन राजनैतिक रीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं।



निर्धनता का विषय और निर्धनता का सामना करने वाले लोगों की वास्तविकता हमेशा से समाजशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। इस परिचर्चा में दुनिया से पांच विद्वान निर्धनता में कमी लाने वाली नीतियों के विशिष्ट प्रादेशिक घटनाक्रम (या उनके अभाव वाली) पर चर्चा करते हैं और खाद्य सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता वाले विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न प्रक्षेप वक्रों का विश्लेषण करते हैं।



यह खण्ड पोलिश समाजशास्त्र के ऐतिहासिक विकास के परिचय के साथ इस देश में वर्तमान समाजशास्त्रीय शोध पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।



सेज प्रकाशन की उदार ग्रांट से वैश्विक संवाद का प्रकाशन संभव है।

> इस अंक में

संपादकीय 2

> समाजशास्त्र पर बातचीत

नवउदारवाद समय में नारीवाद :

नेन्सी फ्रेजर के साथ एक साक्षात्कार

क्रिस्टिन शिकर्ट, जर्मनी 5

> लोकतंत्र को चुनौती

लोकतंत्र का संकट

हौके ब्रंकहोस्ट, जर्मनी द्वारा 9

सत्तावादी पूंजीवाद का उदय

किश्चयन फुच्स, यूनाइटेड किंगडम द्वारा 11

अवैध नागरिकता के रूप में नस्लीय नागरिकता

एंड्रिया सिल्वा-तापिया, जर्मनी द्वारा 13

1994 के पश्चात दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र का मुलावा

हलेंगिबे न्दलोरु, दक्षिण अफ्रीका द्वारा 15

एथेन्स में लोकतंत्र

गेरासिमोस काउजेलेस, ग्रीस द्वारा 17

सामाजिक मीडिया एवं लोकतंत्र : एक दोधारी तलवार

हरयाती अब्दुल करीम, मलेशिया द्वारा 19

अर्जन्टीना में लोकतंत्र

एस्टेबन टोरेस कस्तानोस, अर्जन्टीना द्वारा 21

मिस्र की क्रांति से महिलाओं का विलोपन

एमी ऑस्टिन होल्मस, मिस्र द्वारा 23

वैश्विक शासन : लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था

के लिए एक अवधारणा 25

पीटर वाहल, जर्मनी द्वारा

> स्मृति में : अनिबाल क्विजानो, 1928-2018

एक उत्कृष्ट प्रकृति के बुद्धिजीवी

निकोलस लिंग, पेरू द्वारा 27

एक यौद्धा की खुशी

रेक्वेल सोसा एलीज़ागा, मेक्सिको द्वारा 29

> निर्धनता का सामना

पोस्ट नस्लीय निर्धनता की

मुख्य विशेषताएं

जोशुआ बुडलेण्डर, यू.एस.ए. द्वारा 30

बेल-आउट के उपरान्त का कल्याण: यूनान में निर्धनता का नया प्रारूप

बसीलिस एरापोग्लू, ग्रीस द्वारा 32

लेटिन अमेरिका में अधिक निर्धन महिलाएं क्यों हैं?

जुलियाना मार्टिनेज फ्रेंजोनी, कोस्टा रीका द्वारा 34

“चैरिटी अर्थव्यवस्था” : कल्याणकारी राज्य की छाया में

फेबियन केसल, जर्मनी द्वारा 36

खाद्य सुरक्षा विमर्श : 21वीं सदी के लिए चुनौतियां

मुस्तफा कोस, कनाडा द्वारा 38

> सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य

वैश्विक आधुनिकता

सुजाता पटेल, भारत द्वारा 40

> पोलैंड में समाजशास्त्र

(कहां) क्या हमारा महत्व है? पोलिश समाजशास्त्र पर पार्श्व दृष्टि

मार्ता बुचोल्क, जर्मनी/पोलैंड द्वारा 43

पोलैंड और जर्मनी में युवा असुरक्षित कामगार

जेन जारज़ास्ती, जुलियूस्ज गारदावस्की, एडम मरोज़ोविकी, पोलैंड

एवं वेरा ट्रैप्पस्मन, यूनाइटेड किंगडम द्वारा 45

दक्षिण पंथी दलों के लिए लोग मत क्यों डालते हैं?

कतारजेयना देबस्का, सारा हरज़िंस्का, जुस्तिना कोसिंस्का

एवं कमिल ट्रैपका, पोलैंड द्वारा 47

नये सार्वजनिक क्षेत्र में समाजशास्त्र की संभावनाएं

मासिसेज़ ग्दूला, पोलैंड द्वारा 49

“हमारी वर्तमान दुनिया में, हम अब सांस्कृतिक रूप से, नस्लीय रूप से या प्रजातीय तौर पर सजातीय राष्ट्र-राज्यों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिन्हें चुप करा दिया गया को सुनना एक ऐसा ऐतिहासिक ऋण है जिसे लोकतंत्र को गहरा करने के खातिर चुकाना पड़ेगा।”

एंड्रिया सिल्वा तापिया

> नवउदार काल में नारीवाद

नैन्सी फ्रेजर के साथ एक साक्षात्कार



नैन्सी फ्रेजर

नैन्सी फ्रेजर आज की सबसे महत्वपूर्ण आलोचन सिद्धान्तकार एवं नारीवादी विचारक हैं। वे न्यूयॉर्क स्थित न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च में दर्शनशास्त्र एवं राजनीति की प्रोफेसर हैं। व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले प्रकाशनों, जिसमें रिडिस्ट्रिब्यूशन ऑफ रिकग्निशन? अ पोलिटिकल-फिलोसोफिकल एक्सचेंज (2003), एक्सेल होनेथ के साथ बहस में वे न्याय और अन्याय की एक सैद्धान्तिक अवधारणा विकसित करती हैं। वे बहस करती हैं कि न्याय को दो तरीकों से अवधारणाबद्ध किया जा सकता है: वितरणात्मक न्याय एवं मान्यता का न्याय के रूप में उनका दावा है कि आज के अन्यायों से लड़ने के लिए पुनर्वितरण और मान्यता दोनों मुख्य हैं। उन्होंने एक विद्वान और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में नारीवाद और नारीवादी मुद्दों पर बड़ी संख्या में पुस्तकों और लेखों का प्रकाशन किया है। उनमें से एक फॉरव्यून्स ऑफ फेमिनिज्म: फ्रॉम स्टेट मेनेज्ड कैपिटलिज्म टू नियोलिबरल क्राइसिस (2013) है। यहां जेना विश्वविद्यालय, जर्मनी में समाजशास्त्र विभाग में पोस्ट-ग्रोथ सोसाइटी पर शोध समूह की प्रशासकीय निदेशक एवं वैश्विक संवाद की सहायक संपादक क्रिस्टिन शिकर्ट उनका साक्षात्कार लेती हैं।

सीएस: आपके लेख “नारीवाद, पूंजीवाद और इतिहास की चालाकी” के प्रकाशन को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। इसमें आप मूल रूप से तर्क देती हैं कि मुख्यधाराई या उदार नारीवाद को पूंजीवाद अपने स्वयं के लक्ष्य के लिए सहयोगित करता है। क्या आप इस तर्क को यहां रेखांकित कर सकती हैं?

एनएफ: मैं उस लेख को एक बहुत ही विशिष्ट पल में लिख रही थी जो तब था जब विश्व वित्तीय संकट सामने आ रहा था और उम्मीद और परिवर्तन के बारे में बात करते हुए बराक ओबामा राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। यह वह समय था जिसमें सभी ने स्वीकार किया कि हम बहुत ही निर्णायक और डरावने क्षण में थे और बहुत

उम्मीद थी कि कुछ भिन्न हो सकता है। उस क्षण के बारे में ऐसा कुछ था जिसने मुझे अचानक इन क्षणों के इतिहास और समग्र रूप से नारीवाद के इतिहास के बारे में सोचने के लिए सक्षम बनाया। लम्बे समय से मैं उदार या मुख्यधारा नारीवाद की दिशा से नाखुश थी, जिसके बारे में मैंने पहले पहचान पर अधिक फोकस और वितरण पर कम ध्यान के बारे में लिखा था लेकिन इस ने मुझे संकट की घड़ी का अधिक स्पष्ट दृश्य दिखाया।

मेरी सोच यह थी कि नारीवाद के विकास के साथ-साथ और समानांतर चल रही पूंजीवादी समाज की प्रकृति में प्रमुख बदलाव आया था। जब 1960 के दशक के उत्तरार्ध और 1970 के दशक

के पूर्वार्ध में नारीवाद की द्वितीय लहर उभरी तो हम वास्तव में किनारे पर थे और हम सोच रहे थे कि हम अभी भी एक सुरक्षित, सामाजिक लोकतांत्रिक या राज्य-प्रबंधित पूंजीवादी शासन में कार्य कर रहे थे। हमने सोचा कि जो लाभ यह शासन लाया वे कमोबेश सुरक्षित थे और हम वहां से अधिक अतिवादी समतावादी और लोकतांत्रिक दुनिया में जा सकते हैं। जहां नारीवाद एक प्रमुख कर्ता होगा।

यद्यपि, इसके बजाय जो हुआ वह सामाजिक लोकतंत्र का संकट था, जो प्रकट होने वाला था और नवउदारवाद का उभार था। यह पूंजीवाद का पूर्णतया नया स्वरूप था और नारीवादी — न सिर्फ नारीवादी अपितु कई प्रगतिशील, सामाजिक आंदोलन कार्यकर्ता — इसको समझने में धीमे थे; सरल शब्दों में, हम अभी भी इस तरह के मान्यता/पहचान केन्द्रित एजेण्डा को बिना यह समझे कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था कैसे बदल गई, जारी रख रहे थे। अब सिर्फ यह नहीं था कि हम पुनर्वितरण के बारे में भूल गये, बल्कि यह कि बिना समझे कम से कम कई लोगों ने इसे नहीं समझा — हम वास्तव में नवउदारवाद के लिए कुछ सकारात्मक और आवश्यक योगदान दे रहे थे। हमने इसे हमारे उदारकारी, विमुक्ति वाले करिश्मा को प्रारम्भ किये जाने वाले राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नये प्रतिगामी शासन के लिए वैध उपकरण या गवाह के रूप में उपयोग करने की इजाजत दे कर एक तरह का करिश्मा और वैधता प्रदान की थी।

यह तर्क था चूंकि जाहिर तौर पर 2008-09 में हम संकट की घड़ी में थे, मैंने सोचा कि यह एक ऐसा समय है जब, जैसा मैंने निबंध के अंत में कहा, बड़ा सोचना, हट के सोचना, बदलाव या मार्ग सुधार के द्वारा एक नये प्रकार के नारीवाद, जिसमें हम वास्तविक नवदार-विरोधी प्रोजेक्ट के भाग हो सकते हैं, को पेश करना संभव होगा।

सीएस: मैं कल्पना कर सकती हूं कि नारीवादी कार्यकर्ताओं या विद्वानों के रूप में ज्ञात कई महिलाओं ने नारीवादी मुद्दों के लिए उनके कार्य पर प्रश्न लगते देखा और उन्होंने आपके विश्लेषण पर प्रतिरक्षात्मक रूप से प्रतिक्रिया दी।

एनएफ: जब मैंने यह निबन्ध प्रकाशित किया, मुझे अपेक्षा थी कि मुझे काफी पीछे धकेला जाएगा। हकीकत यह है कि मुझे अपेक्षा से कहीं कम मिला, कम से कम उन शैक्षणिक हलकों में जिनमें मैं घूमती हूं। चाहे लोग मुझ से पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे, उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ पता चला था और नारीवादी के साथ कुछ गलत हो गया था। एक व्यापक भावना थी कि जिस दुनिया को हम बनाने की सोच रहे थे, वह दुनिया वह नहीं थी जिसमें हम वास्तव में रह रहे हैं। मेरी आशा से ज्यादा लोग थे जो इस थीसिस के बारे में सोचने के इच्छुक थे।

मेरा मानना है कि यह न तो आरोप है न ही दोषारोपण का प्रश्न है, बल्कि यह समझने की अत्यावश्यक जरूरत थी कि कैसे प्रगतिशील नवउदार प्राधान्य का एक निश्चित स्वरूप स्वयं को निर्मित करने में सफल हुआ और उस समय की सहज समझ की लड़ाई जीत गया। मुझे लगता है कि हमें यह जानने की जरूरत है कि हमने अनजाने में क्या भूमिका अदा कर दी, ताकि हम बेहतर कर सकें और अपने मार्ग में सुधार लाएं। कोई भी श्वेत नारीवादी को अश्वेत महिलाओं का

यह आरोप सुनना पसंद नहीं था कि हमने बिना किसी मंतव्य के, श्वेत वर्चस्व से बंधी या जो वर्ण की महिलाओं की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील नहीं थी, कई मान्यताओं को दोहराया। लेकिन हमें सुनना पड़ा और हमें इसे अवशोषित करना पड़ा और मुझे लगता है कि इसके लिए भी यह सच है। पहली प्रतिक्रिया अक्सर रक्षात्मक होती है, लेकिन आप सिर्फ उस अवस्था में नहीं रह सकते हैं।

सीएस: लेकिन मुझे लगता है कि उदार नारीवादी स्वयं को नवउदार एजेण्डे को आगे बढ़ाते हुए नहीं बल्कि अधिक लैंगिक समानता के लिए लड़ते हुए देखते हैं...

एनएफ: यहां सवाल है: समानता से हमारा तात्पर्य क्या है? समानता भी उन विवादास्पद अवधारणाओं में से एक है जिनकी प्रतिस्पर्धी व्याख्याएं हैं। इसकी उदार व्याख्या को मैं मेरिटोक्रैटिक व्याख्या कहूंगी। यह वह विचार है कि अंत में महिलाएं एक व्यक्ति हैं और उन्हें पुरुषों की तरह ही अवसर और मौके मिलने चाहिए कि वे व्यक्ति के रूप में वहां तक पहुंचें जहां तक उनकी प्रतिभा उन्हें ले जा सकती है। यहां समानता का अर्थ है उन अवरोधों को तोड़ने की कोशिश करना जो भेदभाव पैदा करते हैं; असमानता की समस्या भेदभाव की समस्या है और भेदभावपूर्ण बाधाओं को दूर करने से ये प्रतिभाशाली वैयक्तिक महिलाएं पुरुषों जितना ऊंचा जा सकती हैं।

पहली बात जो मैं कहना चाहती हूं कि यह एक वर्ग-विशिष्ट आदर्श है। इसका वास्तविक अर्थ है कि वे अपने वर्ग के स्पष्ट श्वेत पुरुषों के बराबर होना चाहती हैं। मेरे लिए नारीवाद का अर्थ समानता का एक अधिक पुष्ट और अतिवादी विचार है जो वास्तव में यौन पदानुक्रम को विविधता देने के बारे में नहीं बल्कि इसे समाप्त करने या किसी भी तरह से इसे कम करने के बारे में है। इसलिए मेरिटोक्रैटिक समानता के इस विचार को मैं वास्तव में समानता नहीं कहूंगी। समानता की व्याख्या के रूप में उदार मेरिटोक्रैसी ने कुछ वास्तविक लाभ अर्जित किये हैं लेकिन महिलाओं के सिर्फ एक सीमित स्तर के लिए। महिलाओं की अत्यधिक संख्या ग्लास सिलिंग को नहीं तोड़ती हैं; वे तहखानों में फंस जाती हैं, वे टूटे हुए कांच के टुकड़ों को साफ करने में संलग्न रहती हैं। मैं इस उदार, मेरिटोक्रैटिक नारीवाद के वैकल्पिक प्रकार के नारीवाद को विकसित करने के प्रयासों का हिस्सा हूं।

सीएस: संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप में कई दक्षिणपंथी नेताओं के निर्वाचन के बाद, इस प्रश्न पर बहस हुई है कि क्या दक्षिण पंथ सफलताओं के केन्द्र में आर्थिक असमानताओं की सम्बोधित करने की बजाय सामाजिक आंदोलनों में “पहचान” पर एक तरफा ध्यान हैं। नारीवादी आंदोलनों के लिए इस बहस का क्या अर्थ है जिसके सतह पर महिलाओं के रूप में हमारी साझा पहचान एक गतिशील कारक के रूप में है?

एनएफ: मुझे लगता है कि हमें इसे विभिन्न स्तरों पर संबोधित करना चाहिए। वैचारिक स्तर पर, मैंने हमेशा तर्क दिया है कि यह विचार कि कुछ आंदोलन पहचान के आंदोलन हैं और कुछ आंदोलन वर्ग आंदोलन हैं मिथ्याबोध है। वर्ग आधारित आंदोलनों के दो आयाम होते हैं। उनका एक संरचनात्मक पक्ष है जिसका मैंने वितरण के संदर्भ में सैद्धान्तिकरण किया है, लेकिन इसकी व्याख्या के अन्य तरीके हैं और उनमें हमेशा पहचान का पक्ष होता है कि सभी

वर्ग संघर्ष, चाहे वे स्पष्ट रूप से इस पर ध्यान केन्द्रित न करें, किसका संघर्ष है – लाभ या हानि आदि की छवि व्यक्त करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि नारीवाद इससे भिन्न है; पूंजीवादी समाजों में महिलाओं की अधीनता वर्ग शोषण के बराबर ही संरचनात्मक रूप से स्थापित है। इसलिए मुझे नाराजगी होती है जब लोग कहते हैं कि नारीवाद एक पहचान आंदोलन है और यह दूसरा वर्ग आंदोलन है। मुझे लगता है कि हमारे दावे भी उतनी ही संरचनात्मक रूप से गहन और जड़ हैं, जैसा वे कहते थे, जितने प्राथमिक विरोधाभासों में। उसके साथ ही, सभी आंदोलनों का पहचान का एक आधार होता है।

यद्यपि पहचान आधार आपको भटका सकता है। अब एक लोकप्रिय शब्द है, परस्परच्छेदन। मेरे पास उस शब्द की कुछ आलोचनाएं हैं लेकिन मुख्य बात सही है। मुख्य बात यह है कि सभी महिलाएं एक समान नहीं हैं, सभी कामगार-वर्ग के लोग भी समान नहीं हैं और न ही सभी वर्ग के लोग समान हैं। इनमें कुछ क्रास-कटिंग संरचनात्मक विषमताएं हैं; शक्ति, सुअवसर, प्रतिकूलता इत्यादि की विषमताएं हैं। एक नारीवाद जो कहता है “हम उन मुद्दों को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ महिलाओं की बात करेंगे” केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं के लिए ही बोलेगा। मुझे लगता है उदार, मेरिटोक्रेटिक नारीवाद ने यही किया है। नारीवाद को पूंजीवादी समाजों में उत्पीड़न के वर्ग, प्रजाति और सभी अन्य प्रमुख अक्षों के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील होना चाहिए।

सीएस: आपने स्वयं, अन्य कई प्रमुख नारीवादी विचारकों के साथ हाल ही में एक अधिक समावेशी नारीवादी आंदोलन बनाने के प्रश्न को संबोधित किया है और “99 प्रतिशत के लिए नारीवाद” के विचार को विकसित किया है। क्या आप हमें इस पहल के बारे में और बता सकती हैं?

एनएफ: यह एक प्रकार की लोकप्रिय भाषा है जिसे हमने आक्यूपाइ से उधार ली है। आप कह सकती हैं कि स्पष्ट समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह पूर्णरूप से परिशुद्ध नहीं है लेकिन इसमें जबरदस्त गतिशील शक्ति है और यह तुरंत प्रेषित करती है कि यह क्रिस्टिन लागार्ड और हिलेरी रोडम क्लिंटन का नारीवाद नहीं है। यह क्रेक द ग्लास सीलिंग, नारीवाद की तरफ झुकाव के खिलाफ होने के रूप में स्वयं को वर्णित करने का लगभग “युद्ध करने वाले शब्द” का एक तरीका है। यह मार्ग सुधारने का एक स्पष्ट प्रयास है। जैसा कि मैंने उस निबन्ध में निदानित किया कि हाल ही के दशकों में जो हुआ वह था कि नारीवाद या नारीवाद की महत्वपूर्ण प्रभावी धाराओं को किसी तरह एक गठबंधन में खींच लिया गया था जैसा हेस्टर एडसेनस्टीन ने कहा, इस तरह की नवउदार ताकतों के साथ “खतरनाक संपर्क” और यह उनके लिए एक बहाने के रूप में कार्य कर रहा था। इसलिए, नवउदार ताकतें जो 1% का प्रतिनिधित्व करती हैं का प्रतिवाद 99% का प्रतिनिधित्व करने वाला नारीवाद है। यह बहुत ही सरल आलंकारिक रणनीति है। इसके बारे में सोचक बात और हम में से कुछ ही थे जिन्होंने इसका सपना देखा था, यह थी कि यह वास्तव में लग गई और इसको कुछ खिंचाव मिला। यह मुझे दर्शाता है कि वहां कुछ ऐसा था जो इस तरह के कुछ के आने का इंतजार कर रहा था। इसके लिए एक वास्तव में आवश्यकता महसूस हो रही थी।

99% के लिये नारीवाद वास्तव में उन महिलाओं की भारी संख्या की

स्थिति से चिंतित था जो सामाजिक प्रजनन और मजदूरी कार्य के बड़े हिस्से में संलग्न हैं और नवउदार, वित्तीय पूंजीवाद के इस शासन के तहत जिनकी जीवन स्थितियां बिगड़ रही हैं। पूंजीवाद के इस प्रकार को पूर्व के पूंजीवाद की तुलना में प्रति परिवार अधिक घंटों के वैतनिक कार्य की आवश्यकता होती है। यह राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक कल्याण और सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर हमला कर रहा है और ऋण को एक हथियार के रूप में प्रयोग में लेता है। सामाजिक प्रजनन पर इस हमले की अग्रिम पंक्ति में महिलाएं हैं और नारीवादी 99% इन पक्षों पर फोकस करते हैं और वास्तव में उन्हें पूंजीवाद के इस रूप की समस्या के रूप में बांध रहे हैं। हम इस व्यवस्था के नामकरण का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि हम एसडीएम (स्टूडेंट्स फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी) में कहते थे, और जहां उदार नारीवाद व्यवस्था तक पहुंच विकसित करने के संबंध में है, हम उन तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें व्यवस्था हमारे जीवन को जीने के अयोग्य बना रही है।

सीएस: लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका में 53% श्वेत महिलाओं ने 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प के लिए मतदान किया, एक ऐसा उम्मीदवार जो न केवल खुले तौर पर यौनवादी है बल्कि जो खुद को किसी भी प्रकार के लैंगिक समानता से संलग्न नहीं करता है। 99% के लिए नारीवाद का विचार क्या इन महिलाओं तक पहुंच सकता है?

एनएफ: सब नहीं, लेकिन मुझे लगता है उनमें से एक बड़ा हिस्सा। बेशक, कुछ उन पुरुषों की तरह हैं जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया, वे रिपब्लिकन हैं जो हिलेरी क्लिंटन से नफरत करते हैं और उनको कभी भी वोट नहीं देंगे, व्यवसायी जो मुक्त बाजार चाहते हैं इत्यादि। उनमें से बहुत सारे बहुधा संदिग्ध हैं जो रिपब्लिकन को वोट करते हैं लेकिन सब नहीं। उनमें से कुछ श्रमिक महिलाएं उन वि-औद्योगीकरण क्षेत्रों से हैं जो संयुक्त राज्य अमरीका के बाहर विनिर्माण के स्थानांतरण से पूर्ण रूप से तबाह हो गये हैं और उनमें से कुछ दक्षिणी महिलाएं हैं। दक्षिण में एक नया औद्योगीकरण था जो अक्सर गैर-संघीय था, वह भी हाल के वर्षों में तबाह हो गया। वे भी बुरी तरह से हार गये। ग्रामीण महिलाएं भी हैं, छोटे शहरों की महिलाएं जहां बेरोजगारी भयानक है, अफीम की तल फैली हुई है और इस तरह और आगे भी। आशय यह है कि ये वे लोग नहीं हैं जो नारीवाद झुकाव या प्रगतिशील नवउदारवाद के किसी संस्करण से लाभान्वित होने वाले हैं।

उन्होंने क्यों ऐसे वोट दिया जैसे उन्होंने किया के बारे में अभी तक गंभीर परिशुद्ध और नृजातीय अध्ययन नहीं हुए हैं लेकिन ऐसे होंगे। कुछ साक्षात्कार, जिन्हें मैंने देखा है और यह व्यवस्थित नहीं है – से आप जान सकते हैं कि लोग क्या महसूस करते हैं। जब उन्होंने हॉलीवुड एक्सेस टेप (जो चुनाव के ठीक पहले हुआ जब ट्रम्प महिलाओं को यौन अंग से पकड़ने के बारे में डींग हॉक रहा था) को सुना, इस तरह की चीजों से उन्हें बुरा लगता था, उन्हें यह पसंद नहीं था, यह अपमानजनक था और वे नहीं चाहते थे कि वो इस तरह बात करे, लेकिन बाकी सब कुछ देखते हुए, वह अभी उनके लिए सही था। इसके साथ, मुझे लगता है ऐसे भी लोग हैं जो उनके मेक्सिकन या मुस्लिम के बारे में बात करने के तरीकों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन भले ही वह उन लोगों के प्रति इस हद तक बदतहजीब था, तदपि वह उनके लिए चीजों को बेहतर करने के बारे में बात कर रहा था।

बेशक, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि सभी ट्रम्प समर्थक नस्लवादी हैं। ऐसे ट्रम्प मतदाता हैं जो वास्तव में नस्लवादी हैं, लेकिन जिन तक हम नहीं पहुंच सकते हैं और मैं उनके बारे में चिंतित नहीं हूँ। मैं उन लोगों के बारे में चिंतित हूँ — और मुझे लगता है कि उनका एक बड़ा हिस्सा है — जिसे वामपंथ द्वारा पहुंचा जा सकता है। हम जानते हैं कि 2016 में 8.5 मिलियन अमेरिकियों ने ट्रम्प को वोट दिया जिन्होंने 2012 में ओबामा को वोट दिया था।

सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है कि नवम्बर के चुनाव आने के समय तक, एकमात्र विकल्प हिलेरी क्लिंटन थीं और इसका अर्थ प्रगतिशील नवउदारवाद था। बर्नी सैंडर्स ने किसी और का प्रतिनिधित्व किया था लेकिन वे उस समय खेल से बाहर थे।

सीएस: तो आप क्या सोचती हैं कि इन 8.5 मिलियन अमेरिकियों तक वामपंथ कैसे पहुंच सकता है?

एनएफ: जिस राजनीति का मैं समर्थन कर रही हूँ, जिसका 99% के लिए नारीवाद एक भाग है, वह सैंडर्स के विकल्प जैसे को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना है (मैं उनका नाम केवल शार्टहैण्ड के लिए काम में ले रही हूँ)। इसमें प्रत्येक प्रगतिशील सामाजिक आंदोलन को, वे जो 99% के लिए हैं और वे जो 1% के लिए हैं में बांटना सम्मिलित है — निस्संदेह यह भौंडा है लेकिन विचार स्पष्ट होना चाहिए — और सबको एक साथ रखना चाहिए। सैंडर्स के साथ आपके पास वह विचार था कि आप बहुत से कामगार

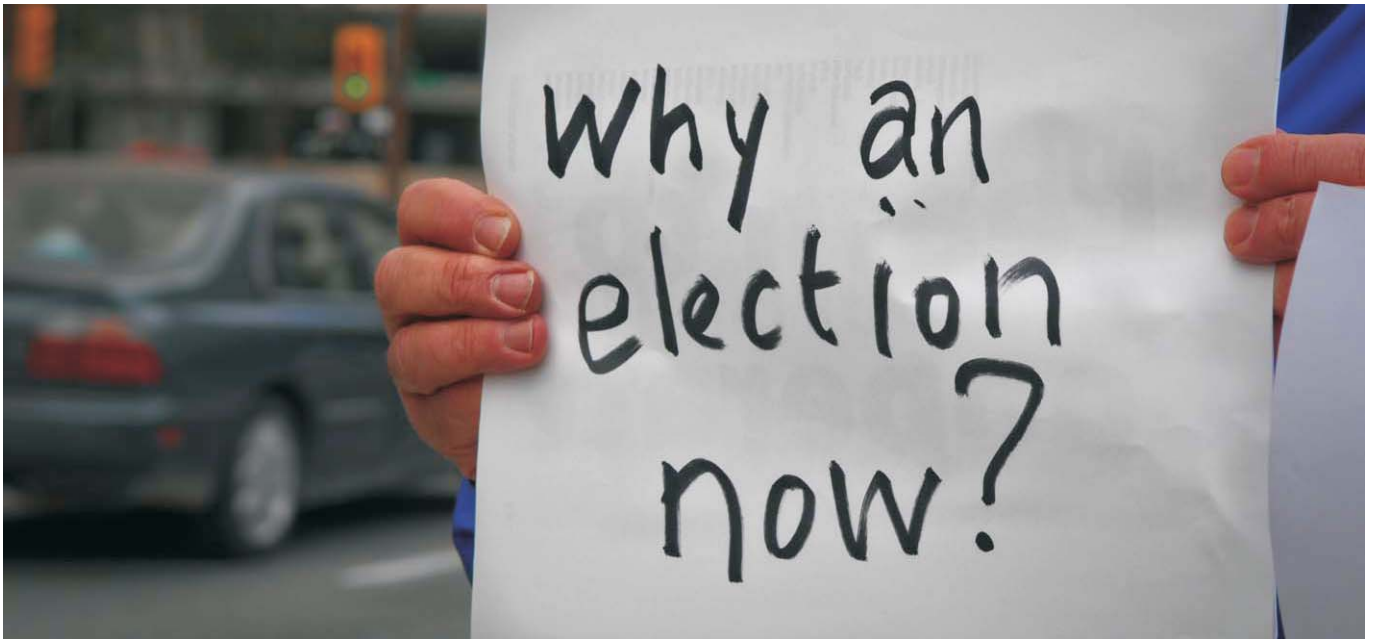
वर्ग समर्थक और कामगार परिवार समर्थक, जीविकोपार्जन के मुद्दों: जिनमें अन्य के मध्य सभी के लिए मेडिकेयर, बैंकों को तोड़ना और निःशुल्क कॉलेज की पढ़ाई को मिला सकते हैं।

जब मैं कामगार वर्ग कहती हूँ, मेरा मतलब सिर्फ श्वेत लोग नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका में कामगार वर्ग में कई वर्ग के लोग और महिलाएं हैं और वे स्वयं को अधिकाधिक कामगार वर्ग के रूप में सोचते हैं। तो 99% को लाभान्वित करने वाले जीविकोपार्जन के मुद्दों को लो और उन्हें आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार जैसी चीजों के साथ जोड़ दो जो कि वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्रजनन स्वतन्त्रता के साथ जो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, और अन्य मुद्दे जो समान रूप से संरचनात्मक और भौतिक हैं, जो कि यद्यपि जिन्हें होना नहीं चाहिए — पहचान के मुद्दों के रूप में सोचे जाते हैं। इसलिए मुझ लगता है 99% के लिए नारीवाद एक ऐसा उदाहरण है जिसका अन्य आंदोलन अनुकरण कर सकते हैं। अतः उदाहरण के लिए चलो हमें 99% के लिए पर्यावरणवाद चाहिए। हमारे पास ये धाराएं हैं लेकिन हमें वाकई में बुलाना चाहिए और एक स्पष्ट तरीके से उन्हें एक साथ रखना चाहिए। ■

सभी पत्राचार नैन्सी फ्रेजर को <frasern@earthlink.net> पर प्रेषित करें।

> लोकतंत्र का संकट

हैके ब्रंकहोस्ट, फ्लेंसबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी द्वारा



9

लोकतंत्र संकट में है इसका आज के समाज विज्ञान में व्यापक विश्लेषण किया जाता है। फिलकर/इत्जा फाइन दिवस। कुछ अधिकार सुरक्षित।

एक शताब्दी के भयंकर, खूनी और क्रूर वर्ग संघर्ष, वैश्विक गृह युद्ध और विश्व क्रांतियों के बाद पूंजीवादी राज्य विश्वव्यापी-निर्मित (उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 23 से 26, जर्मन मूल कानून), लोकतांत्रिक एवं सामाजिक राज्य (अनुच्छेद 20 और 28, जर्मन मूल कानून) बन गया है। वैश्विक उत्तर में न्याय एक 'मौजूदा अवधारणा' बन गया है (हीगल)।

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में फैली सम्पत्ति के अनगिनित विशिष्ट रूपों में खण्डन के साथ उत्पादन के सम्बन्ध आंशिक रूप से समाजीकृत हो गये। पूंजीपति और श्रमिक अपनी छुट्टियां एक ही समुद्र तटीय रिसोर्ट पर बिता रहे हैं। पहला समुद्र के दृश्य के साथ और और दूसरा सड़क के दृश्य के साथ। लेकिन उन्हें एक ही पानी में तैरना, उन्हीं समुद्रतटों पर खेलना और अपने बच्चों को — यह मामलों की मुख्य बात हैं — समान सार्वजनिक विद्यालय में भेजना पड़ता है। श्रमिक छोटी कार चलाता है, बॉस बड़ी कार चलाता है, लेकिन दोनों ही समान रूप से ट्रेफिक जाम में फंसे हैं, चूंकि अभी तक धनी के लिए हेलीपैड वाली कोई गगनचुंबी इमारतें नहीं हैं — न ही निर्धन के लिए पर्याप्त अग्नि सुरक्षा के बिना ऊंची इमारतें।

तथापि वैश्विक उत्तर की समृद्धि दक्षिण के विनाश की उच्च लागत से आई है। राष्ट्रीय स्तर पर सीमित कल्याणकारी राज्य श्वेत, नर और विषमलिंगी थे। कोई भी मौजूदा न्याय बिना 'मौजूदा विरोधाभास' के नहीं (हीगल)। लोकतंत्र — और यह सब जगह हुआ — रंग और लैंगिक रेखा पर आ कर खत्म हुआ। 1960 के दशक से नये सामाजिक आंदोलनों ने बारम्बार इसके खिलाफ प्रतिरोध करके मानवाधिकार, अश्वेत के लिए नागरिक अधिकार, महिला मुक्ति, अक्षम अधिकार, यौन पर्यावरण संरक्षण और एक विश्वव्यापी संस्कृति में वृद्धि करने में सफलता प्राप्त की है। मई 1968 में जब छात्र और कामगारों ने ताकत मिला ली, तब आधुनिक पूंजीवाद की कलात्मक आलोचना एवं सामाजिक आलोचना के एकीकरण (बोल्तान्सकी) का स्वपन आखिर में साकार होता प्रतीत हुआ। असंभव की मांग करना यथार्थवादी बन गया। यद्यपि इसके बाद जो आई वह आर्थिक मंदी थी जिसने राजनैतिक दक्षिणपंथ को ऑफिस में पहुंचाया।

> राज्य सन्निहित बाजार से बाजार सन्निहित राज्य की ओर

चिली (1973) और अर्जन्टीना (1976) में खूनी तख्तापलट, जो

>>

पश्चिम द्वारा उदारता से समर्थित थे, प्रयोगात्मक पार थे जबकि ग्रेट ब्रिटेन (1979) और संयुक्त राज्य अमेरिका (1981) में नवरूढ़िवादी चुनावी जीत ने नौकरशाही समाजवाद के आत्म-विनाश का मार्ग प्रशस्त किया (1989) और अंततः नवउदार वैश्वीकरण की राह में अंतिम बाधा को भी हटाया। कुछ ही वर्षों के दौरान, राज्य सन्निहित बाजार, बाजार सन्निहित राज्य बन गये। सार्वजनिक कानून को निजी कानून के अधीन अंतराष्ट्रीय शासन की विशाल (और बढ़ते) संख्या द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो विशेष रूप से साम्राज्य में शासक वर्गों के हितों को समन्वयित करने के उद्देश्य से कार्य करता है, जैसा कि पूर्व रोमन नागरिक कानून के मामले में था। कानूनी औपचारिकता जो हमें अनौपचारिक शासन से मुक्त करती है को एक अत्यधिक गतिशील अनौपचारिक कानून द्वारा पूरक किया गया जिसने औपचारिक सांविधिक कानून और अनौपचारिक निपटान कानून के नये 'दोहरे राज्य' (फ्रेंकल) की रूपरेखा को दर्शाया।

इसका एक प्रतिमानात्मक उदाहरण यूरो ग्रुप था। 2015 के संकट के चरम पर इस निकाय से निष्कासन के बाद ग्रीक वित्त मंत्री ने इस निर्णय के विधिक औचित्य के बारे में पूछा। यूरो ग्रुप के अध्यक्ष ने अपने वकीलों को यह बताने के लिए बुलवाया कि समूह के पास कोई प्रक्रियात्मक मानदण्ड नहीं था चूंकि यह अनिवार्य रूप से विधिक शर्तों में गैर मौजूद था और इसके सदस्य हत्या करने के अलावा अन्य जो कुछ भी चाहते थे कर सकते थे।

हस्तक्षेप करने की राज्य की आर्थिक शक्ति बाजार अनुकूलता से बाधित होती है जबकि इसकी संगठनात्मक शक्ति और पुलिस बल बरकरार रहते हैं ताकि वे 'फ्रैक्टी के रखरखाव दल' की भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें जिससे अपनी शक्ति में दृढ़ता से अंतःस्थापित रहने के साथ 'समग्र बाजार व्यवस्था' की निरन्तरता को सुनिश्चित किया जा सके (हायेक)। विश्व बाजार में अंतःस्थापित होना सुनिश्चित करता है कि निवेशक अपनी इच्छा के देश को स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं जबकि बदले में राज्य अपने निवेशकों को चुन नहीं सकते हैं और इस प्रकार वे आकर्षक उत्पादन स्थितियों को प्राप्त करने की अंधाधुंध दौड़ में भाग लेने के लिए मजबूर होते हैं। परिणामस्वरूप, वर्गों, राष्ट्रों राष्ट्रीयताओं, और पीढ़ियों के मध्य सामाजिक अंतर बड़ी ऊँचाइयों तक धकेले जाते हैं।

फुटबॉल का खेल कई तरह से वैश्विक समाज का प्रतिबिंब है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के पेशेवर खिलाड़ी यदि 1985 में उनके साधारण प्रशंसकों की तुलना में लगभग दुगुना कमाते थे, आज वे 200 गुणा अधिक कमाते हैं। खिलाड़ियों की आय में वृद्धि के साथ टिकट कीमतों में वृद्धि हुई। लम्बे समय से फुटबॉल प्रशंसकों जो साथ बनाये रखने में असमर्थ थे, ने इस्तीफा दे दिया और दूरी बनायी और स्टेण्ड्स उन लोगों से भर गये जिनके पास अधिक धन था। यही चित्र स्टेडियम के बाहर भी देखा जा सकता है: खराब पड़ोस, नये समाज में प्रवेश लेने में असमर्थ, राजनैतिक उदासीनता, शराब और नशीली दवाओं से सम्बन्धित वेश्यावृत्ति में लिप्त है। चुनावी मतदान 30 प्रतिशत से कम है जबकि यह शहर के सम्पन्न इलाकों में 60 प्रतिशत से ऊपर रहता है, अतः यह धनाढ्यों के प्रगति पर अग्रसर होने के भ्रम को पोषित करता है। और यहां तक कि यदि प्रगति, जैसा कि प्रारम्भ में प्रतीत होती थी से काफी कम होती है, फिर भी लोगों के पास एक मोटा बटुआ रह जाता है। स्वाभाविक है कि वामपंथी दल जो लगातार मतदाता खो रहे हैं, प्रत्येक चुनाव के

साथ और अधिक दक्षिण पंथ की तरफ बढ़ते हैं — जैसा कि उद्विकास की अनंत प्रतिद्वंद्विता में आधारित बाजार व्यवस्था में अपेक्षा की जाती है।

> सामाजिक असमानता राजनैतिक असमानता पैदा करती है

मुख्य नारीवादी और बहुसांस्कृतिक उपलब्धियां जिन्होंने दशकों पुराने प्रभुत्व सम्बन्धों को नष्ट किया था अपने 'उचित मूल्य' को खो रहे हैं (रॉल्स)। बेरोजगार, यहूदी, समलैंगिक स्त्रियां और पूर्व में अपराधी अश्वेत महिलाएं अपनी पैदाइशी बस्ती के 'रक्त सम्बन्धों' (माक्स) को अब पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। अपनी बस्ती में वे सभी प्रकार के कल्पनीय यहूदी-विरोधी, समलैंगिक और नारी-द्वेषी पूर्वाग्रहों से उसी हद तक असुरक्षित होती है जितना वह पुलिस और पुरुषों के गिरोह से सेक्सवाद और हिंसा से होती है।

यदि चुनावी अभियान नवउदार बाजार अर्थव्यवस्था को राजनैतिक विकल्प देने की बजाय विश्व बाजार को समायोजन के विशिष्ट सूक्ष्म-आर्थिक रणनीतियों के आधार पर केवल तकनीकी विकल्प ही उपलब्ध कराते हैं तो लोकतंत्र का अस्तित्व खत्म हो जायेगा।

शॉपिंग मॉल का यह 'चमकदार दुख' (कान्त) लीबियाई मरुस्थल, समुद्र और हमारी दक्षिणी सीमा से लगते हुए शिविरों में अपना भयानक बेचमकदार चेहरा दिखाता है। यूनानी द्वीप लेस्बोस के पूर्व मोरिया शरणार्थी शिविर, अब एक निर्वासन केन्द्र में परिवर्तित, में यूरोपीय संघ उसकी बलि चढ़ा रहा है जिसके लिए वह कभी तथाकथित रूप से पक्ष में था। 'आजादी, सुरक्षा और न्याय का क्षेत्र' (अनुच्छेद 4, यूरोपीय संघ की कार्यप्रणाली पर संधि, अब से टीएफइयू) 'मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में' (अनुच्छेद 67 टीएफइयू), 'शरण के अधिकार' को अंतराष्ट्रीय स्तर पर गारंटी देते हुए (अनुच्छेद 18, इयू के मौलिक अधिकारों का चार्टर) और 'गैर सुधार के सिद्धान्त की अनुपालना' (अनुच्छेद 78, टीएफइयू) जिसमें 'नस्लवाद और जेनोफोबिया' से बचाव और मुकाबला किया जाता है (अनुच्छेद 67, टीएफइयू) लेस्बोस के भयावह रूप से मैले, चिकित्सीय रूप से कम आपूर्ति वाले और अति संकुलित मोरिया शिविर में तीन भिन्न सीमाओं के माध्यम से मूर्त कानून में परिवर्तित होते हैं : पहली, ईंट की दीवार की बाउण्ड्री के भीतर हिरासत शिविर स्थित है जिसमें आश्रय चाहने वाले अस्वीकृत और नवागुन्तक अवैध प्रवासी जिन्हें निर्वासित करने का अनुमोदन किया गया है, रहते हैं। कंट्रीलें तारों, चौकीदार टॉवर और सशस्त्र गार्ड से निर्मित यह बाउण्ड्री मध्य में स्थित हिरासत शिविर वाले शरणार्थी आवास परिसर को चारों तरफ से घेरती है। तीसरी सीमा समुद्र और वह द्वीप है जिसे छोड़ने की अनुमति किसी को नहीं है। समुद्र का गुण, जो हमारे बाजारों की प्रकृति की रक्षा करता है, के कारण सीमा प्राकृतिक कानून का एक तत्व बन जाती है। जिसका भी आगमन होता है, उसे हिरासत में लिया जाता है मानों भागना एक अपराध हो। जैसा कि कैरोलिन वियडेमैन कहती हैं : "मोरिया जैसे स्थान पूरे इयू में योजनाबद्ध हैं। उन्हें तथाकथित रूप से 'नियन्त्रित केन्द्र' (जर्मन में कन्ट्रोलियरते जेटरेन) कहा जाता है। कोई यह अनुमान नहीं लगाना चाहेगा कि इस शीर्षक का लघु रूप (जर्मन) क्या होगा।"

सभी पत्राचार हौके ब्रंकहोर्स्ट को brunkhorst@uni-flensburg.de पर प्रेषित करें।

> सत्तावादी लोकतंत्र का उदय

क्रिश्चियन फूक्स, वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम द्वारा

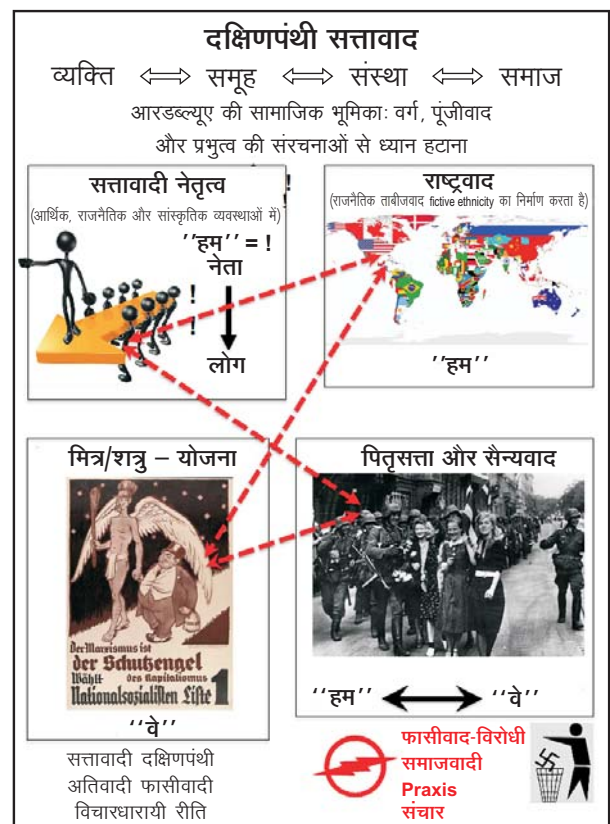
हाल ही के वर्षों में कट्टर दक्षिणपंथी राजनीति विस्तारित हुई और इसने अपनी ताकत को समेकित किया है। संयुक्त राज्य अमरीका में डोनाल्ड ट्रम्प (रिपब्लिकन पार्टी), हंगरी में विक्टर ऑर्बान (फिड्सज), हेनज-क्रिश्चियन स्टैच (फ्रीडम पार्टी), नीदरलैंड में गीर्ट विल्डर्स (पार्टी फॉर फ्रीडम), भारत में नरेन्द्र मोदी (भारतीय जनता पार्टी), तुर्की में रसेप तय्यिप एर्दोगान (एकेपी), द आल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, पोलैंड में जरोस्लो कासिन्सकी (विधि एवं न्याय), फ्रांस में मरीन ली पेन (पूर्व में राष्ट्रीय फ्रंट), इटली में लेगा नॉर्ड, रूस ब्लादिमिर पुतिन (अखिल रूस पीपुल्स फ्रंट) इत्यादि हैं। इस घटनाक्रम का किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ रूप से चरित्र चित्रण कर सकते हैं? इस कार्य के लिए कौन सी समाजशास्त्रीय श्रेणियां सबसे उपयुक्त हैं?

एक प्रमुख सुझाव यह है कि लोकप्रियता की धारणा को प्रयोग में लेना चाहिए। जेन वर्नर मुलेर (2017) ने हाल ही में अपनी पुस्तक व्हाट इज पोपुलिज्म? में इस प्रस्ताव को दोहराया है। इस पुस्तक में उन्होंने लोकप्रियता को 'राजनीति की एक विशिष्ट नैतिकवादी कल्पना, राजनैतिक दुनिया को समझने का एक तरीका जो नैतिक रूप से शुद्ध और पूर्णतया एकीकृत (...) लोगों को ऐसे कुलीन लोग, जो भ्रष्ट माने जाते हैं या किसी और तरीके से नैतिक रूप से कमतर हैं, के विरुद्ध रखता है। (...) लोकप्रिय लोग हमेशा बहुलता विरोधी होते हैं : जनवादी दावा करते हैं कि वे, और केवल वे, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।' वे यह भी नोट करते हैं कि लोकप्रियता 'पहचान की राजनीति का एक अपवर्जी स्वरूप है' जो 'लोकतंत्र के लिये खतरा' पैदा करता है और जिसका उद्देश्य 'नागरिक समाज को दबाना' है।

इस तरह का दृष्टिकोण वामपंथी सिरिजा एवो मोरालेस, पॉडेमोस, या बर्नी सैंडर्स और दक्षिणपंथी डोनाल्ड ट्रम्प, गीर्ट विल्डर्स या मरीन ली पेन के लिए एक समान श्रेणी को काम में लेता है। उसका परिणाम है कि सर्वसत्तावाद के सिद्धान्त की तरह, कट्टरपंथी दक्षिण पंथ की तुलना वामपंथ से की जाती है और इस तरह पहले के खतरों को हल्के में लिया जाता है। चूंकि मुल्लेर के लिए डोनाल्ड ट्रम्प और बर्नी सैंडर्स दोनों लोकप्रिय हैं। बर्नी सैंडर्स निश्चित तौर पर अपरंपरागत राजनेता हैं लेकिन ट्रम्प की तुलना में उनके लोकतांत्रिक अभिविन्यास के बारे में कोई संदेह नहीं है।

कैपिटलिज्म इन द एज ऑफ ट्रम्प एण्ड ट्रिवटर' में प्रयोग में लिया दृष्टिकोण भिन्न है और यह विवेचनात्मक राजनैतिक अर्थव्यवस्था, विचारधारायी आलोचना और विवेचनात्मक मनोविज्ञान का सम्मिश्रण करता है। दक्षिणपंथी सत्तावाद (आरडब्ल्यूए) चार तत्वों को व्यक्त करता है (चित्र 1 देखें) : शीर्ष-नीचे नेतृत्व की आवश्यकता में विश्वास; राष्ट्रवाद; दोस्त/दुश्मन योजना; और आक्रामक पितृसत्ता (कानून एवं व्यवस्था नीतियां; युद्ध एवं सैनिकों का आदर्शिकरण; निर्मित शत्रुओं का दमन; रुढ़िवादी लैंगिक सम्बन्ध)। आरडब्ल्यूए वर्ग संरचना और पूंजीवाद की सामाजिक समस्याओं की नींव और कारणों में भूमिका से ध्यान हटाने का विचारधारायी उद्देश्य पूरा करता है। शरणार्थी, अप्रवासी, विकासशील राष्ट्र, मुसलमान इत्यादि को बलि के बकरे के रूप में निर्मित किया जाता है और उन्हें बेरोजगारी, कम मजदूरी, आर्थिक

चित्र 1 : दक्षिणपंथी सत्तावाद का एक मॉडल



2018 की मेरी पुस्तक 'डिजिटल डेमागोग : अथोरिटेरियन

स्रोत : सी फूक्स, 2018

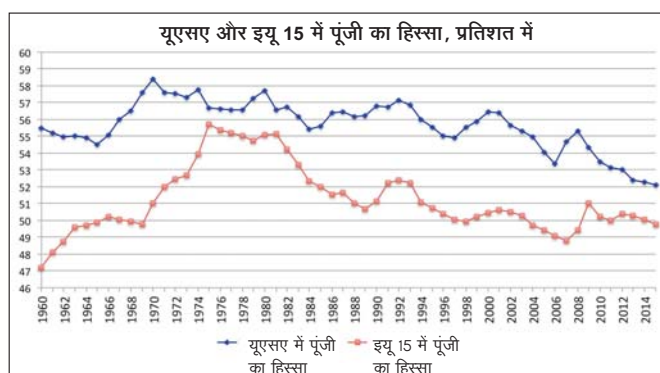
उहराव, सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट, आवासीय संकट जैसी समस्याओं के लिए दोषारोपित किया जाता है। ट्रम्प विऔद्योगीकरण एवं सामाजिक गिरावट के लिए मैक्सिको और चीन को दोषारोपित करते हैं बगैर यह कहे कि अमरीकी पूंजी यूएस एवं पूंजी के आउटसोर्स के गंतव्यों, जिसमें चीनी मजदूर गृह और मेक्सिकन मेक्वीलाडोरास सम्मिलित हैं, दोनों में कामगारों का शोषण करती है।

आरडब्ल्यूए न तो चेतना का न ही संरचना का और न ही समाज का एक प्रकार है। यह एक प्रक्रिया है जो समाज के विभिन्न स्तरों पर हो सकती है : वैयक्तिक (सत्तावादी व्यक्तित्व संरचना, चेतना, व्यक्तिगत राजनैतिक व्यवहार), राजनैतिक समूह एवं आंदोलन, विचारधारा, संस्थाएं, सकलता में समाज। दक्षिणपंथी चरमपंथ और फांसीवाद आरडब्ल्यूए का तीव्रीकरण हैं जो राजनैतिक साधनों के रूप में शारीरिक हिंसा और आतंक को सहन करने या सक्रिय रूप से उसका अनुसरण करते हैं।

आरडब्ल्यूए के उदय की सांस्कृतिक व्याख्या का दावा है कि 'उत्तर भौतिकवादी' समाज के उभार ने पीढ़ी गत अन्तर को निर्मित किया है जिसमें पुरानी पीढ़ी रूढ़िवादी मूल्य को पकड़ कर रखती है और अतीत की हानि के बारे में विलाप करती है। लेकिन उदाहरण के लिए, उत्तर-भौतिकवादी प्राकल्पना इसकी व्याख्या नहीं कर सकती है कि 2017 के ऑस्ट्रियाई संघीय चुनाव में कैसे कट्टर दक्षिणपंथ 16-29 आयु वर्ग (30%) में सबसे ताकतवर पार्टी थी लेकिन 60+ आयु वर्ग में वह केवल तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी।

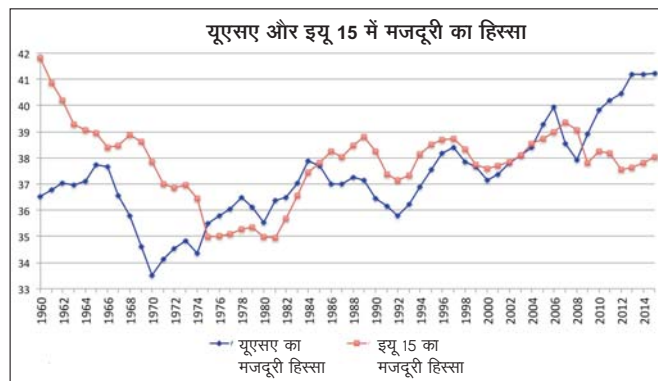
एक वैकल्पिक व्याख्या राजनैतिक अर्थव्यवस्था को गंभीरता से लेती है। इस उद्देश्य के लिए, विवेचनात्मक राजनैतिक विचारक

चित्र 2 : समय के साथ यूएसए और इयू की जीडीपी में मजदूरी का हिस्सा



स्रोत : एएमइसीओ

चित्र 3 : समय के साथ यूएसए और इयू की जीडीपी में पूंजी का हिस्सा



स्रोत : एएमइसीओ

फ्रांज.एल. न्यूमैन का 1957 का लेख *एन्कजाइटी एण्ड पोलिटिक्स* में प्रयुक्त दृष्टिकोण काफी सहायक है। इस व्याख्या के अनुसार दक्षिणपंथी सत्तावाद का उदय श्रम के अलगाव (चित्र 2 और 3 देखें); विनाशकारी प्रतिस्पर्धा; सामाजिक पतन का डर पैदा करने वाला सामाजिक अलगाव; राजनैतिक व्यवस्था, राजनेता और राजनैतिक दलों से राजनैतिक अलगाव; और कट्टर दक्षिणपंथी समूहों द्वारा चिंता का संस्थाकरण जो डर को भड़काता है और बलि का बकरा बनाने की राजनीति को अग्रेषित करता है, से जुड़ा है।

सत्तावादी पूंजीवाद नवउदारवादी पूंजीवाद के नकारात्मक द्वन्द्व का परिणाम है। बाजार की स्वतन्त्रता और सामाजिक स्वतन्त्रता के मध्य विरोधाभास का परिणाम असमानताओं और संकट में वृद्धि था जो 2008 के क्रेश के बाद एक नई गुणवत्ता में बदल गया। सामाजिक लोकतंत्र का बुर्जुआकरण और नवउदारकरण, वामपंथ की कमजोरी, और वर्ग राजनीति एवं वर्ग विश्लेषण के महत्व को कमतर आंकने वाली उत्तर-आधुनिक पहचान की राजनीति ने कट्टर दक्षिणपंथी और सत्तावादी पूंजीवाद के उभार को बढ़ाया है। नवउदार पूंजीवाद का परिणाम अलगाव का सार्वभौमिकरण है। जैसा कि हार्वे, हार्डट और नेग्री के साथ मैंने भी कहीं अन्य यह तर्क दिया है कि नवउदारवाद ने लगभग सबका ही वस्तुकरण किया है ताकि हमने पूंजी के तहत बेदखली ओर समाज के वास्तविक धारणा द्वारा चल रहे आदिम संचय को अनुभव किया है। डेविड हार्वे के शब्दों में : 'व्यापक रूप से फैले अलगाव के फलस्वरूप कब्जा करो आंदोलन के साथ दक्षिणपंथी लोकप्रियता और धर्मांध राष्ट्रीय एवं नस्लवादी आंदोलन भी उभरे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प अलगाव के राष्ट्रपति हैं।' ■

सभी पत्रचार <christian.fuchs@triple-c.at> पर प्रेषित करें।

> अवैध नागरिकता के रूप में नृवंशीय नागरिकता

एंड्रिया सिल्वा-तापिया, हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन और जस्टिस लिबिग गिसेन विश्वविद्यालय जर्मनी द्वारा

> एक स्थायी/स्थिर औपनिवेशिक विश्व में नागरिकता और राष्ट्र-राज्य का निर्माण

एक अवधारणा के रूप में नागरिकता एक अस्पष्ट अवधारणा (संदिग्ध शब्द) है और इसके अर्थ पर व्यापक बहस की जा सकती है। कुछ लोगों के लिए यह अवधारणा राष्ट्रीयता या संबंधित देश द्वारा दी गई पूर्णतः कानूनी प्रस्थिति को व्यक्त करती है, जबकि अन्य लोगों के लिए यह उनकी पहचान की व्यक्त करती है। विभिन्न परिभाषाओं और विभिन्न विचारकों जैसे टी.एच. मार्शल, मार्गरेट सोमर्स, टी.के. ओमेन, एनजिन एफ. इस्न और पेटीसिया के. वुड ने नागरिकता को एक राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र की सदस्यता के आधुनिक स्वरूप के रूप में वर्णित किया है। इसलिए, नागरिकता की अवधारणा एक राष्ट्र-राज्य से वैधानिक और प्रतीकात्मक सम्बद्धता को व्यक्त करती है। यह एक सरल परिभाषा प्रतीत होती है लेकिन जब हम ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार करते हैं जिसमें नागरिकता की अवधारणा उभरती है, तो यह परिभाषा अधिक जटिल हो जाती है।

अपने आधुनिक स्वरूप में नागरिकता राष्ट्र-राज्य की उत्पत्ति के साथ-साथ विकसित हुई। नागरिकता एक ऐसी अवधारणा है जो एक ही समय में आधुनिकता, राष्ट्र-राज्य निर्माण और सम्बद्धता की भावना से संबंधित है। राष्ट्र-राज्य का विचार, जो फ्रांसीसी एवं अमेरिकी क्रांति तथा औपनिवेशिक राज्यों की आजादी में अभिव्यक्त हुआ था, को पुनः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखा जा सकता है जो उसी राष्ट्र-राज्य निर्माण के प्रारूप का अनुकरण करता है। एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में परिभाषित किया गया, जिसके पास एक लिखित संविधान था और जो समान नागरिकता के नाम पर शासन करता है। अतः वैधता के सिद्धांत राजशाही (या दिव्य अधिकार) से समान नागरिकता का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्र में बदल गए। हालांकि, नागरिकता और राष्ट्र-राज्य की ये अवधारणाएं राष्ट्र-राज्य निर्माण की एकल (यूरोकेंद्रित) विधि पर आधारित हैं, जहां उपनिवेशवाद दृढ़ता से संचालित हुआ था और अभी भी संचालित होता है।

अवैध नागरिकता हमारी वर्तमान पितृसत्तात्मक, यूरोकेंद्रित और ईसाई केंद्रित विश्व-व्यवस्था में औपनिवेशिक नागरिकता को सम्मिलित करने का एक और तरीका है। यह औपनिवेशिक विश्व-व्यवस्था वैश्विक नृवंशीय/प्रजातीय संस्तरण के माध्यम से संचालित होती है, जो निर्धारित करती है कि कौन से समूह प्रतिष्ठा के पात्र हैं और कौन से नहीं हैं। अंजा वीस का तर्क है कि हम प्रजातिवाद के बारे में यह कह सकते हैं कि 'जब एक दीर्घकालिक और स्थिर संकेतक कथित तौर पर भिन्नता दिखाने का दिखावा करता है और सामाजिक विभाजन, गतिविधियों और संस्थानों पर इस तरह से प्रभाव डालता है कि उस श्रेणी के लोगों को कम अधिकार प्राप्त है, भले ही यह संकेतक जैविक या अन्य प्रकार के स्थिर अंतर को अभिव्यक्त करता हो'। यह नृवंशीय या प्रजातीय नागरिकता न केवल दुनिया भर के स्वदेशी और अल्पसंख्यक नृवंशीय समूहों द्वारा अनुभव की जाती है, बल्कि प्रवासियों का समूह भी प्रजातीयकरण/नस्लीकरण की प्रक्रिया का अनुभव करते हैं जैसा कि जर्मनी में तुर्कों के साथ या अमेरिका में लेटिन अमेरिकियों के साथ होता है। इस प्रजातीयकरण/नस्लीकरण की प्रक्रिया का अर्थ है कि किसी समूह को प्रजातीय या सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर एक समरूपीय समूह के रूप में अवमूल्यांकित और निर्मित किया गया है।

एक यूरोकेंद्रित विश्व-व्यवस्था में राष्ट्र-राज्य की इस अवधारणा में, राष्ट्र वह धुरी है जिस पर आधुनिक राज्य बनाए गए हैं और जो उनकी वैधता का आधार है। राष्ट्र और आधुनिक राज्यों के बीच संबंध स्पष्ट प्रतीत होता है और आमतौर पर हमारे दैनिक जीवन पर सवाल नहीं उठाया जाता है। हम अक्सर 'राष्ट्र', 'राज्य' और 'देश' शब्द का उपयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। और कभी-कभी हम नागरिकता को इन सभी का समानाथ मानते हैं।

> वैध और अवैध नागरिक

एक समरूप सांस्कृतिक समूह के रूप में राष्ट्र को एकीकृत

“नस्लीय नागरिक, गैरकानूनी नागरिक का हमेशा एक समूह के हिस्से के रूप में वर्णन किया जाता है, और कभी स्वायत्त व्यक्ति विषय के रूप में नहीं”

करने वाले लोग वैध नागरिक माने जाते हैं, जबकि नृवंशीय नागरिकों को अवैध माना जाता है। बाद वाले समूह को देश का नागरिक तो माना जाता है लेकिन वैध या 'वास्तविक' नहीं। नृवंशीयकरण और प्रजाति अवमूल्यन से संबंधित यह अवैधनिकता एक विशिष्ट प्रकार की असमानता है जो लोगों की गरिमा और उनके लिए उपलब्ध अवसरों को प्रभावित करती है और भेदभाव और अपमान में वृद्धि करती है। यह असमानता राष्ट्र-राज्य की उत्पत्ति के साथ नागरिक असमानता के रूप में शुरू हुई, लेकिन यह ऐसे वर्गीकरण और संरचनाओं का अनुकरण करती है जो पहले (पूर्व राष्ट्र-राज्य या औपनिवेशिक काल से) से विद्यमान हैं। राष्ट्र-राज्य निर्माण या स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने एक समरूपतामूलक राष्ट्रीय पहचान को प्रोत्साहित किया जिसके कारण कुछ समूहों ने अपनी विशिष्ट पहचानों को छोड़ दिया, जैसा मैपचेस समूह (चिली के स्थानीय लोग), या भारत में पूर्वोत्तर के लोग (जो भारत में कई अलग-अलग नृवंशीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन समान रूप से रुढ़िग्रस्त और बहिष्कृत हैं) और जैसा कि आज नृवंशीय प्रवासियों (जैसे जर्मनी में तुर्की प्रवासियों) के साथ होता है। चिली में मैपचेस और भारत में पूर्वोत्तर के लोग कम औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जहां रोजगार और शैक्षणिक विकास के अवसर भी कम हैं। दोनों समूह राज्य और पुलिस (सेना के साथ भी पूर्वोत्तर के मामले में) के साथ लम्बे समय से संघर्ष का सामना कर रहे हैं और उनकी पहचान को प्रभुत्वशाली राष्ट्रीय पहचान का विरोध झेलना (सामना करना) पड़ता है। पूर्वोत्तर के मामले में, उन्हें शेष आबादी से भी हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से जब वे पूर्वोत्तर छोड़ते हैं और दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे शहरों में प्रवास के लिए जाते हैं।

वैध और अवैध नागरिक के रूप में दो प्रकार की नागरिकता की चर्चा की जा सकती है परन्तु दोनों को ही कानूनी मान्यता प्राप्त है। हालांकि, सम्बद्धता का पक्ष केवल वैध नागरिकों के साथ जुड़ा है, जबकि अवैध नागरिकों को द्वितीयक/गौण माना जाता है। अवैध नागरिकों में कुछ पक्षों का अभाव देखा जाता है, जैसे उनकी संस्कृति और व्यवहार अपूर्ण दिखा देता है और यह पक्ष भेदभाव और अपमान को बढ़ावा देता है जिसे शेष समाज देख नहीं पाता।

> लोकतंत्र के लिए परिणाम

नागरिकता एक अवधारणा है जो व्यक्तियों को अभिव्यक्त करती

है लेकिन जब इसे प्रजातीय या नृवंशीय रूप में देखा जाता है, तो व्यक्तियों की वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है। प्रजातीय नागरिक या अवैध नागरिक को हमेशा किसी समूह के एक भाग के रूप में वर्णित किया जाता है : जैसे 'आप्रवासी', 'अरब', 'मुस्लिम', 'स्थानीय/देशज', 'पूर्वोत्तर भारतीय', परन्तु उन्हें कभी स्वायत्त व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखा जाता। यह व्यक्तिवादिता श्वेत समूहों के लिए आरक्षित है। परिणामस्वरूप, एक श्वेत यूरोपीय व्यक्ति को या यूरोपीय वंशज की असफलताओं को उनकी व्यक्तिगत त्रुटियों के रूप में देखा जाता है, उनके पास व्यक्तिगत नागरिक होने का विशेषाधिकार है। इसे 'श्वेत विशेषाधिकार' की संज्ञा दी गयी है। दूसरी तरफ, औपनिवेशिक पक्षों की असफलताओं, अवैध नागरिक की त्रुटियों के लिए उनकी संस्कृति, राष्ट्र, प्रजाति/नस्ल, नृवंशीयता को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन कभी भी एक स्वायत्त नागरिक के रूप में व्यक्ति को उसका जिम्मेदार नहीं माना जाता। अवैध नागरिक हमेशा अपनी नृवंशीयता और प्रजाति से बंधे रहते हैं जिसके कारण वे लोग उन विशेषाधिकारों का आनंद नहीं ले पाते हैं जो श्वेत समूह के लोग लेते हैं। श्वेत विशेषाधिकार एक अदृश्य प्रवृत्ति के रूप में कार्य करता है, विशेषाधिकार प्राप्त समूह की नृवंशीयता और प्रजाति का कभी भी उल्लेख नहीं किया जाता है। यह चलन में ही नहीं है और यह तथ्य है कि यह पक्ष व्यक्तिवादिता को स्वतंत्रता प्रदान करता है। विशेषाधिकार प्राप्त समूहों की उपलब्धियों और असफलताओं को व्यक्तिगत उपलब्धियों के रूप में देखा जाता है, न कि उनकी नृवंशीयता या प्रजातीयता के साथ सम्बद्धता के रूप में।

कुछ समूहों के अनुभव को स्वीकार न करने पर संघर्ष और यहां तक कि हिंसा भी हो सकती है यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अपने वर्तमान विश्व में, हम सांस्कृतिक, प्रजातीय या नृवंशीय आधार पर समरूपीय राष्ट्र-राज्यों के बारे में नहीं सोच सकते। उन लोगों को सुनना जो खामोश/शांत हो चुके हैं एक ऐतिहासिक ऋण है, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए जिसको चुकाना अनिवार्य है। ■

सभी पत्राचार एंड्रिया सिल्वा-तापिया को

<andrea.silva-tapia@sowi.uni-giessen.de> पर प्रेषित करें।

> 1994 पश्चात के दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र का भ्रम

हलेन्गीवे एनडलोवू, विटवाटर्सरेड विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका द्वारा



हाल के वर्षों में, दक्षिण अफ्रीका, 1976 के सोवेटो छात्र विद्रोह के बाद से, विवादास्पद रूप से, अपने आंतकवाद में अप्रत्याशित, एक छात्र आंदोलन की पकड़ में रहा है। 2015 में #फीस मस्ट फॉल आंदोलन उभरा और 2016 तक जारी रहा। मांगें मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और उच्च शिक्षण संस्थानों में परिवर्तन और उनके वि-औपनिवेशिकरण के आसपास रची थी। यह आंदोलन सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में फैला और यह विद्यार्थियों और आउटसोर्स किये गये विश्वविद्यालय शिक्षकों के मध्य एक अद्वितीय गठबंधन की विशेषता लिये हुये था। इन संघर्षों के केन्द्र में, लोकतंत्र की विफलताओं और 1994 के बाद के दक्षिण अफ्रीका में लोगों को बेचे गये 'इंद्रधनुष राष्ट्र' के विचार के भ्रम से सीधा टकराव था।

रायटिंग एण्ड राइटिंग पुस्तक '#फीस मस्ट फॉल' आंदोलन से निकली और इसमें छात्र कार्यकर्ताओं के लेख हैं। कॉपीराइट: एसडब्ल्यूओपी।

यद्यपि लोकतंत्र की अवधारणा की विविध व्याख्याएँ हैं जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारें, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और विविध मानव और व्यक्तिगत अधिकारों का प्रयोग सम्मिलित है, कई दक्षिण अफ्रीकी लोगों के लिये लोकतंत्र का अर्थ बहुसंख्यक जनसंख्या के ऐतिहासिक अपवर्जन में गहराई से स्थित है। सदियों की दासता और औपनिवेशीकरण के अलावा, वहां नस्लीय रंगभेद प्रणाली के खिलाफ 46 सालों की लड़ाई थी जिसने अश्वेत लोगों को सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों और आर्थिक अवसरों से जानबूझकर अपवर्जित और अलग किया था। अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोग लोकतंत्र के ठोस अर्थ की आशा कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण रूप से, संघर्ष की मुख्य हस्तियों में से एक, बिशप देसमंड टुटु के द्वारा दिया गया 'इंद्रधनुष राष्ट्र' के विचार ने सुझाव दिया कि नस्लीय प्रणाली के जाने से, नस्लीय रूप से विभाजित दक्षिण अफ्रीकी लोग समान सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधनों वाले एक राष्ट्र बन जायेंगे।

#फीस मस्ट फॉल आंदोलन एक संघर्ष था/है जो इस अनुभूति के चारों ओर बना था कि लोकतंत्र एक स्वांग और 'इंद्रधनुष राष्ट्र' एक मिथक था। यद्यपि अन्य के मध्य अधिकांश ऐतिहासिक रूप से श्वेत संस्थान जैसे कि विटवाटर्सरेड विश्वविद्यालय और केपटाउन विश्वविद्यालय, अश्वेत छात्रों की बढ़ती संख्या के द्वारा अपनी विद्यार्थी जनसंख्या में बदलाव लाने के लिये गर्व महसूस करते हैं, यह वास्तविकता से बहुत दूर है। ये दो विश्वविद्यालय अभी भी देश के सबसे मंहगे विश्वविद्यालयों में आते हैं जहां सांस्कृतिक और सर्वव्यापक हिंसा गहरी जड़ें रखते हैं। इसके अलावा, जबकि अश्वेत छात्रों की संख्या बढ़ी है, उच्च शिक्षा के संस्थान सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि वाले छात्रों को व्यवस्थित रूप से अलग करना जारी किये हुये हैं।

दक्षिण अफ्रीका में, यह आशा की गयी कि 1994 के बाद, पूर्व में अपवर्जित समूहों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से लाभ होगा; मुख्य लिबरेशन पार्टी, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी), ने 'सभी के लिये एक बेहतर जीवन' का नारा रखा था। लोगों को उम्मीद थी कि

>>

सभी क्षेत्रों — फ्रीडम चार्टर में प्रस्तावित मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, उचित आवास, पानी, बिजली, रोजगार के अवसरों और स्वच्छता तक पहुंच सहित — जैसा कि *रिकंस्ट्रक्शन एंड डवलपमेंट प्रोग्राम* (आरडीपी) के नीति दस्तावेज में रेखांकित किया गया था, में उनका जीवन बेहतर होगा। 1994 के बाद वितरण संबंधी विरोधों की लहरों ने अश्वेत बस्तियों को तबाह कर दिया, श्रम क्षेत्र में हिंसा जैसे कि 2012 का *मरिक्काना* नरसंहार, और अन्य मामलों के बीच #फीस मस्ट फॉल विरोधों ने दक्षिण अफ्रीकी राज्य की लोकतंत्र के अपेक्षित परिणामों को लाने में असफलता प्रदर्शित की।

दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालयों को व्यापक सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। 1994 के बाद के लोकतांत्रिक संकटों को खोलने के लिये, दक्षिण अफ्रीकी लोकतंत्र के तय किये गये परिवर्तनों का पुनरीक्षण करना महत्वपूर्ण है जैसे कि अफ्रीका में अन्य तय की गयी स्वतंत्रतायें। वार्ता करने का सामान्य अर्थ है कि 'शांतिपूर्ण परिवर्तन' को हासिल करने के लिये बेताब प्रयासों में छिपी हुई वार्ता करने वाली पार्टियों का नीतीपूर्ण पुनर्स्थानीकरण। इसके परिणामस्वरूप अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों को केवल वोट देने के अधिकार के प्रयोग और संगठित होने की राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुयी — एक ऐसा अधिकार जो 1994 पश्चात की राज्य हिंसा के द्वारा खतरे में पड़ना जारी है। दूसरी तरफ, आर्थिक शक्ति और सामरिक संसाधन जैसे जमीन, बैंक, और खदानें अपने पूर्व मालिकों के हाथों में बने रहे — जिसने श्वेत सर्वोच्चतावादी व्यवस्था के प्रभुत्व को कायम रखा। इसने अश्वेत जनसंख्या के लगभग 80 प्रतिशत को अर्थव्यवस्था से बाहर करना जारी रखा। 1994 पश्चात के दक्षिण अफ्रीका में, संरचनागत आर्थिक असमानताओं का सामना किये बिना, लोकतंत्र के बारे में बात करना इसलिये असंभव बन जाता है।

#फीस मस्ट फॉल आंदोलन अपवर्जन, मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, परिवर्तन और अकादमिक परियोजनाओं और विश्वविद्यालय संस्कृति के वि-औपनिवेशीकरण के प्रश्नों का सामना करने के लिये पैदा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि अन्य के मध्य, ऐतिहासिक रूप से अश्वेत विश्वविद्यालय जैसे फोर्ट हारे विश्वविद्यालय (जहां कई अफ्रीकी संघर्ष आइकॉन शिक्षित हुये थे), जहां तक का इतिहास याद रह सके तब से इस संघर्ष में रहे हैं। हालांकि, इन्होंने दूसरी समस्याग्रस्त घटना — ऐतिहासिक रूप से श्वेत विश्वविद्यालयों का दक्षिण अफ्रीकी श्वेत सुपरमासिस्ट मीडिया के द्वारा रोमांटिकरण — ने इस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों तक बढ़ाया जहां इसे विटवाटर्सरेड विश्वविद्यालय में प्रारम्भ हुआ दिखाया गया। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि #फीस मस्ट फॉल यूसीटी के #रोड्स मस्ट फॉल आंदोलन के कुछ महीनों बाद आया जहां वृहद उच्च शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम के परिवर्तन और वि-औपनिवेशीकरण के मुद्दे पहले से ही उठाये जा रहे थे। वि-औपनिवेशीकरण की परियोजना से अलंघनीय रूप से जुड़े, ये संघर्ष सत्तामूलक और ज्ञानमीमांसीय तरक्की की कीमत पर विश्वविद्यालयों के व्यवसायीकरण और बाजारीकरण की वैश्विक परियोजना की आलोचना का हिस्सा बन गये।

यद्यपि ऐतिहासिक रूप से श्वेत संस्थान विद्यार्थी जनसंख्या के मामलों में परिवर्तित होने का दावा करते हैं, फिर भी संरचनात्मक व्यवस्थित अपवर्जन नस्लीय रेखाओं के साथ असमानताओं को बांटना जारी रखता है। अत्यधिक शुल्क का अर्थ है कि वे जो भुगतान कर सकते हैं — प्रमुख रूप से श्वेत लाभान्वित छात्र और

कुछ मध्यमवर्गीय अश्वेत — प्रवेश लेंगे, जबकि अधिकांश अश्वेत इन्द्रधनुष राष्ट्र की धारणा को हराते हुये व्यवस्थित रूप से बाहर हो जायेंगे — इसके अलावा, अकादमिक स्टॉफ — अंतर्राष्ट्रीय और दक्षिण अफ्रीकी दोनों, श्वेत बने रहते हैं, जबकि अकादमिक पाठ्यक्रम मुख्यतः यूरोकेंद्रित बना रहता है। यह बेमेलता और सांस्कृतिक टकराव पैदा करता है। अधिकांश अकादमिक स्टॉफ की सत्तामूलक और ज्ञानमीमांसीय ज्ञान निर्माण के अफ्रोकेंद्रित तरीकों को अपनाने में विफलता गरीब बस्तियों के अधिकतर अश्वेत छात्रों के लिये एक चुनौती बनी रहती है।

#फीस मस्ट फॉल आंदोलन ठोस लोकतंत्र को प्राप्त करने और 'इन्द्रधनुष राष्ट्र' के सपने को साकार करने के लिये लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलताओं का सामना करने के लिये उभर कर आया। यद्यपि आंदोलन ने विश्वविद्यालयों और राज्य के लिये एक बड़ी चुनौती उत्पन्न की, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी थी। अपने शुरुआती चरणों में, आंदोलन में सभी राजनीतिक संबद्धताओं, नस्ल, और वर्ग में एकता इसकी विशेषता थी। हालांकि, शुरु से ही, यह वैचारिक मुद्दों और लिंग के प्रश्नों के आसपास आंतरिक लोकतंत्र के अभाव से ग्रस्त था। यद्यपि आंदोलन को महिलाओं द्वारा शुरु किया गया था, इसका महिला और लिंग गैर-अनुरूप लोगों को कमजोर करते हुये पुरुष साथियों द्वारा जानबूझकर अधिग्रहण किया गया था। हालांकि #फीस मस्ट फॉल में महिलाएं दृढसंकल्पित थी कि वे वही पितृसत्तात्मक प्रणाली पैदा नहीं करेंगी जिसके खिलाफ वे लड़ रही थीं। इसने आंदोलन को विभाजित कर दिया, क्योंकि कई असहमत आवाजों को विभाजनकारी बनने के लिये आरोपी ठहराया गया। इसके अलावा, राज्य और विश्वविद्यालय बहुत अधिक दमनकारी और हिंसक बन गये। उपद्रव पुलिस को परिसरों में तैनात किया गया और अत्यधिक बल प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। छात्र कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और गिरफ्तार किया गया, और कुछ को विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया गया। अलोकतांत्रिक राज्य की दमनकारी प्रकृति को देखते हुये, आंदोलन को पीछे हटना पड़ा और संघर्ष को बढ़ाने के वैकल्पिक साधनों को खोजना पड़ा।

#फीस मस्ट फॉल आंदोलन वर्तमान में ठंडे बस्ते में है। कुछ छात्र कार्यकर्ता अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं और कुछ अदालती मामलों में भाग ले रहे हैं। यद्यपि दक्षिण अफ्रीकी राज्य गरीबों के लिये मुफ्त शिक्षा शुरु करने की दिशा में प्रगति कर रहा है, फिर भी मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और वि-औपनिवेशीकरण के लिये संघर्ष जारी है। लोकतंत्र 1990 के दशक में दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर होने वाली घटना बना हुआ है। यह अंत के संघर्ष आइकॉन नेल्सन मंडेला और अन्य राजनीतिक कैदियों की रोबेन द्वीप से रिहाई के साथ समाप्त हुआ। अधिकांश दक्षिण अफ्रीकी लोगों के लिये, लोकतंत्र एक स्वांग और 'इन्द्रधनुष राष्ट्र' एक मिथक बना हुआ है। #फीस मस्ट फॉल कार्यकर्ताओं के लिये, संघर्ष जारी है, और महिलाओं और अन्य अपवर्जित अंगों के लिये, लोकतंत्र आने वाली सदियों के लिये एक संघर्ष बना हुआ है। ■

सभी पत्राचार को हलेन्गीवे एनडेलोवू को <hlengiep@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> एथेंस में लोकतंत्र

गेरासिमोस कौजेलिस, एथेंस विश्वविद्यालय, ग्रीस, द्वारा



मित्ययिता के उपायों के विरुद्ध ग्रीक पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन।
पिलकर/कॉन्टेरेज। कुछ अधिकार सुरक्षित।

आजकल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात करना आदर्श लग सकता है क्योंकि वास्तव में इसके लागू होने की क्षमता बेहद सीमित है। संसद से परे पर्याप्त लोकतांत्रिक नियंत्रण का विचार, जैसा कि हाल ही के साहित्य में मिलता है, यूटोपियन तत्वों वाले एक आमूल परिवर्तनवादी दावे की तरह लगता है। किस तरह 'प्रदर्शन', लोग, मध्यस्थ शक्ति और शासन में नियंत्रण का प्रयोग करते हैं जहां शर्तों का निर्धारण बाहरी कर्ताओं — अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि लोकतांत्रिक रूप की संरचना नहीं है, द्वारा किया जाता है? ग्रीस में स्थितियां, 'मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' पर आधारित, ऐसी स्थितियां नहीं है जो लोकतंत्र को कार्य करने देती हैं। संसद-लोगों के प्रतिनिधि-स्वायत्ता से कार्य नहीं कर सकते; उनके निर्णय काफी हद तक पूर्व निर्धारित होते हैं।

यह तथ्य कि राष्ट्रीय संप्रभुता आंशिक रूप से समझौते पर आधारित है, जैसा कि स्वायत्त निर्णय लेने का संसद का अधिकार उस संकट का परिणाम (कई के लिये न्यायसंगत) है जिसकी प्रकृति राजकोषीय मानी गई और जिसके ग्रीस का ऋण जैसे वित्तीय प्रभाव थे संकट जिसने मितव्ययता और राष्ट्रीय संप्रभुता को जोखिम में डालने के लिये दबाव डाला, वास्तव में राजकोषीय है — प्रचलित आर्थिकवाद इस पहलू पर सही है — परंतु यह सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक कारणों से राजकोषीय है। इसकी क्षमता

के साथ साथ इसकी जरूरत नियामक सामाजिक राज्य को निषिद्ध करने के कारण है; प्रतिद्वंद्वी की अनुपस्थिति में विनाशकारी उदारवादी विचारधारा का प्रचलन; अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों का सामाजिक और राजनीतिक रूप से नियंत्रित पुनर्गठन; और विशेषतः, पूंजी समेकन और आर्थिक शक्ति खंड का संगठन। इस प्रकार बलों के एक विशिष्ट सहसंबंध ने संकट को पोषित किया और शोषण करने की अनुमति प्रदान की।

यद्यपि 'नवउदार प्रभुत्व' शब्द एक अपेक्षाकृत सरल शब्द है, यह दर्शाने में उपयोगी है कि कैसे लोकतंत्र का पतन, शुरुआत से ही, वार्तालाप ('नवउदारवाद') के प्रचलन के साथ चला जो इस प्रकार के प्रभुत्व पर पकड़ रखता है, वैधता देता है और विस्तृत करता है। विशेषतः ग्रीक संकट के परिप्रेक्ष्य से, लोकतंत्र का गहराई से विखंडन नवउदारवाद के ठंडे कठोर सत्य की तरह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार की वार्ता के साथ जुड़े घटनाक्रम, इसकी अभिव्यक्तियों के साथ साथ इसके परिणामों की स्थितियों, पूंजीवादी प्रजनन की गतिशीलता के साथ साथ थोपे गये अल्पकालिक रुझान, सभी सामाजिक तानाशाही को मजबूत करने में प्रतिच्छेद करते हैं।

मैं नीचे राजनैतिक परिवर्तनों से पूर्व 2010-2015 की अवधि के

दौरान व्यापक रूप से चर्चित अनेक अक्षों को सूचीबद्ध करता हूँ :

- उत्पादन से परे सामाजिक संगठन के क्षेत्र में पूर्ण रूप से वर्धित आर्थिक शक्ति और इसके हस्तक्षेप, जिसकी विशेषता उस प्रकार और मात्रा के घोटाले हैं जो 'अभिजात वर्ग' में प्रवेश करते हैं और आर्थिक हितों को राजनीतिक के साथ गुंथते हैं।
- मीडिया और सांस्कृतिक प्रथाओं (प्रमुखतः पार्टी आधारों पर आयोजित एकाधिकारवादी मास मीडिया और प्रेस परिसरों) का संपूर्ण व्यवसायीकरण
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रक्रियाओं की गिरावट और व्यापार-विपणन जैसा पुर्ननिर्माण (व्यवसायिक उत्पादों के रूप में प्रस्तुत और टेलीविजन 'सितारों' द्वारा प्रतिनिधित्व की गयी 'राजनीति से ऊंची उठती' पार्टियाँ)
- वस्तुओं के परिसंचरण ('बाजार मार्ग दिखाता है।') की अंधी कार्यप्रणाली को अपने मुख्य सिद्धांत की तरह मानने वाले तर्क का प्रचलन।
- 'लोकतंत्र प्रबंधन' की तरह थोपी गयी प्रक्रिया और जो आंशिक रूप से न्यायपालिका, और विधायिका के खर्च पर, कार्यपालिका के लगातार विस्तार के कार्य के दौरान कार्यान्वित की गयी (बिना संसद की सहमति और न्यायिक हस्तक्षेप के मंत्रीस्तरीय निर्णयों के माध्यम से जो प्रकृति में राजनीतिक और एकपक्ष में ढली हुयी थी)।
- राष्ट्रीय सामाजिक गठन और इसके अंतर्राष्ट्रीय अनुलग्नकों दोनों के अंदर राज्य संप्रभुता का अस्थिरकरण ('ट्रोइका शर्तों' की दैनिक तर्कसंगतता के माध्यम से)।
- छोटे टापूओं का निर्माण जो लोकतांत्रिक नियंत्रण के लिये दुर्गम, प्रचार से दूर, और स्वयं संसद के लिये अदृश्य, जैसे कि राजकोषिय और मौद्रिक नीति के क्षेत्र, परंतु जिनका एक बड़ा हिस्सा ब्रुसेल्स द्वारा निर्णित (वास्तव में अपवाद की स्थिति को पैदा करते हुए)।

जब 2015 में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, इन अक्षों के पहलुओं में भी बदलाव आया। इस प्रकार, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के सशक्त और स्पष्ट उद्देश्य – सिरिजा के लिये एक केंद्रीय नीति विकल्प – नवीनतम अक्ष के रुझानों का पलटने में कामयाब रहे। मौटे तौर पर संसद नियंत्रण बहाल करने में परंतु पूरा नहीं, अधिकतर निर्णय अभी भी बाहरी केंद्रों या 'संस्थाओं' (अब तथाकथित) से प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं।

मुख्यतः, इस नयी राजनीतिक स्थिति ने सुरक्षा बलों के द्वारा प्रबलित सुरक्षा उपायों, निगरानी और अधिनायकवादी दमन की खतरनाक रूप से अनियंत्रित गतिशीलताओं को यहां प्रतिबंधित कर दिया, जो खुले तौर पर नाजी समूहों को सहयोग कर रही थी, और इसने समाज में लोकतांत्रिक सजगता को विकसित होने दिया। दैनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र फिर से 'सामान्य' बन गया।

फिर भी वहां दो क्षेत्र बचते हैं जहां नवउदारवादी विमर्श स्थितियों को निर्धारित करना जारी रखते हैं, जिससे वसूली नीति का प्रभावी होना अधिक मुश्किल बनता है। पहली राजकोषिय आंकड़ों के रूप में, वस्तुओं के जटिल समूह जिसे 'लोग' ना नियंत्रित कर सकते हैं और ना ही आंकलन कर सकते हैं, और जैसा कि, खास तौर से अनियंत्रित, और किसी लोकतांत्रिक योजना और सामूहिक निर्णयों की जिम्मेदारी से परे है, के रूप में वास्तविकता

की कुटिल परिभाषा है। दूसरा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का विखंडन है और इसलिये, सार्थक आंकलन पर आधारित जनता की राय का निर्माण करना असंभव है। कुछ लोगों द्वारा नियंत्रित मीडिया की रौबदार चर्चा की प्राथमिक व्यवस्था बनी रहती है जो 'वास्तविकता के निर्माण' पर राजनीतिक दृश्य में परिवर्तनों के बावजूद एकाधिकार रखती है जबकि परामर्श और तर्कों का आदान प्रदान असामान्य बन चुका है।

इन दोनों क्षेत्रों में गातिकी को पलटने की असमर्थता हमें याद दिलाती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का विखंडन संकट के नवउदारवादी प्रबंधन से इतना जुड़ा हुआ नहीं है जितना यह सामाजिक संगठन के पहलुओं से है जिनको व्यवस्थित के रूप में पहचाना जाता है और जिनको वर्तमान युग में लोकतंत्र के संकट के तत्वों के रूप में दर्ज किया गया है।

दूसरी तरफ आर्थिक संकट के आधार पर यानि कि अधिकारों के 'आवश्यक' परिसीमन का आंकाकारिकरण पर लोकतंत्र के सिकुड़ने को औचित्यपूर्ण ठहराने के कुख्यात विमर्श के रूप में तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। यह ना सिर्फ सामाजिक अधिकारों परंतु, शरणार्थी संकट और सार्वजनिक अभिव्यक्ति (चुनावों और जनमत संग्रह) की मांग के आतंकवादी हेरफेर के साथ साथ राजनीतिक अधिकारों की ओर भी इंगित करता है। संकट के पांच सालों के दौरान, सरकारों ने सामाजिक अधिकारों (कार्य सामाजिक कल्याण स्वास्थ्य) को पूर्ण रूप से खत्म करना शुरू कर दिया और राजनीतिक आग्रहों (नियंत्रण और जनमत) से इंकार कर दिया, इस विचार को विकसित करते हुये कि आर्थिक संसाधनों की कमी के मध्य यह सभी "विलासिता" हैं। भूली जा चुकी एकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्राथमिकता देकर, नई सरकार ने यह दर्शाया कि संकट सिर्फ एक बहाना था।

जहां परिदृश्य पर्याप्त रूप से नहीं बदला है और संकट, वैचारिक और वास्तविक रूप में दोनों जगह चल रहा है, जो सभी नागरिकों के जीवन के संगठन से संबंधित हैं, जहां तक दृष्टिकोणों, परिप्रेक्ष्यों और मानसिकता का, और उनकी उनके परिवार और समुदाय और साथ साथ उनके स्वयं के भविष्य का सवाल है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि परिप्रेक्ष्य की कमी सर्वसत्तात्मक और लोकतंत्र विरोधी अभिवृत्तियों के लिए लाभदायक है।

नव.नाजी बलों की शक्ति एक चुनौती प्रस्तुत करती है। यह वास्तव में खतरनाक रूप से बढ़ रही है और राजनीतिक संगठनों की अभिव्यक्तियों से जुड़ी है जो ग्रीस में एक पैरा.अर्थव्यवस्था के प्रारूपी 'धोखाधड़ी' के एक रूप में और दिन-प्रतिदिन अपराध के रूप में नयी प्रघटना का प्रतीक है। राष्ट्रवाद और लोकलुभावनवाद को पोषित कर रहे विशिष्ट राजनीतिक दलों की चर्चा और लाभों और शक्ति से संबंधित प्रचलित नवउदारवादी चर्चा के पहलुओं ने (संस्थागत नियमों और 'नौकरशाही' की विवशताओं को अनदेखा करते हुये 'मजबूत व्यक्तित्वों' के साथ साथ 'प्रभावी निर्णय लेना') बहुत नकारात्मक भूमिका निभायी है, ना सिर्फ बहुत बार एक रिक्त वाक्पटुता में बहते हुये, बल्कि एक गिरोह 'राजनीति' को सहन करते हुये। इस प्रकार वर्तमान स्थितियों में कमजोर लोकतंत्र को सतर्कता की जरूरत है। ■

सभी पत्रचार गेरासिमोस कौजेलिस को <gkouzelis@pspa.uoa.gr> पर प्रेषित करें।

> सोशल मीडिया एवं लोकतंत्र एक दुधारी तलवार?

हरियाती अब्दुल करीम, मलेशिया सबाह विश्वविद्यालय, यू.एस.ए.



19

सेलफोन और सामाजिक मीडिया राजनैतिक सक्रियतावाद के आवश्यक/
जरूरी हिस्सा हो गये हैं। फिल्मर/एलेक्स प्रोमिसोस। कुछ अधिकार सुरक्षित।

समाज पर सोशल मीडिया के गहनतम प्रभावों में से एक निस्संदेह यह है कि यह किस हद तक सामान्य नागरिकों के लिए अपने भावी जीवन को निर्धारित करने के लिए सशक्तिकरण का साधन बन गया है। आज के सामाजिक जीवन की विशेषता इंटरनेट सक्रियता है जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग आसानी से अपनी हथेलियों के बीच रखे स्मार्टफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यह निश्चित तौर पर नागरिकों को अपेक्षाकृत रूप से अज्ञात रहते हुए अपने देश और बाहर की दुनिया के बारे में सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेने और अधिक स्वतन्त्रता से

संलग्न होने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह विशेष रूप से उन देशों में मूल्यवान है जहां अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की संस्कृति या मानक नहीं हैं।

मलेशिया इस नए विकास के लिए अपवाद नहीं है। आज, मलेशियाई सभी प्रकार के विषयों पर स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का काफी प्रयोग करते हैं, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उनके लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जिन मुद्दों पर वे मजबूत राय रखते हैं, टिप्पणियां पोस्ट करना,

> >

वीडियो और वेबसाइट साझा या अपलोड करना एक आदत सी बन गई है। वे मित्रों के बीच आनलाइन चर्चा को भी प्रारम्भ करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया मलेशियाई लोगों के मध्य बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन फेसबुक इन सब में सबसे ऊपर है। लगभग 81 प्रतिशत मलेशियाई फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं जिनमें से 90 प्रतिशत इसका उपयोग स्मार्टफोन के माध्यम से करते हैं।

किस हद तक सोशल मीडिया ने मलेशियाई लोगों को वास्तव में 'मुक्त' किया है, इस का अनुमान इससे देखा जा सकता है कि वे सरकार एवं उन मुद्दों जिन्हें संवेदनशील माना जाता है जैसे धर्म, जातीयता के बारे में अपनी राय को खुलेतौर पर व्यक्त करते हैं। ऐसा वे ऐसी चर्चाओं को प्रतिबंधित करने वाले विद्यमान कानूनों के बावजूद करते हैं। यह एक स्वतंत्र और जीवन्त माहौल बनाता है जहां लोग स्वयं को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय मुद्दों में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक के अलावा, सोशल मीडिया मलेशियाई लोगों को एक हाइब्रिड वैश्विक स्थानीय पहचान को अभिव्यक्त करने और तराशने में सक्षम बनाता है।

उन देशों में जहां राज्य का मीडिया पर मजबूत नियंत्रण है, चाहे वो प्रत्यक्ष मीडिया स्वामित्व के माध्यम से या कानून के द्वारा, वैकल्पिक विचारों के लिए संचार के चैनल सीमित हो गये हैं। इसलिए, लोग नये मीडिया के माध्यम से भूमिगत होने को बाध्य हो जाते हैं। जनमत को आकारित करने में वैकल्पिक समाचार पोर्टलों की तुलना में सोशल मीडिया अधिक प्रभावी पाया जाता है। इसका एक उदाहरण अरब क्रांति में था जहां संचार के चैनल गंभीर रूप से सीमित थे और जनता ने सरकार और मुख्यधारा के मीडिया में विश्वास खो दिया था। सोशल मीडिया लोगों के लिए सूचना का एकमात्र स्रोत बन गया और एक स्थान भी जहां वे अपने विचार व्यक्त कर सकते थे।

मलेशिया में, 2008 के आम चुनावों के दौरान सोशल मीडिया ने जिसे राजनैतिक सुनामी कहा गया में योगदान दिया, जिसने राष्ट्रीय गठबंधन सरकार (बरिसन नेशनल या बीएन) के आधिपत्य को धीमे-धीमे बिखरते देखा। बीएन का राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी, जो एलायंस ऑफ होप के नाम से जाना जाता था, भूमिगत बना रहा क्योंकि वह मुख्यधारा के मीडिया से बाहर कर दिया गया था। पीएच के साइबर सैनिकों और समर्थकों के लिए सोशल मीडिया लोगों को अपने विचार फैलाने का एक साधन बन गया। अपने फेसबुक प्रशंसक पृष्ठों को प्रयोग में लेते हुए, उन्होंने माल एवं सेवा कर (जीएसटी), जीवित रहने की उच्च लागत, और बीएन सरकार की तथाकथित भ्रष्ट प्रथाओं जैसे पेचीदा मुद्दों को व्यवस्थित रूप से उजागर किया। इसने लोगों के मध्य चर्चा को पैदा किया और जनक्षेत्र का निर्माण हुआ। गठबंधन के मजबूत समर्थक ब्लागरस ने अपने पक्ष में जनमत को आकारित करने के लिए अपने ब्लॉग का इस्तेमाल किया। हाल ही में सम्पन्न चौहदवें आम चुनाव में, ट्विटर और फेसबुक के साथ व्हाट्स एप को भी अभियान के एक उपकरण के रूप में काम में लेना शुरू कर दिया। फेसबुक के विपरीत व्हाट्स एप लोगों तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचता है। पीएच के अभियान संदेशों पर चर्चा करने हेतु व्हाट्स एप चेट समूह के भीतर व्यक्तियों

में एक जनक्षेत्र का निर्माण हुआ। शायद यह एक बहुत ही व्यवस्थित अभियान रणनीति थी जहां पीएच ने विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया और लगातार उन्हें प्रेषित किया जिसके परिणामस्वरूप 61 वर्षीय पुरानी बीएन सरकार को उखाड़ फेंका। मुख्यधारायी मीडिया पर नियन्त्रण होने के कारण बीएन सोशल मीडिया की तरफ मुड़ने में धीमा था। पीएच की संचार रणनीति का परिणाम था कि इसने 222 में से 113 संसदीय सीटें जीती जबकि 9 मई 2018 के चुनाव में बीएन 79 सीटें हासिल करने में कामयाब रही।

जब सोशल मीडिया, प्रेस की स्वतन्त्रता और लोकतंत्र का सवाल उठाता है, सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है। यद्यपि यह अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और आत्म सशक्तिकरण के लिए कई द्वार खोलता है, यह नकली समाचार के निर्माण और वायरल होने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मलेशियाई लोगों के बीच नकली खबर एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। हाल के आम चुनावों में, सोशल मीडिया में प्रामाणिक समाचार रिपोर्टों के बजाय मतदाता नकली समाचारों से भर गये। फर्जी समाचारों द्वारा सूचना को पूर्णता से विकृत करने के साथ, यह अंततः नागरिकों के सच जानने के अधिकार को नकारता है। सूचना के एक मात्र स्रोत के रूप में सोशल मीडिया पर अत्यधिक निर्भरता ने नकली खबरों के फलने फूलने में योगदान दिया क्योंकि नागरिक शायद ही तथ्यों की जांच करते हैं। 2018 में नकली खबर विरोधी अधिनियम पारित कर के इस मुद्दे को सम्बोधित करने के सरकार के प्रयास खबरों में 'नकली' क्या है को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में असफल रहे। बहरहाल, यह अधिनियम अल्पकालिक दिखाई दिया क्योंकि नई सरकार ने इसे रद्द करने के अपने इरादे की घोषणा की है।

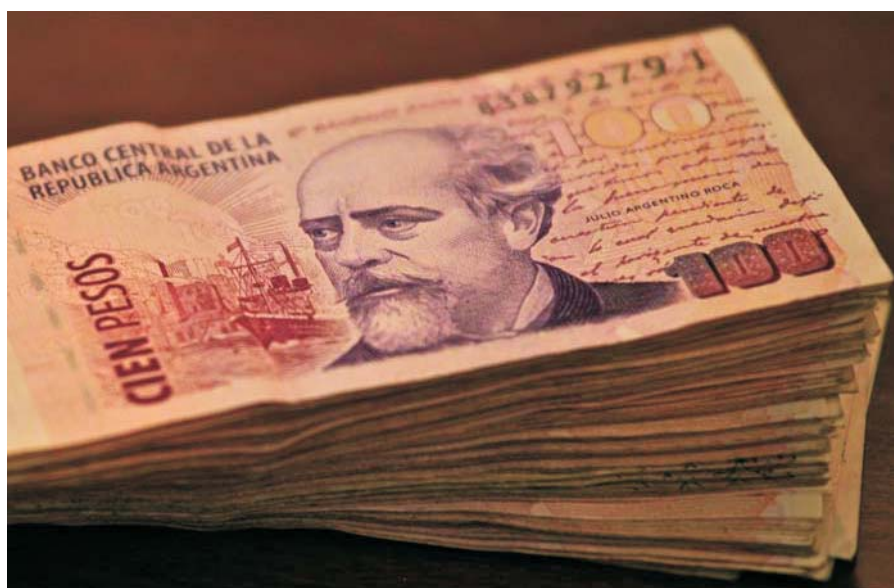
जो दूसरा खतरा सामाजिक मीडिया के कारण होता है वह है जब प्रभुत्व वर्ग के समर्थकों का राजनैतिक कट्टरतावाद साइबर स्पेस में अन्य विचारों पर शासन करता है। वैकल्पिक पदों वाले लोग साइबर दादागिरी का शिकार होते हैं, इतना कि वो किसी भी लोकतांत्रिक चर्चा में भाग लेने से हतोत्साहित हो जाते हैं जबकि अन्य राजनैतिक कट्टरपंथियों के शत्रुतापूर्ण व्यवहारी से आहत होते हैं। उठाये गये बिन्दुओं में से यदि कोई सही भी है, राजनैतिक कट्टरपंथी एकजुट होकर ऐसे उपयोगकर्ताओं की अश्लीलता के साथ निंदा करते हैं, जो उनकी राय व्यक्त करने के अधिकार और स्वतन्त्रता को नकारते हैं। सामान्य नागरिकों के स्तर पर सम्यता और तार्किकता का अभाव सार्वजनिक मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा में शामिल होने की उनकी भावना को बुझा देता है।

सोशल मीडिया के सच्चे लोकतंत्र के लिए एक प्रभावी साधन बनने के लिए, सम्यता और मीडिया साक्षरता को पहले नागरिकों के मध्य आदर्श और संस्कृति का निर्माण करना होगा। नागरिकों को तर्कसंगत संचार का अर्थ समझना होगा। केवल तभी विचारों के आदान-प्रदान से राष्ट्र का वास्तविक नवनिर्माण किया जा सकता है। ■

सभी पत्राचार हरियाती अब्दुल करीम को <haryati@ums.edu.my> पर प्रेषित करें।

> अर्जेंटीना में लोकतंत्र का पलायन

एस्तेबान टोरेस कास्टानोस, कॉर्डोबा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान परिषद (कोनीसेट), अर्जेंटीना द्वारा



अर्जेंटीना में नये आर्थिक संकट ने लोकतंत्र के लिए नवीन चुनौतियां पैदा की हैं। फिलकर/एलेक्स प्रोमिमोस। कुछ अधिकार सुरक्षित।

21

अर्जेंटीना गणराज्य लोकतंत्र के एक उल्लेखनीय पलायन को अनुभव कर रहा है। इस पलायन के विस्तार और जटिलता को समझना मुश्किल है यदि हम लोकतंत्र के उन सिद्धान्तों का उपयोग करते हैं जो सैन्य तानाशाही के पतन के साथ देश में और लेटिन अमरीका में वामपंथ और प्रगतिशील ताकतों के लिए प्रमुख विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क बन गये हैं। सार्वजनिक विनियोग की ताकतों के विस्तार की सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझा जाने वाले समकालीन लोकतांत्रिकरण में तीन महत्वपूर्ण वेक्टर सम्मिलित हैं : एक तकनीकी-राजनैतिक वेक्टर, एक तकनीकी-आर्थिक वेक्टर और एक तकनीकी-संचार वेक्टर। इनमें से प्रत्येक के कुछ मुट्ठीभर आयाम हैं। यहां मैं केवल इन महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करना चाहता हूं जो 2018 में अर्जेंटीना में लोकतंत्र के संरचनात्मक पलायन को प्रबल कर रही थी। ये घटनाएं उपर उल्लेखित राजनीतिक वेक्टर के राजनीतिक दमनकारी आयाम से और एक परिधीय देश के तकनीकी-आर्थिक वेक्टर के प्रमुख पक्ष : अपनी समष्टि आर्थिक नीति को परिभाषित करने की राज्य की स्वायत्तता की छिड़ी से जुड़ी हैं।

राजनीतिक दमनकारी पक्ष के संबंध में, दो मुख्य घटनाएं जो एक-दूसरे को प्रबलित करती हैं, वो हैं : (1) राष्ट्रीय कार्यकारी शक्तियों का सशस्त्र बलों के सैद्धान्तिक और प्रकार्यात्मक रूपांतरण को राजाज्ञा द्वारा स्थापित करने का निर्णय और (2) राष्ट्रीय क्षेत्र के विभिन्न भागों में अमरीकी सैन्य अड्डों को स्थापित करने का स्वयं सरकार समर्थन।

पहली घटना के संबंध में कार्यकारी शक्ति द्वारा राजाज्ञा N° 683/2018 से प्रोत्साहित रूपांतरण का स्तम्भ सशस्त्र बलों द्वारा घरेलू सुरक्षा कार्यों को करने की अनुज्ञा है। इसके साथ, घरेलू सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा के मध्य बाधा व्यवहारिक रूप से भंग हो जाती है जो दिसम्बर 2015 में कंबिमोस (सत्तारूढ़ गठबंधन) की जीत के बाद से पूरे देश में फैले सामाजिक प्रतिरोधों के अपराधीकरण के सरकार के इरादे को मजबूती प्रदान करती है। इस कदम के साथ, मॉरीसियो मैक्री की सरकार सशस्त्र बलों को 'नशीली दवाओं की तस्करी विरोधी और आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम' की सेवा में लगाने का प्रयास करती है जिसके माध्यम से

>>

यह अमरीकी विदेश नीति के एजेण्डे के साथ पूर्णता से संरेखित होते हैं। इस राजाज्ञा के कार्यान्वयन के साथ, राजाज्ञा N° 1691/2006 का निर्मूलन हो जाता है और राष्ट्रीय रक्षा कानून (1998), घरेलू सुरक्षा कानून (1997) और राष्ट्रीय खुफिया कानून (2001) से जुड़ा कानूनी ढांचा खंडित हो जाता है। तीन दशकों के लोकतांत्रिक विस्तार के परिणामों के फल के रूप में ये नियम राष्ट्रीय इतिहास में अपने महत्ता में अप्रत्याशित बहुदलीय मतैक्य से निर्मित हुए थे।

दूसरी घटना के बारे में, सरकार अर्जेन्टीना की भूमि पर अमरीकी सैन्य अड्डों की स्थापना को बढ़ावा दे रही है जिनका तकनीकी नियंत्रण अमरीकी दक्षिण कमान के हाथों में है। अभी तक तीन ठिकानों को चिह्नित किया गया है : ट्रिपल सीमा (अर्जेन्टीना, ब्राजील एवं पैराग्वे) टिएरा डेल फुएगो (उशुआइया) और न्यूक्वेन प्रांत/दोनों घटनाएं एक तीसरे: इस वर्ष राष्ट्रीय क्षेत्र पर स्थानीय सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास करने के लिए अमरीकी सैनिकों का आगमन से प्रबलित होती है। जैसा कि दोनों देशों के अधिकारियों ने घोषणा की है, ये अभ्यास 'सामूहिक विनाश के हथियारों की तस्करी के खिलाफ सूचना देने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं। विदेशी सैनिकों के आगमन के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुज्ञा की आवश्यकता होती है लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ऐसी अनुज्ञा के लिए निवेदन नहीं किया गया है।

इन घटनाओं के साथ घटनाओं की दूसरी श्रृंखला पर ध्यान देना आवश्यक है जिसने रिकॉर्ड समय में राष्ट्र राज्य की समष्टि आर्थिक नीतियों को बनाने की स्वायत्तता के समग्र नुकसान को उकसाया है। मैं यहां मैक्री सरकार द्वारा प्रदर्शित बाह्य हाइपर-ऋणात्मक नीति का उल्लेख करता हूँ। यहां दो मुख्य संकेतक अर्जेन्टीना के जीएनपी की तुलना में बाहरी ऋण का और लेनदारों के साथ किये गये प्रतिबद्धताओं की विशेषताओं का उद्विकास हैं। पूर्व के संबंध में यह देखना संभव है कि कैम्बिओस ने वित्तीय मूल्य के नये शासन के फ्रेमवर्क के अन्तर्गत राष्ट्रीय इतिहास में बाह्य ऋण की सबसे तीव्र वृद्धि को उकसाया है। किरचेर सरकारों (2003-2015) के तहत, राज्य आर्थिक नीतियों ने लेनदारों के साथ वार्ता के दौरान कड़ रुख अपनाते हुए बाह्य ऋणग्रस्तता को कम करने का लक्ष्य रखा है। इन वार्ताओं की सापेक्ष सफलता ने उत्पादक अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन की अनुमति दी है। काफी हद तक, इसने वित्तीय मूल्य के 1976-2001 के मॉडल के परित्याग की भी अनुमति दी है। दिसम्बर 2015 के बाद से, मैक्री सरकार वित्तीय मूल्य की व्यवस्था को पुनःस्थापित करने के प्रमुख उपाय के रूप में बाध्यकारी बाहरी ऋणग्रस्तता की तरफ लौटी है। जीएनपी और बाह्य सार्वजनिक ऋण का अनुपात 2011 के बाद से बढ़ रहा है, जब 1983 में लोकतंत्र की बहाली के बाद से इसने अपना न्यूनतम स्तर 14.2 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व किया। उस क्षण से, ऋण बढ़ने लगा और मैक्री के त्वरित हाइपर-ऋणग्रस्तता की नीतियों के तहत जून

2018 तक जीएनपी का 65.5 प्रतिशत तक पहुंच बहुत अधिका बढ़ गया। इस प्रकार, अर्जेन्टीना का ऋणग्रस्तता गुणांक रिकॉर्ड समय में निम्न से मुश्किल से प्रबंधन योग्य बन गया है। स्थानीय और विदेशी मुद्रा में कुल जारी ऋण लगभग 133 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर पहुंच गया है जिसने देश को 2016-18 की अवधि के लिए दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे बड़ा ऋण जारीकर्ता राज्य बना दिया है।

लेनदारों के साथ संबंधों के संबंध में, ऋणग्रस्तता के इस नये चक्र में मुख्य घटना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ सारे ऋण चुकाने के चौदह वर्ष उपरान्त अधीनता के लिंक को पुनः स्थापित करने का निर्णय है। आईएमएफ की तरफ वापसी स्टैण्डबाय ऋण के अनुरोध के द्वारा कार्यान्वित होती है। अर्जेन्टीना और आईएमएफ द्वारा हस्ताक्षरित पूर्व के स्टैण्डबाय ऋण की तुलना में इस विशाल ऋण (50 बिलियन अमरीकी डॉलर) की विशेषता यह है कि इस बार न सिर्फ कर और मौद्रिक लक्ष्य बल्कि मुद्रास्फीति की भी निगरानी की जायेगी। इस तरह मैक्री का राष्ट्रपति काल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रबंधन व्यवहारिक तौर पर आईएमएफ को सौंपता है। ऐसा करने में, यह आईएमएफ द्वारा निवेदित मुद्रावादी नवउदार समायोजन कार्यक्रम का कार्यकारी अंग बन जाता है।

घरेलू सैन्यीकरण और तीव्र हाइपर-ऋणग्रस्तता की नीतियां राष्ट्रीय संप्रभुता का अपरदन कर रही हैं और पूरे राष्ट्र में भारी प्रतिरोध और प्रदर्शनों को उकसा रही हैं। विरोधी ताकतों में सामाजिक कक्षाओं की एक व्यापक श्रेणी सम्मिलित है जो इस प्रतिगामी सामाजिक रूपांतरण से समाज से क्षतिग्रस्त या बहिष्कृत होते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिकरण के समर्थकों और वैश्वीकृत निजी समष्टि-विनियोजन के नये शासन के समर्थकों के बीच शक्ति सम्बन्ध परवर्ती के पक्ष में उल्लेखनीय रूप से असमान हैं, मध्यम अवधि में राष्ट्रीय राजनीतिक भविष्य अप्रत्याशित है। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि लोकतांत्रिक क्षरण की वर्तमान प्रक्रिया का सिर्फ वर्णन करना पर्याप्त नहीं है। मुद्रा विनियोजन और सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तन के नई सामाजिक सिद्धान्त में सम्मिलित लोकतंत्र के बहुआयामी परिपेक्ष्य से प्रघटना की व्याख्या करना है।

इस तरह का व्याख्यात्मक उपकरण हमें सामाजिक परिवर्तन के एक नये वाम कार्यक्रम, जो विनियोग के सामाजिक खेल जिसमें हम डूबे हैं को सम्बोधित करता है, को पुनःपरिभाषित करने की अनुमति देता है। इससे पहले कि लोकतंत्र के लिए बहुत देर हो जाए हमें इसे प्राप्त करना होगा। ■

सभी पत्राचार एस्टेबान टोरेस कास्टोनास को
<esteban.tc@conicet.gov.ar> पर प्रेषित करें।

> मिस्त्र की क्रांति से महिलाओं का विलोपन

एमी ऑस्टिन होल्मस, काहिरा में अमरीकी विश्वविद्यालय, मिस्त्र और हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. में विजिटिंग विद्वान

| फिलकर/लोखा | कुछ अधिकार सुरक्षित |



तहरीर चौक में बड़े पैमाने पर जन प्रतिरोध के प्रदर्शन से विस्मृत हो, अरब स्प्रिंग ने विद्रोह के अध्ययनों में नवीन रुचि उत्पन्न की है। वृहद साहित्य के बावजूद, महिलाएं अक्सर इन विद्रोहों में विलुप्त प्रतीत होती हैं। एच.ए. हेलियर की पुस्तक *ए रेवोल्युशन अनडन* मिस्त्र की क्रांति में 27 महत्वपूर्ण हस्तियों के शब्दकोष से प्रारम्भ होती है। शब्दकोष में 26 पुरुषों के साथ केवल एक महिला का उल्लेख किया गया है। फिलीप माफ़लेंट की *इजिप्ट : कन्टेस्टेड रेवोल्युशन* अपने आवरण पर एक महिला दिखाती है परन्तु उनके विश्लेषण में बहुत अधिक महिलाएं सम्मिलित नहीं हैं। अन्य विद्वान प्रमुख तौर पर महिलाओं को उत्पीड़न या हिंसा के पीड़ित के रूप में सम्मिलित करते हैं न कि ऐसे अग्रणी के रूप में जो विकास घटनाक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण हो। अरब स्प्रिंग पर अथाह साहित्य में महिलाओं को खोजने के लिए हमें लैंगिक अध्ययनों को समर्पित उपक्षेत्रों को खोजना होगा, क्योंकि वे विद्रोह के बारे में सामान्य अवलोकन प्रस्तुत करने का दावा करने वाली पुस्तकों में अक्सर अनुपस्थित होती हैं। 2008 से मिस्त्र में रह रही काहिरा की निवासी के रूप में मैंने महिलाओं को प्रत्येक प्रतिरोध, प्रत्येक हड़ताल, तकरीबन सभी घटनाओं में मैंने उन्हें उपस्थित देखा है। लेकिन मिस्त्र क्रांति के इतिहास से महिलाओं को मिटाया जा रहा है। भावी पीढ़ी यह मानेगी कि अरब स्प्रिंग जैसी घटनाओं में महिलाएं महत्वहीन कर्ता थीं। लेकिन यह सच्चाई से पूरी तरह से दूर है।

महिलाएं केवल महिला अधिकारों के लिए वकालत नहीं करती थी। मुबारक की तानाशाही के समय से उथल-पुथल के वर्षों तक, जब तक कि वर्तमान में राष्ट्रपति सीसी के नेतृत्व में शासन ने खुद को व्यवस्थित नहीं किया था, महिलाएं अक्सर मिस्त्र की क्रांतिकारी सक्रियता के अग्रभाग में थीं। 2005 में धोखाधड़ी को रोकने के प्रयासों में और मिस्त्र की सत्तावादी व्यवस्था में उत्तरदायित्व का तत्व सम्मिलित करने के प्रयासों में तीन महिलाओं ने एक समूह की स्थापना की जो राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों की निगरानी करता था। उन्होंने स्वयं को शैफ़ेनाम कहा जिसका अनुवाद है 'हम आपको देख रहे हैं'। संस्थापकों में से एक, बुथैना कमेल बाद में आधुनिक मिस्त्र के इतिहास में राष्ट्रपति पद के लिए लड़ने वाली प्रथम महिला बनी। क्रांति के पूर्व, मिस्त्र का नदीम केन्द्र यातना पीड़ितों का उपचार करने वाला एकमात्र समर्पित केन्द्र था और यह एक महिला : डा. एड़ा सीफ़ एल-दावला द्वारा स्थापित किया गया था। और वह वीडियो किसने बनाया जो 25 जनवरी 2011 के एक सप्ताह पूर्व वायरल हुआ, जिसने लाखों लोगों को सड़कों पर उतरने और प्रतिरोध करने के लिए लामबंद किया? वह भी एक महिला थी : 6 अप्रैल युवा आंदोलन की असमा महफौज।

मुबारक की बेदखली के बाद, देश पर डेढ़ वर्ष तक सैन्य बल की सर्वोच्च परिषद के रूप में जाने वाली सैन्य जनता ने शासन किया। जैसा कि मैंने अन्यत्र भी तर्क दिया है, क्रांति की सबसे अतिवादी



बुथैना कामेल (चित्र में), अज्जा सोलिमन, मोज्ज हसन, यारा सल्लम और फातमा रमादान उन महिलाओं में से कुछ हैं जो सिसी द्वारा अपने शासन को सुदृढ़ करने के प्रयासों से उत्पन्न बढ़ते दबावों के समक्ष लचीली रहती हैं। कॉपीराइट : एमी ऑस्टिन होल्मस।

मांगों में से एक सैन्य शासन की समाप्ति रही है। यह केवल सुधार या वृद्धिशील परिवर्तन या पद से एक तानाशाह को हटाने के बारे में नहीं है अपितु यह राज्य की संरचना में बुनियादी परिवर्तन की मांग का आह्वान था : 1952 में अपनी स्थापना के बाद से सैन्य शासन के अधीन राज्य में नागरिक शासन को प्रारम्भ करना। मिस्र की सेना सार्वभौम पुरुष शिलालेख पर आधारित है। इस प्रकार महिलाओं को देश की सबसे शक्तिशाली संस्था से बाहर रखा जाता है। यह कोई संयोग नहीं है कि इन सेना-विरोधी समूहों में अग्रणी कार्यकर्ताओं में से कई महिलाएं थीं। नो मिलिट्री ट्रायल्स ग्रुप ने नागरिकों को सैन्य ट्रायल्स के पराधीन रखने की रीति को समाप्त करने की मांग रखी। इस समूह के कुछ अग्रणी लोगों में शाहिरा अबू लील और मोना सीफ सम्मिलित थीं। एक अन्य समूह ने सेना द्वारा किये गये मानवाधिकार उल्लंघनों के वीडियो को सार्वजनिक स्थानों पर दिखाकर उन्हें अनावृत किया। यह समूह असकर काजबोन कहलाता है जिसका अर्थ है सैनिक झूठ बोलते हैं और सैली तोमा, एक कॅप्टिक ईसाई महिला इसकी सह-संस्थापक थीं।

यह अक्सर महिलाएं ही थीं जिन्होंने महिलाओं और पुरुषों दोनों पर होने वाली अकथनीय हिंसा पर बोलकर सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ा। यह समीरा इब्राहिम थीं जिन्होंने हिरासत में महिलाओं का कौमार्य परीक्षण करने की सैन्य परिपाटी पर चुप्पी तोड़ी। हेवा

मोरायफ, जो उस समय मिस्र की मानवाधिकार वॉच की कंटरी निदेशक थी, हेलियर शब्दकोष में सम्मिलित होने वाली एकमात्र महिला थीं। इन्होंने कौमार्य परीक्षण की परिपाटी को बंद करने के अभियान का नेतृत्व किया। महिलाओं ने पुरुष अधिकारों की वकालत करने में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। दलिया अब्देल हामिद, इजिप्शियन इनिशियेटिव फॉर पर्सनल राइट्स (इआईपीआर) में शोधकर्ता, मिस्र के अन्दर उन लोगों में से एक थीं जिन्होंने 2017 के पतझड़ में एलजीबीटीक्यू समुदाय पर क्रेकडाउन की निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने समलैंगिक समझे जाने वाले पुरुषों की जबरन गुदा परीक्षण की भी निंदा की।

मिस्र के विरोधी मीडिया परिदृश्य में भी महिलाएं सबसे आगे रही हैं। लीना अटल्लाह मादा मासर, एक समाचार वेबसाइट जिसे द गार्जियन ने 2015 में मिस्र में प्रेस की स्वतन्त्रता को जीवित रखने वाली के रूप में वर्णित किया था, की संस्थापक एवं प्रधान सम्पादक थीं। अपनी खतरनाक सच कहने की शैली के लिए मादा मासर 2017 में ब्लॉक होने वाली प्रथम वेबसाइटों में से एक थी और एक वर्ष के उपरान्त भी वे सेंसर हैं।

न्यूबियन कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी में कई प्रमुख महिलाएं हैं। फातमा इमाम ने संविधान मसौदा समिति में कार्य किया और वे मिस्र के संविधान में पहली बार न्यूबिया का उल्लेख करने में सफल रही। ब्लॉगर और शोधकर्ता के रूप में वे, संवेदनशील मुद्दे जिसमें सूडान की सीमा के साथ सेना द्वारा जब्त न्यूबियन भूमि सम्मिलित है, पर निरन्तर जागरूकता फैलाने का कार्य करती हैं। 2017 के बसन्त में सीहम उस्मान, असवान से एक युवा महिला, जनरल न्यूबियन यूनियन के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने के इरादे की घोषणा करने वाली प्रथम महिला थी। बाद में उन्हें गंभीर दबावों के तहत पीछे हटना पड़ा।

अंत में, मिस्र की सबसे प्रसिद्ध मानवाधिकार अधिवक्ता में से एक महिनोर अल मसरी हैं। वे सभी मिस्रवासियों के अधिकारों की रक्षा, जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड की 21 महिला समर्थक भी शामिल हैं, के लिये विख्यात है, यद्यपि वे ब्रदरहुड की मुखर आलोचक हैं। उन्होंने सीरियाई शरणार्थियों का भी बचाव किया और पुलिस थानों में उनके बगल में सोने के लिए जोर दिया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उन्हें यातना या दुर्व्यवहार का सामना न करना पड़े। 2014 में उन्हें लुडोविक ट्रोरियक्स मानवाधिकार पुरस्कार मिला; नेल्सन मंडेला को भी 1985 में यही पुरस्कार मिला था।

इस प्रकार की संक्षिप्त टिप्पणी इस विषय के साथ न्याय नहीं कर सकती है। इतनी सारी महिलाएं हैं कि सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है। नर्मिन आलम की वुमन एंड द इजिप्शियन रेवाल्यूशन अधिक विस्तृत विश्लेषण को देखने का एक स्थान है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यह दर्शाने में सफल हुई हूं कि महिलाएं सिर्फ महिला अधिकारों की ही वकालत नहीं करती थीं। वे वृहद संघर्ष का अभिन्न हिस्सा थीं। क्रांति के इतिहास से महिलाओं को मिटा देना, या उन्हें लैंगिक अध्ययन के क्षेत्र में स्थानांतरित कर देना, उन पितृसत्तात्मक संरचनाओं को कायम रखना है जिनके विरुद्ध वे प्रतिरोध कर रही हैं। ■

सभी पत्राचार एमी ऑस्टिन होल्मस को <holmes@aucegypt.edu> पर प्रेषित करें।

> वैश्विक शासन :

लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था के लिए एक संकल्पना?

पीटर वाहल, कार्यकारिणी बोर्ड सदस्य, विश्व अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी एवं विकास संघ (डब्ल्यूइडी), बर्लिन, और सह संस्थापक, अटैक जर्मनी, जर्मनी द्वारा



अर्बु द्वारा चित्रण।

19 90 के दशक में एक अवधारणा: वैश्विक शासन ने अपना कैरियर प्रारम्भ किया। इसने एक नये और अधिक लोकतांत्रिक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के साथ-साथ मानवीय चेहरे वाले वैश्वीकरण का वादा किया। इस अवधारणा का प्रक्षेपवक्र रोचक सबक सिखाता है।

सर्वप्रथम : शासन सरकार नहीं है। इसका फ्रेंच मूल शब्द *गोवर्नर* का अर्थ संचालन, निर्देशन, विनियमन है। वास्तविकता में, निम्नलिखित बिन्दु इस अवधारणा से जुड़े हैं :

- वैश्वीकरण की आर्थिक प्रक्रिया राजनैतिक विनियमन से बच गई है। यह नवउदारवाद की जीत के कारण है जो बाजारों, उदारीकरण, निजीकरण और अविनियमन के स्व-नियमन पर निर्भर है।
- वैश्विक ताप जैसी नई वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जिनका समाधान व्यक्तिगत राष्ट्र-राज्यों की क्षमता के परे है।
- सामूहिक सुरक्षा, हथियारों की दौड़, परमाणु अप्रसार इत्यादि जैसी पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को ताजे दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- औपचारिक और बाध्यकारी समझौतों, गैर बाध्यकारी मानक सेटिंग, स्वैच्छिक समझौतों और बहुपक्षीय नेटवर्क के मिश्रण के माध्यम से राजनैतिक विनियमन के नये स्वरूपों की आवश्यकता है जो मिलकर एक शासन का निर्माण करते हैं।
- इन सभी के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के कर्त्ताओं यानि कि सरकारें, बहुपक्षीय संस्थानों, व्यापार क्षेत्र और नागरिक समाज के मध्य एक नये प्रकार की अंतर्क्रिया की आवश्यकता है। समावेशन, सहयोग, संवाद, नेटवर्किंग और हितों का संतुलन मुख्य साधन है।

शीत युद्ध की समाप्ति के साथ इस अवधारणा के क्रियान्वयन का वास्तविक अवसर दिखाई दे रहा है। वैश्विक शासन युग चेतना से मिल गया और लोकप्रिय हो गया। 100 देशों से अधिक के प्रमुखों और नागरिक समाज की भारी भागीदारी के साथ 1992 में संयुक्त राष्ट्र के रियो सम्मेलन को इसके प्रतीक के रूप में देखा जा सकता

है। रियो “एकल विश्व” के वर्तान्त जो उदार विश्वव्यापीवाद और वामपंथी अंतरराष्ट्रीयवाद के साथ समान रूप से जुड़ सकते हैं, की सफलता का परिचायक थी।

यद्यपि, जल्दी ही मोहभंग हुआ। पांच वर्ष पश्चात पहले स्टॉकहोल्म सम्मेलन में पहले से ही यह स्पष्ट था कि नवउदार पूंजीवाद के वैश्वीकरण ने अपने वादे पूरे नहीं किये। समृद्धि की कोई बाढ़ नहीं थी जिसने छोटी नावों और बड़े स्टीमरों को समान रूप से बढ़ाया। इसके बजाय बहुत सारे हारने वाले पैदा हुए। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में थे — उन परिणामों के साथ जो हम आज उनके सभी आयामों में देखते हैं, जब कई हारने वाले चरम दक्षिणपंथ की ओर मुड़ गये हैं। जैसा 1999 में सियेटल विश्व व्यापार संगठन की बैठक में हुए शानदार विरोध ने इंगित किया अधिकाधिक लोगों ने वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू जिसमें सामाजिक साम्यता, पर्यावरण और लोकतंत्र के प्रति खतरा सम्मिलित है, को समझा।

दूसरे शब्दों में पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था की गतिशीलता प्रबल हुई। 2008 में यह विश्वास कि वित्तीय बाजार दक्ष होंगे और स्वयं का नियमन कर सकेंगे, निश्चित तौर पर मिथक साबित हुआ। वित्तीय पूंजीवाद अनियन्त्रित हो गया जिसके कारण विश्वव्यापी मंदी के बाद का सबसे बड़ा वित्तीय संकट पैदा हुआ। वैश्विक शासन प्रक्रिया को बदलने की बात तो छोड़ इसे प्रभावित करने में भी सक्षम सिद्ध नहीं हुआ।

लेकिन ऐसा केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं था कि वैश्विक शासन सफल नहीं हो पाया। वैश्विक शासन की भावना अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों में भी कार्य नहीं करी। अतः येलत्सिन के रूस के खिलाफ 1997 में नाटो का पूर्व में विस्तार किया गया। जब 1999 में नाटो ने पूर्व यूगोस्लाविया में संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के बिना युद्ध प्रारम्भ किया, एकतरफा शक्ति राजनीति के कृत्यों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघनों की एक पूरी शृंखला का सूत्रपात हुआ। यह 9/11 के बाद “आतंक पर युद्ध”, वैश्विक “इच्छुकों के गठबंधन” के साथ इराक पर हमला, 2008 में नाटो की ढाल के तहत कोसोवो की एकपक्षीय आजादी और 2011 में लीबिया में सत्ता परिवर्तन के साथ जारी रहा। यह सभी वैश्विक शासन के दृष्टिकोण के विपरीत हैं।

इस पृष्ठभूमि के साथ, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जवाबी प्रतिक्रियाएं उभरीं। विशेष रूप से रूस और उत्तरोत्तर चीन शीत युद्ध पश्चात व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित हुए। यह सिर्फ एक अस्थायी घटना नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के गहन रूप से चलने वाले विवर्तनिक रूपांतरणों में स्थित है। हम अब बहुकेन्द्रीय विश्व व्यवस्था में परिवर्तन के साक्षी हैं। इसकी बुनियादी विशेषता महाशक्ति के रूप में चीन का उभार, रूसी राज्य-पूंजीवाद की बड़ी शक्ति के रूप में वापसी, पृथ्वी के आर्थिक केन्द्र के गुरुत्वाकर्षण का एशिया की तरफ स्थानान्तरण और अमरीकी एवं

पश्चिमी प्रभुत्व का क्षरण (सापेक्ष) है।

नवागुन्तक परिवर्तनीय रचनाओं और स्वयं के मध्य विभिन्न मुद्दे आधारित गठजोड़ों जैसे शंघाई सहयोग संगठन या ब्रिक्स पर संगठित होते हैं। वे अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के विकल्प के रूप में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की स्थापना करते हैं और न्यू सिल्क रोड जैसे विशालकाय आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की परिकल्पना करते हैं। यह विश्व अर्थव्यवस्था में समानांतर संरचनाओं के उभार जैसे स्विफ्ट के विकल्प हेतु चीन और रूस द्वारा विकसित वैश्विक वित्त की इलेक्ट्रॉनिक तंत्रिका प्रणाली एवं मास्टर कार्ड, वीजा और अमेरिकन एक्सप्रेस के वैश्विक एकाधिकार को तोड़ने वाला स्वयं की एक क्रेडिट कार्ड व्यवस्था द्वारा संगत पाता है। व्यापार समझौते उत्तरोत्तर द्विपक्षीय रूप से सम्मत समाशोधन इकाइयों के माध्यम से अमरीकी डॉलर को प्रतिस्थापित कर अमरीकी अधिपत्य के एक स्तम्भ को कमजोर करते हैं। दूसरे शब्दों में, वैश्वीकरण के प्रति एक वैकल्पिक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो प्रतिकारी शक्ति के विचार पर आधारित है। एक तत्व एक प्रकार का ‘चयनात्मक अ-वैश्वीकरण’ है।

बेशक, आगामी विश्वव्यवस्था नये जोखिमों के साथ आती है। ऐसी परिस्थितियों में हमेशा नवागुन्तकों और लंबे समय से स्थापित खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और अस्थिरता पैदा करती है। ट्रम्प प्रशासन के आगमन और “अमरीका को फिर से महान बनाने” के एकपक्षवाद के जोखिमों ने एक नई गुणवत्ता हासिल की है।

यदि हम पूछते हैं कि वैश्विक शासन क्यों नहीं चला, तो मुख्य कारण हैं :

- वैश्विक पूंजीवाद की राजनैतिक अर्थव्यवस्था में शक्ति सम्बन्धों के प्रति दृष्टिहीनता या जैसा मार्क्स कहते, आर्थिक सम्बन्धों की निशब्द हिंसा
- अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में शक्ति सम्बन्धों के प्रति दृष्टिहीनता; और
- पूंजीवादी समाज के संगठन के लिए अभी भी प्रभावी फ्रेमवर्क के रूप में राष्ट्र-राज्य की जड़ता का कमतर आकलन

वैश्विक शासन प्रारम्भ से ही अवधारणा के रूप में काफी आदर्शवादी है। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विचार अभी भी मान्य है और इसे विवेचनात्मक सामाजिक सिद्धान्त और आचरण द्वारा छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन यदि व्यवहार्य विकल्पों को विकसित करना है तो कौन किसके साथ सहयोग कर रहा है के साथ किसके खिलाफ और शक्ति संतुलन के वास्तविक आकलन की आवश्यकता होगी। ■

सभी पत्राचार पीटर वाहल को <peter.wahl@weed-online.org> पर प्रेषित करें।

> एक उत्कृष्ट प्रकृति के बुद्धिजीवी

निकोलास लिंग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सेन मारकोज, पेरू



| 2015 में अनीबाल क्विजानो | क्रिएटिव कामन्स |

अ अनीबाल क्विजानो पेरू एवं लेटिन अमेरिका के एक उत्कृष्ट प्रकृति के आलोचनात्मक बुद्धिजीवी रहे हैं, उन्होंने अपने सिद्धान्तों पर अडिग रह कर सदैव भूमिका निर्वाह किया। 1960 एवं 1970 के दशक में वे जब समाजशास्त्री के रूप में उभरे उस समय यथास्थितिवाद की आलोचना अपने चरम

पर थी। क्विजानो ने मार्क्सवाद—लेनिनवाद की प्रभावी आवाज को नहीं छोड़ा जो कि चमकदार रास्ते के बीच बर्बरता के रूप में प्रस्तुत की जा रही थी। 1990 के दशक में विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारों एवं प्रभाव के कारण कुछ सामाजिक श्रेणियों के निम्नवर्गीकरण की उनके (क्विजानो) द्वारा भर्त्सना ने क्विजानो के

उस योगदान को महत्वपूर्ण बना दिया जो कि समकालीन पेरू एवं व्यापक रूप में लेटिन अमेरिका में कार्य सम्बन्धी प्रक्रियाओं के विश्लेषण से जुड़ा था।

क्विजानो ने मुख्यतः अपने गृह क्षेत्र में स्थित सेन मारकोस विश्वविद्यालय, लीगा, पेरू एवं लेटिन अमेरिका तथा अमेरिका ने अन्य अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर तथा अनुसंधानकर्ता के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। 1970 के दशक में एक शोध पत्रिका 'सोसायडाड पॉलिटिका' के माध्यम से क्युइजानो ने प्रत्यक्ष राजनीति में थोड़े समय के लिए प्रवेश किया परिणामस्वरूप जुआन वेलास्को अलवाराडो के सैन्य शासन ने उन्हें निष्कासित कर मैक्सिको भेज दिया। इस घटना ने क्विजानो को एक ऐसा सार्वजनिक बुद्धिजीवी बना दिया जो पेरू एवं लेटिन अमेरिका की जनता के संघर्ष के साथ प्रतिबद्ध था। उन्होंने अपने जीवन को उस रास्ते को समझने के लिए समर्पित किया जिसके अन्तर्गत यह देखा जाए कि सामाजिक व राजनीतिक प्रक्रियाओं का वह स्वरूप क्या है जो हमारे समाज को एक आकार देती है और वे तरीके खोजे जाए जिनसे हमारे समाज में रूपान्तरण हो सके।

क्विजानो के योगदान का पहला पक्ष ज्ञान मीमांसा से जुड़ा है। क्विजानो ने इस क्षेत्र में क्रियाशील सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण हेतु 'दक्षिण से सम्बद्ध' दृष्टिकोण को प्रयुक्त किया इस दृष्टिकोण को विकसित करते हुए क्विजानो ने प्रकार्यात्मक समाजशास्त्र में प्रयुक्त परम्परा/आधुनिकता विभाजन को अस्वीकारा तथा एतिहासिक-संरचनात्मक विषमतरूपता को मुख्य विवेचना का केन्द्र बनाया। उन्होंने उत्पादन के स्वरूपों के उस समुच्चय को समझा जो लेटिन अमेरिकन

समाजों में भी विद्यमान हैं तथा एक प्रघटना के रूप में उस पूंजी के चारों ओर संगठित है जो न केवल राष्ट्रीय अपितु राष्ट्र के परे हैं और साथ ही वह वैश्विक भी हैं।

क्विजानो इस ज्ञान मीमांसा के द्वारा लेटिन अमेरिका की निर्भरता की स्थिति को परखते हैं। हालांकि क्विजानो इसे कथित 'निर्भरता सिद्धान्त' कहने से इन्कार करते हैं। स्पष्ट है कि क्विजानो उस विवेचन का भाग हैं जिसका आरम्भ राउल प्रेबिश एवं सीईपीएएल (अंग्रेजी में इसे ईसीएलएसी कहा जाता है) ने 1950 के दशक में किया इसे कार्डोसो एवं फैलाटो ने निरन्तरता प्रदान की और अन्ततः 1960 एवं 1970 के दशक में रुयो माउरो मैरिनी ने व्यापक रूप दिया। क्विजानो ने उस दौर में विभिन्न योगदानों के द्वारा स्वयं को उस बहस में शामिल किया जो नगर नियोजन से सम्बद्ध थीं और श्रम शक्ति पर केन्द्रित थीं। यह योगदान एवं बहस के रूप में हस्तक्षेप तीन दशकों के उपरान्त लेटिन अमेरिका में एक वैश्विक विशेषता का रूप लेता है जिसमें शक्ति की औपनिवेशिकता की अवधारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान ले लेती है।

लेकिन क्विजानो लेटिन अमेरिकन अस्मिता के विषय में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। पेरू में 1970 के दशक के प्रारम्भ में 'चोलिफिकेशन' की प्रक्रिया में योगदान साथ ही जोज कार्लोस मैरिआटग्यू जो कि 1930 के दशक के महान आलोचनात्मक मार्क्सवादी विचारक थे, के लेखन व विचारों को पुनःजीवित करना इसमें सम्मिलित है। मैरिआटग्यू की सहानुभूति देशज लोगों के संघर्ष के प्रति थी। साथ ही 'कुएन विविर' की अवधारणा पर क्विजानो ने योगदान किया यह अवधारणा हाल के विभिन्न नृवंशीय

आन्दोलनों से सम्बद्ध है।

क्विजानो का अस्मिता के प्रश्न से सम्बद्ध योगदान प्रजाति की अवधारणा पर आधारित है। क्विजानो की दृष्टि में यह अवधारणा यूरोपीय औपनिवेशीकरण अर्थात् दूसरे शब्दों में अमेरिका से उत्पन्न हुई है। और शीघ्र ही क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक संस्तरण के वर्गीकरण का केन्द्रीय तत्व बन गयी। अस्मिता की अवधारणा चारों तरफ प्रजाति से जुड़ी है साथ ही प्रभुत्व का अवयव भी प्रजाति केन्द्रित है। आश्रितता के साथ प्रजाति की अवधारणा शक्ति की औपनिवेशिकता की अवधारणा की रचना करती है। क्युइजानो के अनुसार शक्ति की औपनिवेशिकता का सम्बन्ध बाह्य प्रभुत्व से है। इसमें एक उपनिवेश या नव्य उपनिवेश के ऊपर एक शासक का प्रभुत्व है साथ ही इसमें एक आन्तरिक प्रभुत्व भी है जिसके अन्तर्गत समाज के शेष भाग पर शासक अभिजन का प्रभुत्व है जिसमें विशेषतः विभेदीकृत प्रजातीय रचना योगदान करती है। परिणामस्वरूप शक्ति की औपनिवेशिकता एक सुसंगत राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय राज्यों के लेटिन अमेरिका में निर्माण के सम्मुख मुख्य चुनौती बन जाती है।

हम उपरोक्त विवेचन की दृष्टि में कह सकते हैं कि अनीबाल क्विजानो की सैद्धान्तिक सृजनशीलता एवं स्वयं के क्षेत्र में स्वायत्तशासी सामाजिक चिन्तन की परम्पराओं में स्थिति उन्हें पेरू एवं वृहद महाद्वीप में समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रमुख विचारक के रूप में स्थापित करती है। ■

सभी पत्राचार निकोलास लिंच को
<nicolasylynch54@gmail.com>
पर प्रेषित करें।

> एक योद्धा की खुशी

रेक्वल सोसा एलिजागा, नेशनल आटोनौमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको

हजारों युद्धों के नायक अनीबाल क्विजानो को उस समय सुखद आश्चर्य हुआ जब यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्टा रिका ने उन्हें डाक्ट्रेट की मानद उपाधि से विभूषित किया। उन्हें और भी सुखद आश्चर्य हुआ जब श्रोताओं से पूरी तरह भरे सभागार में उन्हें श्रोताओं ने करतल ध्वनि द्वारा खड़े होकर स्वागत की रस्म अदा की। क्विजानो ने विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों/बुद्धिजीवियों को धन्यवाद दिया कि वे 'उनके द्वारा दिये गये अकादमिक एवं क्रिया-केन्द्रित योगदान' से परिचित हैं। क्विजानो ने इसलिए भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने जो वैचारिक सहभागिता अब तक की है वह उनकी जीवन पद्धति की मान्यता का परिणाम है। यह जीवन पद्धति 'कोई क्या लिखता है और क्या सोचता है' के अर्थ पूर्ण पक्ष पर आधारित है। क्विजानो ने अत्यन्त शालीनता एवं सरलता के साथ अपने जीवन मन्त्र को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार 'अन्तः जीवन एवं विरुद्ध जीवन को मिलाकर जीवन जियें' और इस मन्त्र में अपने वैचारिक पक्ष को भी सम्मिलित किया। इस के अनुसार 'एक ऐसे विश्व में, जहां शक्ति, शोषण एवं हिंसा एक साथ सम्मिलित हैं, जीवन जीने का (अन्तः जीवन एवं विरुद्ध जीवन का समन्वय) कोई अन्य दूसरा तरीका नहीं है।'

मैं अनेक वर्षों पूर्व अनीबाल क्विजानो से मिला था। मुझे याद है, मैं उनसे अपने गृह-देश में मिला था। सन् 1970 के दशक के मध्य में क्विजानो यहां निर्वासन का जीवन व्यतीत करने आये थे। उनके साम्राज्यवाद विरोधी चिन्तन एवं इससे जुड़ा संघर्ष, जमीनी सामाजिक ज्ञान की आवश्यकता से जुड़ी उनकी प्रतिबद्धता, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के लोगों की आवश्यकता एवं उनके संघर्ष से उनका लगाव, महिलाओं, युवा, देशज जनसंख्या, प्रवासी, विस्थापित लोग तथा शरणार्थी जो समूचे विश्व में फैले हैं के संघर्षों के साथ सभानुभूति अनीबाल क्विजानो की वैचारिकी व सक्रियता को निर्मित करती है। इस समग्रता के साथ उन्होंने अनेक स्थानों की

“उनके जीवन का मन्त्र था: अन्तः जीवन एवं विरुद्ध जीवन को मिलाकर जियें”

यात्रा की उन्हें मान्यता मिली तथा उनका स्वागत किया गया वे ऐसे अनेक स्थानों पर गये जहां बुद्धिजीवी सामान्यतः नहीं जाते।

असहमति के उनके लम्बे इतिहास ने उन्हें बाध्य किया कि वे जब अपने देश पेरू में सन् 1990 के दशक के प्रारम्भ में लौटे तो उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ सेन मारकोस में विभागाध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। उस समय के तानाशाह फ्यूजिमोरी ने सेना को आदेश दिया था कि वह विश्वविद्यालय को अपने नियन्त्रण में ले लें। एक बार फिर क्विजानो को बिघंमटान विश्वविद्यालय में शरणार्थी के रूप में आना पड़ा तत्पश्चात पेरिस एवं अन्य स्थानों पर उन्हें शरण लेनी पड़ी। वर्तमान शताब्दी के दूसरे दशक के प्रारम्भ में अन्ततः पेरू में रिकार्डो पालमा विश्वविद्यालय ने उन्हें अपने यहां आमन्त्रित किया जहां उन्होंने अपने संघर्ष के आखिरी वर्ष व्यतीत किये। उनका समूचा जीवन अकादमिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के अनवरत संचालन एवं उनमें सहभागिता में बीता। वे लगातार लोगों के समूहों के सम्पर्क में रहे वे हमेशा उनकी गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर भाग लेते थे और उनके साथ अपनी सघन एकजुटता प्रदर्शित करते थे। विभिन्न विषय विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने शानदार लेख लिखे। इन विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों ने वर्ल्ड सोशल फोरम में भाग लिया था। इनमें सैमुअल वैलेस्ट्रीन एवं पावोलो गोन्जालाज कासानोवा, जो उनके घनिष्ठ मित्र थे, भी सम्मिलित थे।

शक्ति की औपनिवेशिकता सम्बन्धी उनकी दृष्टि ने उन्हें विश्व के प्रत्येक भाग में मान्यता प्रदान की। यह दृष्टि उनके राजनीतिक एवं अकादमिक संघर्ष का परिणाम थी। वास्तव में मेरे विचार में यह दृष्टि एक नैतिक आवाज है और एक ऐसी मांग है जो प्रत्येक की चेतना एवं शिष्ट जीवन हेतु अनिवार्य है। यह दृष्टि बताती है

कि नागरिकों को किसी भी शक्ति, चाहे वह विदेशी हो अथवा घरेलू, की अधीनता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसी आवाज है जो उस ज्ञान, उपकरण एवं प्रभावी हथियार के समन्वय को बताती है जिससे रूपान्तरण का सही मार्ग तलाशा जा सके। यह मार्ग वंचित, हाशिये के लोग, बहिष्कृत एवं शोषण व दमन के शिकार समूहों के लिए हितकर होगा और विश्वभर में ऐसे समूहों को प्रेरणा देगा।

अपने पूर्ववर्ती चिन्तकों एमी सीजार, फ्रैन्ज फैनान विशेषतः जोस कार्लोस मैरियाटिगुइ की भांति अनीबाल क्विजानो ने अपने योगदान द्वारा एक उपयुक्त/ईमानदार ऐतिहासिक अर्थ निर्मित किया जो कि इस अनवरत प्रस्तुति पर आधारित था कि यही वह रास्ता है जिस पर चलते हुए विश्व में सोलहवीं शताब्दी से रूपान्तरण की प्रक्रिया चल रही है। प्रजातिवाद एवं दासता को पूंजीवादी विकास की आर्थिक शक्तियों में बदल दिया गया है। शोषण एवं अलगाव के इस चक्र को न केवल समझना है अपितु इसकी समाप्ति करनी है जो अब तक नहीं हुई है। यही विचार एवं प्रयास क्विजानो के जीवन का ध्येय बना। विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों एवं समारोहों से दूर, पृथक्करण अथवा अपूर्णता के दर्द की अनुभूति के बिना, निजी, व्यक्तिगत एवं राजनीतिक अत्याचार के दर्द की अनुभूति के बिना क्विजानो का जीवन एक योद्धा की खुशी की तरह था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक लक्ष्य हेतु संघर्षरत हैं। यह लक्ष्य उनके जीवन से भी बड़ा है। उन्होंने जीवन, सौन्दर्य, परिवार एवं मित्रों के साथ प्रसन्नता का जीवन जिया जिसमें गहनता थी। इस कारण उन्होंने एक लम्बा जीवन भी जिया। हमें एक उदाहरण के रूप में उनका सम्मान करना चाहिए। उनमें प्रतिबद्धता एवं एक जुटता का अनुकरणीय भाव था। ■

> पोस्ट नस्लीय

निर्धनता की मुख्य विशेषताएं

जोशुआ बुडलेण्डर, मैसाचुसेट्स एम्हेस्ट विश्वविद्यालय, यू.एस.ए.



1992 में डाबोस में विश्व अर्थव्यवस्था मंच पर फ्रेडरिक विलेम दे क्लर्क और नेल्सन मंडेला।
कापीराइट : वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम।

30

यह ध्यान देने योग्य बन गया है कि जहां 1994 में नस्लवाद के अंत के बाद दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत बहुसंख्यकों ने राजनैतिक स्वतन्त्रता हासिल की, वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रताएं अपूर्ण रही हैं। इस बात को यद्यपि अक्सर सामान्य शब्दों में या विशिष्ट घटनाओं के विशेष अध्ययन के संदर्भ में कहा जाता है। यहां मैं, दक्षिण अफ्रीका में व्यापक रूप से फैली आर्थिक निर्धनता के सम्बन्ध में क्या परिवर्तित हुआ या क्या नहीं के प्रश्न पर व्यापक सबूत एकत्रित करता हूँ।

> पोस्ट-नस्लीय दक्षिण अफ्रीका में निर्धनता की घटनाएं

पहला और सबसे मूलभूत तर्क है कि पोस्ट-नस्लीय दक्षिण अफ्रीका में 'आय से निर्धन' रूप में प्रमुख रूप से वर्णित जनसंख्या में शायद ही कोई परिवर्तन हुआ है। विशिष्ट संख्या प्रयोग में ली जाने वाली निर्धनता रेखा पर निर्भर है लेकिन सामान्य तौर पर 50 फीसदी से 65 फीसदी आबादी "निर्धन" कहलाती है। ये समग्र संख्या 1994 से सिर्फ कुछ प्रतिशत ही बेहतर हुई है। जनगणना वर्गीकरण में निर्धनता का निरूपण अभी भी तीव्र रूप से नस्लीय

आधार पर है, जिसमें 73 फीसदी अश्वेत अफ्रीकी, 48 फीसदी/ 12 फीसदी भारतीय/एशियाई और 2 फीसदी अश्वेत सबसे नवीनतम निर्धनता रेखा के नीचे हैं।

निर्धनता में जो थोड़ी बहुत कमी हुई है वह अधिकांशतः पोस्ट नस्लीय 'सामाजिक अनुदान' में बड़े पैमाने पर सरकारी विस्तार के फलस्वरूप आई है निर्धन की कुछ श्रेणियों को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक निर्धन 40 फीसदी परिवारों के लिए, सामाजिक अनुदान अब आमतौर पर कुल घरेलू आय का आधे से भी अधिक भाग है।

पोस्ट नस्लीय अवधि में भौतिक परिस्थितियों में अन्य प्रमुख सुधार भौतिक/वस्तु वंचन के कुछ गैर-आय पहलुओं से सम्बन्धित हैं। बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों ने नाटकीय रूप से जल, बिजली, और स्कूली शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि की है जबकि कुपोषण और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। इन क्षेत्रों में सुधार आंशिक रूप से चरम रंगभेद-युग में उपेक्षा और वंचितता को प्रतिबिंबित करते हैं। लेकिन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति निर्विवाद है।

>>

इन भौतिक सुधारों के बावजूद यद्यपि निर्धनता ग्रामीण इलाकों में, विशेष तौर पर जो रंगभेद युग 'होमलेण्ड्स' कहलाते थे अभी भी व्यापक रूप से बनी हुई है। जब दक्षिण अफ्रीका में निर्धनता को मानचित्रित करने के लिए वंचना के सचकांकों का प्रयोग किया जाता है, उच्चतम वंचना वाले क्षेत्र अक्सर पूर्व के होमलैण्ड सीमाओं को ट्रेस करते हैं और इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका में पुनर्गठित करने के बाद से दो दशकों से अधिक की स्थायी विरासत का प्रदर्शन करते हैं।

बेशक निर्धनता केवल ग्रामीण समस्या नहीं है। अनौपचारिक नगरीय क्षेत्रों के परिवारों का अपने ग्रामीण समकक्ष परिवारों की तुलना में निर्धनता से बाहर निकलने की संभावना थोड़ी बेहतर है। लेकिन फिर भी उन्हें काफी संरचनात्मक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। रंगभेद काल की योजनाओं ने शहरी अश्वेत श्रमिकों और उनके परिवारों को दूर दराज की शहरी परिधि पर जाने के लिए दबाव डाला। यहां वे अपनी नौकरियों से और सुविकसित नगरीय केन्द्रों से दूर हो गये। रंगभेद पश्चात यह पैटर्न निजी सम्पत्ति अधिकारों और सरकार नीति द्वारा संरक्षण से मजबूती से जुड़ा है जिसने सस्ती शहरी सीमान्त भूमि पर राज्य अनुदान वाले आवास का निर्माण किया है।

दक्षिण अफ्रीकी श्रमिकों को लम्बी यात्रा करनी पड़ती है और उच्च यात्रा लागत का भुगतान करना पड़ता है; प्रभावी रूप से इन श्रमिकों की मजदूरी का लगभग 40% यातायात कर के रूप में देना पड़ता है। यह स्थिति कम सेवा वाले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था द्वारा अधिक बढ़ाई गई। "नस्लीय शहर" भी परिधि पर निवास करने वाले निवासियों के लिए रोजगार तलाशना कठिन बनाते हैं।

> बहुत कम नौकरियां और बहुत कम मजदूरी

दक्षिण अफ्रीका का असफल श्रम बाजार अधिक व्यापक रूप से रंगभेद पश्चात की निर्धनता की जड़ता के केन्द्र में है। बेरोजगारी मीडिया और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करती है जो उसकी अस्वाभाविक उच्च स्तर को देखते हुए आश्चर्यजनक नहीं है। बेरोजगारी की वैश्विक संकीर्ण परिभाषा के अनुसार, दक्षिण अफ्रीकी बेरोजगारी की दर 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य है। व्यापक परिभाषा के अनुसार, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में अधिक सही है, बेरोजगारी लगभग 40 प्रतिशत के आस-पास झूलती है।

इस पैमाने पर सामूहिक बेरोजगारी को स्पष्ट रूप से कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि इसने अक्सर दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित न्यून मजदूरी से ध्यान हटाया है। एकल कमाने वाले दक्षिण अफ्रीकी परिवारों में से आधे हाल ही में की गई गणना में निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं (बिना कमाई वाले 88% परिवार इस निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं) जहां वितरण के शीर्ष पर मजदूरी बढ़ी है लेकिन 1994 से वास्तविक रूप से औसत मजदूरी स्थिर रही है। जनसांख्यिकीय सबूत अधिकाधिक दर्शाते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी कामगार अक्सर अपनी नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी मजदूरी इन नौकरियों में सम्मिलित भौतिक और मनोवैज्ञानिक लागतों (जैसे आवागमन की लागत और अपमान के अनुभव इत्यादि) के मिश्रण को उचित ठहराने के लिए बहुत कम होती है। चाहे उसका मतलब बेरोजगार रहना ही क्यों न हो।

उच्च बेरोजगारी और कम मजदूरी के कारण क्या हैं? एक पसंदीदा व्याख्या है खराब गुणवत्ता की शिक्षा। इस सिद्धान्त के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका "कौशल विसंगति" का अनुभव कर रहा है जहां नियोक्ताओं को उच्च कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है लेकिन बुनियादी शिक्षा प्रणाली ऐसे कामगारों के उत्पाद के लिए निष्क्रिय है। निश्चित रूप से यह सच है कि नामांकन की दरों में वृद्धि के बावजूद, दक्षिण अफ्रीकी बुनियादी शिक्षा अप्रत्याशित संकट की स्थिति में है। उदाहरण के लिए कक्षा 4 के हर 10 में से 8 विद्यार्थी अर्थ पढ़ने में असमर्थ हैं। लेकिन शिक्षा पूरी कहानी की व्याख्या नहीं कर सकती है।

एक मुद्दा जिसे पहचाना जाना चाहिए, वह है निजी क्षेत्रों में श्रम की मांग में कमी। रंगभेद के अंत और 1980 के दशक के उत्तरार्ध में और 1990 के दशक के प्रारंभ में प्रवाह नियंत्रण के पतन के साथ, श्रम की आपूर्ति नाटकीय रूप से बढ़ी क्योंकि पहले होमलैण्ड्स तक सीमित दक्षिण अफ्रीकी अब शहरों में बेहतर जीवन तलाश कर सकते थे। इस अवधि के दौरान श्रम की मांग आपूर्ति में वृद्धि के साथ नहीं चल पाई जिसने संरचनात्मक बेरोजगारी अंतर को बढ़ाया जो अब तक जारी है। जहां व्यापारी अक्सर शिकायत करते हैं कि दुष्कर नियमन भर्ती को जोखिम में डालता है, प्रशासनिक आंकड़े दक्षिण अफ्रीकी निजी क्षेत्र कामगारों के मंथन के असाधारण उच्च स्तर को दिखाते हैं। उसी समय श्रम की मांग में कमी को भी निजी क्षेत्र के नियत निवेश के निम्न स्तर से भी जोड़ा जा सकता है। उत्पादक निवेश के बजाए अधिग्रहण द्वारा व्यवसाय विस्तार की पछेती नस्लीय पद्धतियों को कार्पोरेट अनबंडलिंग, बड़े शेरधारकों को भुगतान और विदेशों में पूंजी के स्थानांतरण के बदले दिया जाता है लेकिन घरेलू उत्पादक निवेश में रुचि में कमी बनी रहती है।

> अस्थिरता और गतिशील निर्धनता

1994 से दक्षिण अफ्रीका ने आउटसोर्सिंग और 'श्रम ब्रोकिंग' के वैश्विक रुझानों का पालन किया है जिसने कार्य के अनिश्चित स्वरूपों में वृद्धि की है। दक्षिण अफ्रीकी निर्धनता के गतिशील विश्लेषण से पता चलता है कि गैर-निर्धन परिवारों का 40 प्रतिशत आघात योग्य है — उन्हें भविष्य में निर्धनता में आने का गंभीर जोखिम है — जबकि 80 प्रतिशत निर्धन परिवारों को निर्धनता से निकलने की नगण्य संभावनाओं के कारण 'गंभीर रूप से निर्धन' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

यह कथन कि वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता दक्षिण अफ्रीका में अवास्तविक है एक अच्छे कारण से सही प्रतीत होती है : वास्तविकता स्वयं बोलती है। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में जो अधिक विचारणीय बिन्दु है वह है इस समस्या को सम्बोधित करने के लिए हमारे साथ विद्यमान रंगभेद अर्थव्यवस्था का बुनियादी पुनर्गठन किस सीमा तक संभव है। इसमें कोई शक नहीं है कि सामाजिक अनुदानों और बुनियादी सेवाओं का अग्रिम विस्तार प्रगतिशील कार्यवाही का नेतृत्व करेगा। यद्यपि दक्षिण अफ्रीकी श्रम बाजार ही अर्थव्यवस्था की असफलता के केन्द्र में हैं और यदि नस्लीय मार्ग निर्भरता को हिलाना है तो इसी क्षेत्र में हस्तक्षेपों को लक्षित करने की आवश्यकता है। ■

सभी पत्राचार जोशुआ बुडलैण्डर को <jbudlender@umass.edu> पर प्रेषित करें।

> बेल-आउट के उपरान्त का कल्याणः यूनान में निर्धनता का नया प्रारूप

वेसिलिस एरापोग्लू, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिट, ग्रीस (यूनान)



खाली घरों पर निर्धनता अंकित है, जबकि सड़कों पर सोना कई लोगों के लिए एक दैनिक यथार्थ बन गया है।
क्रेडिट: वेसिलिस एरापोग्लू

कठोर मितव्ययता के आठ वर्ष के उपरान्त यूनान की सरकार ने अनुमान लगाया कि आर्थिक संकट के उबार के उपरान्त का दौर (बेल-आउट एरा) प्रारम्भ हो चुका है और उसने 'भविष्य के लिए वृद्धि-रणनीति' को बढ़ावा देना प्रारम्भ किया। यह योजना यूरो समूह, यूरोपियन कमीशन एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वार्ता व समझौतों के उपरान्त बनायी गयी जिसमें राजकोषीय देखभाल/निगरानी के व्यापक स्वरूपों पर विचार विमर्श के नतीजे सम्मिलित थे और विभिन्न वित्तीय सहायता कार्यक्रमों से अलग होने के निर्णय सम्मिलित थे। यह योजना सुधारों पर यूनान के स्वामित्व को रेखांकित करती थी एवं 'उत्तम एवं समावेशी वृद्धि' की प्राथमिकताओं के एजेण्डा को सम्मिलित करने का प्रयास करती थी।

यहां प्रस्तुत आलेख मेरे द्वारा यूनान के नगरों में निर्धनता से सम्बद्ध शोध कार्य के निष्कर्षों पर आधारित है। यह आलेख एक वृहद समय-स्थान प्रारूप के अन्तर्गत योजना के उसे दावे का मूल्यांकन करता है जिसमें नीतियों की सफलता के तर्क दिये गये हैं जबकि मेरे शोध के निष्कर्ष इन दावों के विपरीत हैं। आर्थिक संकट के उबार (बेल-आउट) के उपरान्त के विमर्श उन विशिष्ट क्षणों को अभिव्यक्त करते हैं जो कल्याण के उपरान्त (पोस्ट-वैलफेयर) के दौर के संकेतक

हैं। ये संकेतक सामाजिक प्रावधानों के विकेन्द्रीकरण की रणनीति, वैश्विक स्तर पर अनेक नगरों में अलग-अलग दरों पर हो रही प्रगति, यूरोपियन कमीशन द्वारा श्रम बाजार में सुधार की चर्चा करते हुए नियमों के उदारीकरण अर्थात कानूनों का विनियमन एवं सामाजिक अधिकारों (एनटाइटिलमैण्ट) के सिकुड़ते ढाँचे को व्यक्त करते हैं। उत्तर-कल्याण अर्थात कल्याण के उपरान्त (पोस्ट-वैलफेयर) में स्थानीय राज्य, बाजार एवं नागरिकीय समाज के मध्य के सम्बन्धों को पुर्नआकार (रीशेप) इस दृष्टि से दिया जाता है कि वह सामाजिक सुरक्षा जाल एवं सामाजिक समावेश की प्रक्रिया को एकरूप (डिजाइन) में प्रस्तुत कर सकें। सामाजिक नीतियों को वि-केन्द्रित करना वस्तुतः सामाजिक नीतियों के दायित्वों को विकेन्द्रित करना है। यह विकेन्द्र प्रतियोगी रणनीतियों के लिए राजनीतिक क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक ओर नव्य उदारवादी रणनीति स्थानीय एवं स्वैच्छिक अभिकरणों एवं उनके ग्राहकों को मानवपूँजी निवेशक एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र हेतु उत्तरदायी उपभोक्ताओं में बदलने के उद्देश्य के साथ सक्रिय होती है। वहीं दूसरी ओर प्रगतिशील रणनीतियां कल्याण को हतोत्साहित करने वाली इन परियोजनाओं का विरोध करती हैं तथा बाजार के नियमों के अनुरूप नागरिकीय समाज की सक्रियता को हतोत्साहित करती हैं। वैचारिकी को प्रोत्साहित अर्थात एडवोकेसी को प्रोत्साहित

करने वाली स्थितियाँ ज्ञान एवं जमीनी हकीकत वाले प्रयासों को एकीकृत करने का दावा करती हैं। ये स्थितियाँ स्थानीय परिलब्धियों एवं वित्तीय सहायता का पता लगाकर उन गतिविधियों को विकसित व गति देती हैं जो नवीन क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, एवं सामाजिक देखभाल, आवास, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं नगरीय पारिस्थितिकी से जुड़े हैं।

यूनान में पहले दो बेल-आउट समझौतों ने समझबूझ कर ऐसे प्रयास को जन्म दिया जो श्रम शक्ति एवं श्रमिक जनसंख्या की परिलब्धियों के मूल्य को कम करते हैं। सन 2010 में जीवनचर्या स्थितियों में अनअपेक्षित रूप से तीव्र गिरावट आयी। पिछले दो वर्षों में इस गिरावट में कुछ रोक लगी है परन्तु इस स्थिति को, जिस तरह यूरोपियन पूंजीवाद वर्तमान में स्वयं को संगठित कर रहा है, पूर्णरूपेण ठीक नहीं किया जा सकता। सन 2016 में गरीबी की दर सन 2008 के मापक का प्रयोग करें तो यूनान देश की आधी आबादी गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही है। परन्तु यदि हम वर्तमान आय मापक का भी प्रयोग करें तो 25 वर्ष से कम आयु के चार रोजगार युवाओं में से एक युवा अंशकालिक नौकरी में संलग्न है और पांच में से एक कार्यशील गरीब की श्रेणी का भाग है। यूनान में बेलआउट समझौतों ने असमानता में वृद्धि की है तथा युवा जनसंख्या का लगभग आधा भाग या तो अत्यन्त गरीब है अथवा अत्यन्त प्रतिकूल जीवन चर्या स्थितियों का शिकार है। नयी गरीबी ने लगभग सभी को विशेषतः युवा जनसंख्या, अप्रवासी एवं नगर की कच्ची बस्तियों के निवासियों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।

हाल के अनुसंधान के निष्कर्षों (जो मेरी हाल में प्रकाशित पुस्तक 'कन्टेस्टेड लैण्डस्केप्स ऑफ पावर्टी एण्ड होमलैसनेस इन सर्दन यूरोप : रिप्लैक्मन्स फ्रॉम एथेन्स' का भाग है जिसमें कोस्टास गाउनिस मेरे सहलेखक हैं) से यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार अनियमित/आधे अधूरे (स्टाप गैप) मापक स्थानीय निर्धनता विरोधी नीतियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किये हुए हैं। 'सामाजिक एकजुटता आय' के कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है जो सामाजिक सेवाओं को हस्तान्तरित करता है पर आय सम्बन्धी सहायता बहुत कम है एवं अत्यन्त कठोर कार्य सम्बन्धी शर्तें उस कार्यक्रम में प्रावधान के रूप में लागू की गयी हैं। संसाधनों की कमी के कारण स्थानीय एवं नागरिकीय अभिकरण बाध्य हुए हैं कि वे सामाजिक समावेश के स्वरूप को इस प्रकार बदलें कि वह निजी आर्थिक सहायता को आकृष्ट कर सकें। यह पक्ष स्थापित किया जा रहा है कि बेल आउट कार्यक्रमों ने न केवल सहायता/समर्थन के कमजोर एवं अनुपयुक्त स्वरूपों को ही नष्ट नहीं किया है अपितु सार्वजनिक प्रावधानों एवं सशक्त उपकार प्रक्रियाओं को निजीकरण की तरफ विशेष रूप से आकार दिये हैं अथवा उन्हें अग्रसर किया है।

एक और निराशाजनक जानकारी शोध से प्राप्त हुई कि 'नवीन गरीब' एवं हाशिये पर खड़े अन्य के मध्य कृत्रिम विभाजन बनाया गया है। नवीन गरीब वे हैं जो अब तक स्वयं को मध्यवर्गीय नागरिकों के हिस्से के रूप में पाते थे (अब वे निर्धनता की सामान्य जोखिम उत्पन्न होने की सम्भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं) जबकि हाशिये पर खड़े अन्य में मादक द्रव्य सेवक, मानसिक रूप से अस्वस्थ, अवैध अप्रवासी एवं घुमन्तु लोग सम्मिलित होते हैं। इस संदर्भ में स्थानीय नीति से सम्बद्ध प्रत्युत्तरों की सबसे बड़ी खामी यह है कि वे न केवल भौतिक अभाव/निर्धनता के पक्ष के सुलझाव में असफल हैं अपितु अभावग्रस्त लोगों में प्रतीकात्मक विभाजन को छिपाने का भाव उत्पन्न हुआ है ताकि वे अपराध एवं भय बोध के कारण अभाव/निर्धनता को छिपा सकें।

इसके विपरीत नागरिकीय समाज में व्याप्त बाहुल्यता ने बाजार के तर्क एवं निर्धनता निवारण की पुरानी स्थापित प्रणालियों पर प्रश्न

चिह्न उत्पन्न किये हैं। अनेक संगठित एवं कम संगठित प्रयासों को चारों ओर फैलाकर आशा का एक परिवेश व्यापक रूप से बनाया गया है जो उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की कोशिश करता है जो प्रशासनिक श्रेणियों का हिस्सा बनने में समर्थ नहीं है। सीमान्तता को गहराई से फैलने के विरुद्ध अनौपचारिक सहायता एक संरक्षण प्रदान करती है साथ ही स्थानीय एकजुटता के प्रयासों ने यूनानी नगरों में गैरस्थिर यूरोपियन अप्रवासी नीति के विरुद्ध अप्रवासियों का स्वागत किया है।

इसके बावजूद 'स्वाभाविकता' अथवा 'साख' (गुडविल) परिवर्तन हेतु उपयुक्त नहीं है विशेषतः तब जबकि जमीनी प्रयासों पर यूरोपियन यूनियन द्वारा सन्देह किया जाता हो या फिर ये जमीनी प्रयास भारी भरकम प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत होते हों। एक व्यापक रूप में फैले विचार या विश्वास के विरुद्ध यह पाया गया कि उन क्षेत्रों से सम्बन्धित ज्ञान व सूचना को एकत्रित करने में वर्षों लगे जहाँ नागरिकीय समाज ऐतिहासिक दृष्टि से सक्रिय है, जहाँ स्वैच्छिक क्षेत्र, पेशे से जुड़े संगठन, अवैध कब्जा करने वाले संगठन एवं जमीनी स्तर के समूह विभिन्न प्रयासों में सहयोग करते हैं और जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आवाज उठाने वाले संगठन अथवा आन्दोलन स्थापित हो चुके हैं। इन सब के बावजूद अनेक क्षमताओं की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। निरंकुशतावादी एवं ग्राहकी (क्लाइन्ट) की मानसिकता अब तक जीवित है जो शासक दलों की चेतना का भाग है। ये दल राज्य के विस्तार हेतु सामूहिक संगठनों को प्रयुक्त करते हैं, सामाजिक विशेषज्ञता के महत्व को कम आंकते हैं एवं असहमति की आवाज को दबाते हैं।

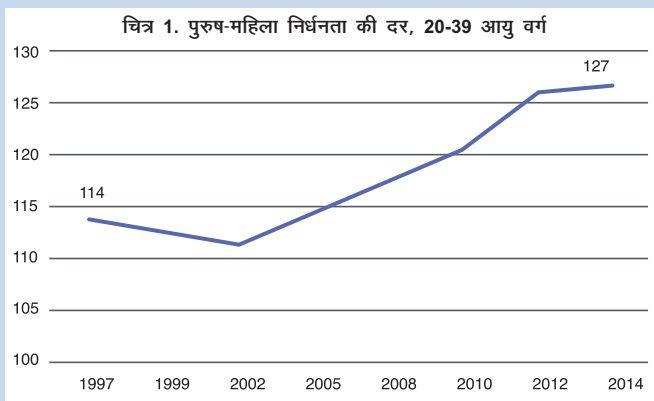
यूनान की 'उत्तम एवं समावेशी वृद्धि' की रणनीति को एक ऐसे प्रयास सम्बन्धी विचार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो सुधार नीतियों को विखण्डित करता है और एक ऐसे समझौते की तरफ जाता है जहाँ यूरोपियन संस्थाओं के साथ मिलकर 'उत्तर कल्याण' के भविष्य की तलाश हो सके। नागरिकीय समाज के संगठनों ने ऐसी योजना व प्रयासों की आलोचना की है एवं यूरोपियन कमीशन के साथ समझौते की पारदर्शिता के अभाव के कारण आलोचना की है। ये योजनाएं मूर्त उद्देश्यों को सुनिश्चित नहीं करती है यदि ऐसा हो तो निर्धनता कम करने के प्रयास हो सकते हैं। साथ ही उद्देश्य केन्द्रित/लक्ष्य केन्द्रित सहायता का ये योजनाएं स्वागत नहीं करती है एवं सहायता के वर्तमान निम्न स्तरों के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन नहीं करती है। ठीक ऐसे ही 'युवाओं के आर्थिक व सामाजिक एकीकरण' एवं 'सामाजिक अभिमुखित अर्थव्यवस्था' की प्राथमिकताओं को मूर्त मापकों द्वारा सहयोग व समर्थन नहीं करती हैं। यह चौंकाने वाला तथ्य है कि शरणार्थियों एवं अप्रवासियों के एकीकरण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बल नहीं दिया जाता है। यह योजना कमीशन के साथ समझौते पर बल देती है और मुख्य क्षेत्रों को रेखांकित करती है। मुख्य रूप से सामूहिक सौदेबाजी एवं न्यूनतम पारिश्रमिक को पुनः जीवित करने पर बल देती है जो कि श्रमिक क्रियाओं के अथवा श्रमिक सक्रियता के क्षेत्र हैं। हम यह जानते हैं कि श्रम विरोधी विधेयकों की वापसी या उन्हें उलटना अत्यन्त कठिन है साथ ही निम्न आय वर्ग एवं युवा स्वरोजगार पर कर संरचना की वापसी, सेवानिवृत्ति लाभों जैसे पेंशन में कमी/कट या उसका स्थगन की वापसी भी अत्यन्त कठिन है क्योंकि इन मुद्दों पर नेताओं की सहमति है। ऐसी विपरीत स्थितियों में राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों व मांगों हेतु नागरिकीय समाज द्वारा स्थानीय स्तर पर संघर्ष की आशा की एकमात्र किरण है। ■

सभी पत्राचार वेसिलिस एरापोग्लू को <arapov@uoc.gr> पर प्रेषित करें।

> लेटिन अमरीका में अधिक निर्धन महिलाएं क्यों हैं?

जुलियाना मार्टिनेज फ्रेन्जोनी, कोस्टा रीका विश्वविद्यालय, आई.एस.ए., निर्धनता, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक नीति की शोध समिति (आरसी 19) की सदस्य द्वारा

आर्थिक वृद्धि, चुनावी प्रतिस्पर्धा एवं वाम झुकावों के बावजूद लेटिन अमरीका में महिला निर्धनता की दर प्रत्येक 100 पुरुष पर 114 से 127 तक बढ़ गई है (चित्र 1)। प्रदेश भर की लाखों महिलाओं के लिए क्या गलत हुआ?



स्रोत: इसीएलएसी आंकड़ों, सेपलस्टेट, 2018 पर आधारित स्वयं का विश्लेषण

> संदर्भ

लेटिन अमरीका एक 'वामपंथी झुकाव' या 'पिंक टाइड' जो 1998 से प्रारम्भ हुआ एवं 2000 के मध्य तक चला, से उभर रहा है। चुनावी प्रतिस्पर्धा ने प्रगतिशील प्लेटफार्मों को व्यापक प्रभाव उपलब्ध कराया और प्रगतिशील श्रम और सामाजिक नीतियों की मांग को उजागर किया।

वामपंथ की तरफ झुकाव पूर्व रूढ़िवादी सरकारों के अपूर्ण वादों के साथ नागरिकों के मोहभंग का राजनैतिक परिणाम था। यह मोहभंग आर्थिक बूम के संग आया। वामपंथी दलों एवं उनके नेताओं, यद्यपि विविध, ने परिवर्तन, विशेष रूप से रहने की स्थितियों में, की मांग उठाई। 2000 तक प्रदेश भर में सामाजिक परिणाम एवं सामाजिक नीतियां फैल गईं।

> राज्य कार्यवाही

पिंक टाइड के दौरान लागू हुई आर्थिक नीतियों में श्रम बाजार के नीतिगत सुधार जैसे वास्तविक न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना और

औपचारिकता में वृद्धि, सम्मिलित थे। सामाजिक व्यय कुल सार्वजनिक व्यय का काफी बड़ा हिस्सा बन गया। यह 2000 में 49 प्रतिशत से 2014 में 58 प्रतिशत तक बढ़ गया। प्रति व्यक्ति के संदर्भ में यह 2000 में 687 अमरीकी डॉलर से 2014 में 1619 अमरीकी डॉलर तक चला गया। ऐसा इकोनोमिक कमीशन फॉर लेटिन अमरीका एण्ड द कैरेबियन (इसीएलएसी) ने रिपोर्ट किया। यद्यपि वृद्धि का आकार विस्तार देशों के पास भिन्न था, रुझान पूरे प्रदेश में प्रकट हुआ और नये एवं सुधारे हुए कार्यक्रमों दोनों में देखा गया।

अधिकांश सामाजिक खर्च ने हस्तांतरण और सेवाओं के माध्यम से राज्य संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच का पक्ष लिया। लेटिन अमरीका में सर्वत्र राज्य हस्तक्षेपों की काफी बड़ी संख्या ने महिलाओं और माताओं को लक्ष्य बनाया। नीतिगत विकास ने सशर्त नकद हस्तांतरण (सीसीटी) और विस्तारित पेंशन कवरेज द्वारा स्व-आय वाली महिलाओं के अनुपात में वृद्धि की। इन हस्तक्षेपों ने पतियों के आश्रितों के रूप में प्राप्त लाभों की तुलना में अपनी शर्तों पर वृद्धावस्था लाभ तक महिलाओं की पहुंच में सुधार किया। इसके अतिरिक्त, प्रसूति अवकाश की अवधि और कवरेज में वृद्धि हुई और धीरे-धीरे परिवारों के परे देखभाल और अवैतनिक महिला, मातृत्व कार्य का पुनर्गठन प्रारम्भ हुआ। श्रम बाजार में अधिक भागीदारी में महिलाओं का जीवन बदल गया।

श्रम बाजार और राज्य निगमन

>

2000 के दशक के दौरान, तृतीयक श्रेणी की शिक्षा वाली महिलाओं पर उच्चतम सीमा लगाने के कारण कुल महिला श्रम भागीदारी धीमी हुई। 24 में से 59 वर्ष की आयु की उच्च शिक्षित महिलाओं ने लगभग 90 प्रतिशत श्रम बल भागीदारी को अनुभव किया। महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि के लिए कम शिक्षित महिलाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, इन महिलाओं ने श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए कई संरचनात्मक बाधाओं का सामना किया। परिवर्तन का सम्पूर्ण पैटर्न सभी महिलाओं के लिए अपूर्ण था लेकिन आय असमानता भी महिलाओं के बीच विभाजित हो गई।

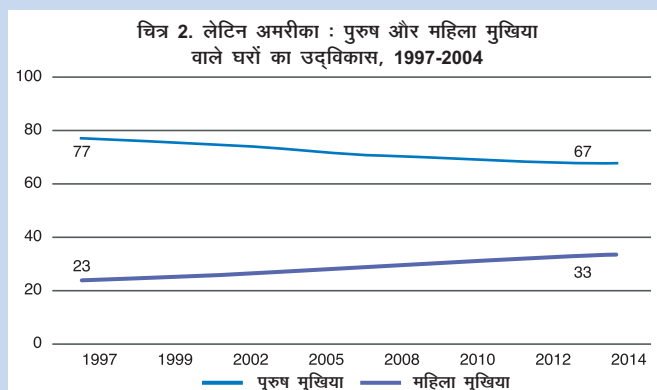
विभिन्न कारणों से, श्रम बाजारों में महिलाओं का समावेशन 2000 के दशक के प्रारम्भ तक दोनों निम्न और उच्च आय वाली महिलाओं के लिए स्थिर हो गया। सबसे खराब स्थिति वालों के

लिए श्रम के लैंगिक विभाजन, पूर्व और उच्च प्रजनन क्षमता और राज्य सेवाओं तक पहुंच निजी बाजारी देखभाल सेवाओं को क्रय करने के सीमित संसाधनों के कारण भागीदारी दर बढ़ी। श्रम के अपरिवर्तित यौन विभाजन का अर्थ था कि उच्च शिक्षित महिलाएं प्रजननता को कम एवं स्थगित कर और निजी बाजार से देखभाल सेवाओं का क्रय कर पुरुषों के समान श्रम बल भागीदारी बल तक पहुंच गई थीं।

> परिवार व्यवस्था में परिवर्तन

द्वितीय जनसांख्यिकीय क्रांति के बाद लेटिन अमरीकी परिवारों में भी गहरे परिवर्तन हुए। विविध वैवाहिक संबंधों का अर्थ व्यापक पारिवारिक प्रवेश एवं निकास विकल्पों और अधिकारों एवं जिम्मेदारियों का बेहतर वितरण था। यद्यपि इन परिवारों की संख्या कम थी, ये भी अस्थिर थे और टूटने के लिए प्रवण थे।

प्रदेश भर में, पारिवारिक व्यवस्थाओं में हास, और एकल मुखिया परिवारों, सहवास, समाज लिंग वैवाहिक युगलों और परिवार के अन्य रूपों के उभार से एकल परिवारों में गिरावट आई। तलाक दरों में वृद्धि इन परिवर्तनों का एक संकेत है। चित्र 2 द्वि-अभिभावक, पुरुष-मुखिया परिवारों के अनुपात में महिला मुखिया गिरावट और परिवारों के अनुपात में वृद्धि को दर्शाता है। पारिभाषिक तौर पर पारिवारिक इकाइयां सहयोगात्मक और असंगत है। चालू पारिवारिक इकाइयां सहयोगात्मक और असंगत है। चालू पारिवारिक परिवर्तनों ने परिवारों के सहयोगात्मक पक्ष, जिसमें व्यस्क संयुक्त रूप से एक-दूसरे एवं अपने बच्चों की देखभाल और रक्षा करते हैं, को चुनौती दी जिसने पुराने और नये संघर्षों की उपस्थिति को उजागर किया। इन परिवर्तनों का एक परिणाम, पिता के साथ एक घर में नहीं रहने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि है।



स्रोत: इसीएसएसी आंकड़ों पर आधारित

परिवारों में परिवर्तन का सभी भागीदारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आँकड़े लेटिन अमरीका के बच्चों और युवाओं की

कम से कम 60 प्रतिशत उपभोग आवश्यकताओं को निजी अंतरण से आता हुआ दिखाते हैं। बच्चों के आर्थिक रखरखाव और देखभाल आमतौर पर बच्चों के अभिभावक, उनकी माताओं के साथ जुड़ी होती है। महिलाएं अपने बच्चों को खिलाती हैं, लालन-पालन करती हैं, चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले जाती हैं और बच्चों के लालन-पालन की लंबी सूची को पूरा करती हैं। आवश्यकता, मूल्य और उपभोग की छिपी पीढ़ी परिवार के भीतर होती है और यह महिलाओं के अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य के माध्यम से पूरा होती है। क्षेत्रीय समय-उपयोग सर्वेक्षण रिपोर्ट करते हैं कि आय, आयु और पारिवारिक व्यवस्थाओं के बावजूद भी यह मामला होता है।

महिलाओं ने श्रम बाजार भागीदारी में बदलावों को अनुभव किया लेकिन पुरुषों की घरेलू भागीदारी में मामूली परिवर्तन आया। पुरुषों की तुलना में महिलाएं दुगुना या तीन गुना अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य लगातार करती रहती हैं। इसके अलावा, जब परिवार टूटते हैं, कुछ ही बच्चें अपने पिताओं के साथ रहते हैं। घरेलू श्रम का इस तरह का निरंतर और असमान वितरण का संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घरेलू दायित्व महिलाओं की श्रम बाजार भागीदारी (उदाहरण के लिए वैतनिक कार्य घंटे) को प्रतिबंधित करते हैं और पारिवारिक जरूरतों को समायोजित करने के लिए व्यवसायिक अलगाव को बनाये रखते हैं। आय का अंतर महिलाओं की उनकी अवैतनिक घरेलू कार्य को आंशिक रूप से घर-आधारित साथ ही महिला कार्य जो लेटिन अमरीका के असमान देखभाल व्यवस्था की मूल विशेषता, में परिवर्तन करने की क्षमता को सीमित करती है।

> परिणाम

परिवर्तित पारिवारिक व्यवस्थाएं, पिताओं द्वारा वैवाहिक सम्बन्धों के परे भूमिकाओं को छोड़ना और बच्चों के भौतिक कल्याण में राज्य का मामूली और प्रत्यक्ष भागीदारी मिलकर एक अनुकूली राज्य कानून और नीतियों की आवश्यकता पैदा करती हैं। राज्य ऐसी नीतियों का विकास करने में चुनौतियों का सामना करते हैं जो तलाकशुदा परिवारों की बढ़ती संख्या, एकल अभिभावक (अधिकांशतः एकल माता वाले) परिवार, दोहरी कमाई वाले परिवार, समान लिंग पार्टनर और गरीबी से आघात योग्य अधिक बच्चे और महिलाओं की जरूरतों का प्रत्युत्तर देने में सक्षम हों। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक व्यवस्था की इस विस्तृत शृंखला की कानूनी मान्यता और समान अधिकारों की मांग राज्य हस्तक्षेपों को पारिवारिक व्यवस्था और निर्धनता विरोधी नकद अंतरण के परे सहयोग को लागू करने में सक्षम हैं। कुल मिलाकर, यह सभी राजनैतिक कलाकारों के लिए, जिसमें वामपंथी दल सम्मिलित हैं एक नई चुनौती है।

सभी पत्राचार जुलियाना मार्टिनेज फ्रांज़ोनी को <julianamartinez@ucr.ac.cr> पर प्रेषित करें।

> 'चैरिटी अर्थव्यवस्था' कल्याणकारी राज्य की छाया में

फैबियन केसल, डुइसबर्ग-एसेन विश्वविद्यालय, जर्मनी द्वारा



जर्मनी अकेले में, लाखों लोग सूप किचन, दान के कपड़ों की दुकानें खाद्य वितरण स्थान और अन्य खाद्य बैंक जाते हैं। क्रियेटिव कामन्स।

दि सन्बर 2017 में एसेन (जर्मनी) में स्थानीय खाद्य बैंक के बोर्ड ने अप्रवासी उपभोक्ताओं के लिए पहुंच को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। एक युवा प्रवासी पुरुष के अनुमानित दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए, खाद्य बैंक ने जर्मन पासपोर्ट के बिना लोगों के लिए पहुंच रद्द कर दी। नस्लीय रेखा के आधार पर स्थानीय खाद्य बैंक तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के निर्णय की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई और निहित नस्लवाद के लिए इसकी भारी आलोचना की गई। एसेन का मामला सामाजिक प्रश्न में बदलाव की ओर इंगित करता है। एसेन जैसे शहर में जहां अमीर और गरीब के मध्य भारी धुवीकरण है 'ऊपर और नीचे' के मध्य मतभेदों और सम्बन्धों पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय, एक नये अंतर को एजेन्डा पर लगाया 'अन्दर और बाहर' के मध्य। विपक्षी अब "जरूरतमंद और कमजोर जर्मन पेशनभोगी" और "हठधर्मी-युवा गैर जर्मन व्यक्ति" के मध्य स्थित हैं। लोकतांत्रिक समाज की पृष्ठभूमि के बावजूद ऐसे परिवर्तन पर सार्वजनिक रूप से एवं वैज्ञानिक रूप से चर्चा की जानी चाहिए। हालांकि इस नये एजेन्डा में जो सही समझा गया है वह है बड़े यूरोपीय शहर में स्थानीय खाद्य बैंकों की उपस्थिति। उल्लेखनीय है कि बहस ने इस प्रश्न को सिर्फ छुआ मात्र है कि जर्मनी जैसे देश या अन्य यूरोपीय और साथ ही उत्तर अमरीकी देशों में 21वीं सदी में लोग दैनिक आधार पर खाद्य बैंक का उपयोग क्यों कर रहे हैं।

जर्मनी में खाद्य सहायता पर आधिकारिक संख्या जर्मन फूड बैंक एसोसिएशन (ताफेल ड्यूशलैंड इवी) जैसी राष्ट्रीय संघों के आंतरिक आंकड़ों के आधार पर ही उपलब्ध है। एसोसिएशन ने बताया कि 2016 में, सिर्फ उनके सदस्य संगठनों की गिनती कर 934 खाद्य बैंक थे। यदि हम उन सभी संगठनों की गणना करें जो 'जरूरतमंदों' को मूलभूत वस्तुएं वितरित करते हैं, हमें यूरोप भर में और उसके आगे गरीबी में राहत देने की व्यापक व्यवस्था मिलती है। अकेले जर्मनी में, लाखों लोग सूप किचन, दान के कपड़ों की दुकानें, खाद्य वितरण स्थान और अन्य खाद्य बैंक के उपयोगकर्ता

हैं। हमारे अपने शोध ने दिखाया कि लगभग 5000-6000 संगठन सोलह बुन्डेस्लेन्डर (जर्मन राज्यों) में से केवल पांच में पाए जा सकते हैं। 1980 के दशक (या पहले जैसे अमरीका में) के बाद से निर्धनता राहत की एक नई प्रणाली स्थापित की गई है। इस प्रणाली को 'नई चैरिटी अर्थव्यवस्था' भी कहा जा सकता है।

'नई चैरिटी अर्थव्यवस्था' शब्द एक ऐसी वितरण प्रणाली का वर्णन करता है जिसमें मूल वस्तुओं को स्वैच्छिक सहायकों या कम वेतन वाले व्यक्तियों के माध्यम से 'निर्धन' या 'जरूरतमंदों' को निशुल्क वितरित किया जाता है या कम दामों पर बेचा जाता है। यह व्यवस्था दैनिक उपभोग की वस्तुओं के प्रावधान के लिए तीन स्त्रोतों में से एक पर निर्भर करती है : औद्योगिक अधिक उत्पादन; वे सामान जो सांविधिक मानकीकरण विनिर्देशों और विपणन उद्देश्यों जैसे कारकों के कारण क्रय न किये जा सकें; और वे सामान जो निजी घरों के लिए आवश्यक नहीं हैं।

'नई चैरिटी अर्थव्यवस्था' उन लोगों के समूह को लक्षित करती है जिनके पास माल वितरण की पूंजीवादी व्यवस्था में भाग लेने के लिये साधन या संसाधन नहीं हैं। हालांकि यह नई अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से दैनिक जीवन के लिए मूल जरूरतों का सामान वितरित करती है। इस तरह वह समर्थन के स्वरूपों, जो कभी कल्याण राज्य और उसके अभिकरणों की विशेष जिम्मेदारी थे (जैसा कि हम उन्हें बीसवीं शताब्दी के मध्य में यूरोप या उत्तरी अमरीका में जानते थे) को प्रभावित करता है। कल्याणकारी राज्यों के सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में, कानूनी दावों के आधार पर माल आपूर्ति अन्तर मुख्य रूप से नकद लाभ के माध्यम से बफर किये जाते हैं और सामाजिक सेवाओं द्वारा पूरक होते हैं। फिर भी, 'नई चैरिटी अर्थव्यवस्था' संवैधानिक सामाजिक बीमा, आपूर्ति, या जरूरतमंदों के लिए अनुदान के साथ गैर-मौद्रिक लाभों को रखती है। कभी-कभी वे इनको प्रतिस्थापित कर देती हैं। प्रतिस्थापन के मामले में, प्रयोक्ता को दान पर आधारित इस नई आजीविका सहायता सेवा के पास भेजा जाता है। इसकी उपलब्धता पात्रता पर आधारित नहीं है अपितु धर्मार्थ उपहार (जिसका अर्थ वफादारी है) प्राप्त करने में है। सहायता प्रदान करने के तरीके को बदल कर 'नई चैरिटी अर्थव्यवस्था' निर्धनता में कमी को निर्धनता राहत में बदल देती है: दानदाताओं के साथ-साथ सहायक 'अजनबियों के मध्य एकजुटता' (हौके ब्रंकहोस्ट) की बजाय करुणा पर कार्य कर रहे हैं। यह दूसरों के दुर्भाग्य पर अस्थायी ध्यान है न कि 'नई चैरिटी अर्थव्यवस्था' को दर्शाने वाले को समर्थन प्रदान करने का औपचारिक अधिकार।

लेकिन यह ऐतिहासिक रूप से औद्योगिता के प्रारम्भ के दिनों से जाने जाने वाली निर्धनता राहत की प्रणाली नहीं है जो वफादारी और अनुकम्पा पर आधारित थी। 'नई चैरिटी अर्थव्यवस्था' को एक द्वैतीयक आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी समझा जाना चाहिए। प्राथमिक बाजार के साथ निकटता से जुड़ी चैरिटी अर्थव्यवस्था

अधिशेष वस्तुओं की प्राथमिक बाजार से द्वैतीयक बाजार में हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। यह हस्तांतरण उन लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से लाभदायक है, जो प्राथमिक वस्तुओं का दान देते हैं क्योंकि उन्हें अपने दान के बराबर का लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, खाद्य छूटकर्ता दान किये माल से भी लाभ प्राप्त करते हैं, चूंकि (अ) यह उनकी निपटान लागत को कम करता है और संभवतः कुछ कर बचत की अनुमति देता है; और (ब) आधिकारिक तौर पर सहयोगी या प्रायोजक कम्पनियां कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत दान करके लाभ एवं अपनी सार्वजनिक छवि को परिष्कृत कर सकती हैं।

अतः 'नई चैरिटी अर्थव्यवस्था' कल्याणकारी राज्य की विशाल और बढ़ती छाया के अस्तित्व को दर्शाती है। सार्वजनिक छवि के विपरीत, खाद्य बैंक, सूप किचन, दान के कपड़ों की दुकानें और अन्य ही नागरिक समाज में स्वैच्छा आधारित पहलें नहीं हैं। हमारा शोध दिखाता है कि जर्मनी में 'नई चैरिटी अर्थव्यवस्था' में 90% संगठन दोनों भौतिक सहायता और सामाजिक सेवाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं। इस प्रकार, औपचारिक कल्याण राज्य के साथ एक मजबूत सम्बन्ध है, जो चैरिटी अर्थव्यवस्था के वित्त पोषण से भी स्पष्ट है : अक्सर दान, प्रयोजन, सार्वजनिक धन, सदस्यता शुल्क, अर्जित राजस्व और/या सेवा शुल्क का मिश्रित स्वरूप देखा जा सकता है। इसके अलावा, दान आधारित सहायता के प्रदाता अक्सर साधन-परीक्षण निष्पादित करते हैं जहां मौजूदा कल्याण राज्य विनियम अक्सर लागू किये जाते हैं। दूसरे शब्दों में, कल्याण राज्य की सेवा व्यवस्था को 'नई चैरिटी अर्थव्यवस्था' से जो जोड़ता है, वह सरकारी प्रशासन द्वारा व्यक्ति की स्थिति का आकलन है। उदाहरण के लिए, नौकरी केन्द्रों और रोजगार एजेन्सियों के कर्मचारी राज्य लाभों के लिए आवेदन करने वाले जरूरतमंदों को खाद्य वितरण स्थान जैसी सेवाओं के बारे में बताते हैं। इस प्रकार सहायकता का एक नया सम्बन्ध — जहां छोटी इकाई से अगली बड़ी इकाई के पहले मदद प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है — स्थापित होता है। लोक प्रशासन कर्मचारी नई चैरिटी अर्थव्यवस्था की सेवाओं को वास्तविक कल्याण राज्य लाभों के एक पूरक के रूप में — या एक विकल्प के रूप में समझते हैं चाहे उनके पास सामाजिक कानून में कोई आधार न हो।

'नई चैरिटी अर्थव्यवस्था' नागरिक समाज, अर्थव्यवस्था और राज्य के तीन क्षेत्रों के मध्य एक नये श्रम विभाजन के प्रमुख उदाहरण के रूप में कार्य कर सकती है, जहां इनकी संबंधित सीमाएं और कार्यवाही के तर्क धुंधले हैं। हम इस प्रकार जरूरतमंद लोगों की सहायता के पारंपरिक रूपों में मौलिक बदलाव की तरफ अग्रसर हैं। ■

सभी पत्राचार फैबियन केंसल को <fabian.kessl@uni-due.de> पर प्रेषित करें।

> खाद्य सुरक्षा विमर्श : 21वीं शताब्दी के लिए चुनौतियां

मुस्तफा कोक, रायरसन विश्वविद्यालय, कनाडा और प्रवासन का समाजशास्त्र (आरसी 31) एवं कृषि और खाद्य (आर सी 40) पर आई.एस.ए. शोध समिति के सदस्य द्वारा



अर्थव्यवस्था में किस प्रकार खाद्य तक पहुंच का प्रबंध करना चाहिए के साथ खाद्य व्यवस्था के संयोजन के विशिष्ट तरीकों में बदलाव जैसे बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खाद्य प्रावधानों की शर्तों को परिभाषित करने वाली नीतियां और रीतियां, की प्रतिस्पर्धात्मक कल्पनाओं को दर्शाती है।

1980 के दशक से खाद्य सुरक्षा की अवधारणा बाजार उदारवाद, वैश्विक आर्थिक संबंधों में तीव्रिकरण, अर्थव्यवस्था और राज्य के पुनर्गठन के माहौल में पुररीक्षण से गुजरी है। 1970 के दशक के वित्तीय संकट के समाधान के रूप में अपनायी गई नवउदार नीतियों ने सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च में कटौती और कार्य की स्थितियों में बदलाव, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को संकुचित करना, विनिमयन, निजीकरण और व्यापार का उदारीकरण को अग्रेषित किया। इन परिवर्तनों से विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों और अधिकतर अनौपचारिक एवं सेवा क्षेत्रों में अनिश्चित और अंशकालिक रोजगार में कमी आई। सामाजिक कार्यक्रमों में गिरावट ने स्थिति को और खराब कर दिया जिसके परिणामस्वरूप निर्धनता और खाद्य असुरक्षा की दरें उच्च हुईं।

19 70 के दशक के मध्य में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान सभी के लिए खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता और पहुंच को सम्बोधित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उभरी। खाद्य सुरक्षा की सुपरिचित परिभाषाओं में से एक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) द्वारा 1996 के विश्व खाद्य शिखर में दी गई थी। इस परिभाषा के अनुसार, खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तब होता है “जब सभी लोगों को, हर समय, पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है जो एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार सम्बंधी आवश्यकताओं को आहार प्राथमिकताओं को पूरा करता है।”

एफ.ए.ओ. जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा व्यापक मान्यता के बावजूद, अनेकानेक परिभाषाओं और अलग-अलग प्राथमिकताओं के साथ खाद्य सुरक्षा एक भ्रमित अवधारणा रही है जो वर्षों से बदलती रही है। खाद्य सुरक्षा विमर्श की वैचारिक जटिलता, बाजार

नवउदार खाद्य सुरक्षा विमर्श में पूर्ववर्ती युग की अधिकार-आधारित भाषा से एक बाजार-उन्मुख की तरफ परिवर्तन हुआ जो खाद्य को एक वस्तु के रूप में पहचानता था और खाद्य असुरक्षा को कृषि-खाद्य व्यवस्था की असफलता के बजाय व्यक्तिगत/निजी असफलता मानता था। 1993 के विश्व बैंक के दस्तावेज ने इस बदलाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित किया : “यद्यपि, व्यवहार में भोजन एक वस्तु है।” कल्याणकारी राज्य के सामाजिक प्रचार्यों में संकुचन के साथ और राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रमों को प्रादेशिक और स्थानीय सरकारों के जिम्मे देने के साथ ही, सामाजिक सहायता और देखरेख कार्यों को अधिकाधिक नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और परिवारों के लिए छोड़ दिया गया था। लोकोपकारी संगठन जैसे खाद्य बैंक सरकारी सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा छोड़े गये रिक्त स्थान को भरने लगे। 1967 में संयुक्त बैंकों में सामाजिक कल्याण एजेंसियों की तुलना में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था। फिर भी वे दुनिया भर में “अधिशेष आबादी, अधिशेष भोजन” तक प्रदान करने वाले सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में फैलने लगे।

बाजार आर्थिकी में, वे उत्पाद जो मानव उपभोग के लिए उत्पादित किये गये हैं लेकिन बाजार में अपनी उपभोग की अन्तिम तारीख के पहले विक्रय नहीं किये जा सकते हैं, अधिशेष बन जाते हैं। अधिशेष भोजन के पुनर्वितरण को खाद्य अपशिष्ट और खाद्य निर्धनता से निपटने के एक समाधान के रूप में बढ़ावा दिया गया है। प्रकट रूप से नेक चिंता, हालांकि सामाजिक सहायता में सरकारी कटौती और खाद्य असुरक्षा में वृद्धि में कृषि-खाद्य कंपनियों की विपणन अनिवार्यताओं को अनदेखा करती है। यद्यपि यह सच है कि मानव उपभोग के लिए उत्पादित 40 प्रतिशत तक भोजन खेत और प्लेट के मध्य खो जाता है या बर्बाद हो जाता है और इस बर्बादी में कमी हमें दुनिया के सभी खाद्य असुरक्षित को भोजन खिलाने की अनुमति देगी, खाद्य असुरक्षा का कारण भोजन की कमी नहीं है बल्कि यह पहुंच में असमानता के कारण है। वर्तमान में, दुनिया के अधिकांश अनाज और तिलहन को भोजन के बजाय जानवरों के भोजन, जैव ईंधन और उच्च फ्रूक्टोज कार्न सिरप जैसे औद्योगिक उत्पादों में काम में लिया जाता है। इस प्रकार बर्बाद भोजन में कमी लाने के लिए एक विवेचनात्मक पुनः परीक्षण की आवश्यकता है। इसे देखना आवश्यक है कि कृषि-खाद्य प्रणाली की लाभ अनिवार्यताएं और कुछ क्षेत्रों में अनुदान एक साथ भोजन और भूख दोनों के भारी अधिशेष को कैसे पैदा कर रही हैं।

> प्रगति सार्वभौमिक नहीं थी

1996 में विश्व खाद्य शिखर में, 2015 तक कुपोषित लोगों की संख्या को आधी तक ले जाने की प्रतिबद्धता दिखाई गई। उस समय, खाद्य असुरक्षितों की अनुमानित संख्या 799 मिलियन थी। 2009 में, खाद्य असुरक्षितों की अनुमानित संख्या 1023 बिलियन तक पहुंच गई। एफएओ द्वारा 2012 में अपनी पद्धति के साथ भी, कुपोषितों की संख्या को 2015 तक केवल 815 मिलियन तक घटा पाना संभव हुआ। इसके अलावा, अफ्रीका और मध्य पूर्व में, युद्ध और सैन्य संघर्ष के कारण कुपोषित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। हाल ही के दशकों में, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सैन्य संघर्षों ने लाखों लोगों को खाद्य असुरक्षित अधिशेष आबादी में बदल दिया है। एफएओ के 2017 के अनुमानों के अनुसार दुनिया भर के 815 मिलियन क्रोनिक रूप से खाद्य असुरक्षित और कुपोषित लोगों में से लगभग 60 प्रतिशत संघर्ष से प्रभावित देशों में रहते हैं। कुपोषण के फलस्वरूप करीब 75 प्रतिशत अल्पविकसित युद्ध प्रभावित देशों में रहते हैं। घरेलू अर्थव्यवस्थाओं, बुनियादी ढांचे और राज्य की मुख्य संस्थाओं का युद्ध के कारण विनाश ने लाखों लोगों को शरणार्थी बना दिया है जबकि अपने संबंधित क्षेत्रों में आबादी के गमनागमन को रोकने के प्रयासों ने पड़ोसी देशों को शरणार्थी शिविरों में बदल दिया है। पाकिस्तान और ईरान में 6 मिलियन अफगान शरणार्थी, और तुर्की, जोर्डन, लेबनान, इराक और मिस्र में 5.6 मिलियन सिरियाई बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय जनसंख्या के गमनागमन के हाल ही के दो उदाहरण हैं। जहां शरणार्थी दीर्घकालिक और क्रॉनिक देशों में खाद्य असुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता के भी स्रोत बन जाते हैं।

> खाद्य सुरक्षा के भावी खतरे

2050 तक, विश्व आबादी 9 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा अमीर देशों के अनावश्यक उपभोग पैटर्न को अपनाने के साथ और दुनिया भर में सैन्य संघर्षों के द्वारा शरणार्थियों की एक नई लहर को जन्म देने से खाद्य असुरक्षा का स्तर काफी बिगड़ सकता है। अभी तक हमने अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के और आबादी के कमजोर वर्गों के लिए भोजन तक पहुंच में सुधार लाने के तरीकों को तलाशने पर भरोसा किया है। उत्पादक क्षमता को औद्योगिक कृषि पद्धति से बढ़ाने के प्रयासों ने अधिक कुशल किसानों के हाथों में स्वामित्व के संकेन्द्रन में वृद्धि की है और लाखों कृषकों और लघु किसानों को शहरों की तरफ धकेला है। कृषि रसायनों के बढ़ते उपयोग ने भी वृहद पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि-क्षरण, वायु एवं जल प्रदूषण और जैव-विविधता का नुकसान का निर्माण किया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 13 प्रतिशत कृषि का योगदान है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव दुनिया भर की उत्पादन क्षमता पर एक और खतरा पैदा करता है। भोजन की उपलब्धता और पहुंच में सुधार और हानि और अपव्यय/अपशिष्ट में कमी के लिए नई नीतियों को तलाशते समय, हमें पिछली शताब्दी से प्रचलित अपने आहार, उपभोग/खपत पैटर्न और कृषि-खाद्य प्रणाली के संगठन के बारे में प्रश्न पूछने की आवश्यकता है।

उभरता खाद्य संप्रभुता आंदोलन वैकल्पिक खाद्य व्यवस्था की दिशा में काम करने के प्रयासों में किसानों, श्रमिकों और खाने वालों को जोड़ रहा है। जहां खाद्य संप्रभुता खाद्य सुरक्षा के पूर्व के विमर्शों के साथ कुछ अंतर्दृष्टि साझा करती है जिसमें वह राष्ट्रीय/स्थानीय सीमाओं में खाद्य प्रावधानों को परिभाषित स्थितियों में राज्य की भूमिका पर जोर देती है, यह वैश्वीकरण के प्रतिरोध की एक नई भावना को भी सम्मिलित करती है। खाद्य सुरक्षा के नवउदार व्याख्याओं से भिन्न, खाद्य संप्रभुता विमर्श भोजन को एक मानवाधिकार के रूप में मान्यता देता है; भूमि, जल स्थानीय/देशज लोगों के अनुवांशिक साधनों पर स्वामित्व और नियन्त्रण के महत्व को रेखांकित करता है; उत्पादन प्रक्रिया में दक्षता के बजाय संवहनीयता और लचीलेपन पर जोर देता है; और भोजन के हथियार के रूप में इस्तेमाल को खारिज करता है। खाद्य सुरक्षा की तरह, खाद्य संप्रभुता विमर्श भी गतिशील और तरल है जो परिवर्तित राजनैतिक और आर्थिक इतिहास से आकारित होता है। खाद्य प्रणाली की प्राथमिकताओं की सार्वजनिक धारणा के पुनर्निर्माण और खाद्य सुरक्षा को पुनः परिभाषित करने में खाद्य संप्रभुता क्या भूमिका निभाती है, यह देखना रोचक होगा। ■

सभी पत्राचार मुस्तफा कोक को <mkoc@yrverson.ca> पर प्रेषित करें।

> वैश्विक आधुनिकता

सुजाता पटेल, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, भारत तथा आई.एस.ए. की समाजशास्त्र का इतिहास (आरसी 8), नगरीय एवं प्रादेशिक विकास (आरसी 21), अवधारणात्मक एवं शब्दावली समाजशास्त्र (आरसी 35), ऐतिहासिक समाजशास्त्र (आरसी 56) इत्यादि शोध समितियों की सदस्य एवं आरसी 8 की कार्यकारी परिषद् की सदस्य।

19 90 के दशक के उत्तरार्ध से 'वैश्विक आधुनिकता' की अवधारणा का प्रयोग साहित्य में तेजी से किया जा रहा है जिसमें वैश्वीकृत दुनिया के सिद्धांतों की प्रकृति और अंतर्वस्तु पर चर्चा की जाती है। यह अवधारणा स्वयं दो अवधारणाओं 'वैश्वीकरण' और 'आधुनिकता' से मिलकर बनी है और जैसे ही यह दोनों परस्पर जुड़ते हैं प्रत्येक अवधारणा के सिद्धांतों को एक भिन्न तरीके से परिभाषित करते हैं।

वैश्विक आधुनिकता के सिद्धांत प्रारंभ में मुख्यधारा के समाजशास्त्रीय विचार-विमर्श से उभरे जिसने वैश्विक उत्तर के समकालीन परिवर्तनों का आकलन करने में शास्त्रीय सिद्धांतों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन किया। इस सवाल ने अन्य प्रश्नों को उत्पन्न किया, जिसमें से एक यह था कि क्या 1950 और 1960 के आधुनिकीकरण के सिद्धांत शास्त्रीय समाजशास्त्रीय स्थितियों पर आधारित थे और क्या यूरोपीय अनुभवों का अनुकरण दुनिया भर में आधुनिकता की समझ के लिए उपयोगी हो सकता है। इसे जल्द ही स्वीकार कर लिया गया कि आधुनिकीकरण मॉडल वास्तव में समरूपतावादी थे और यह तर्क देते हुए यूरोपीय अनुभवों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया कि संस्थागत संगठन एवं सांस्कृतिक विशेषताएं यूरोप में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो समग्र विश्व में इसका प्रतिनिधित्व करेंगी। बुद्धिजीवियों का सुझाव था कि अब एक ऐसे परिप्रेक्ष्य की जरूरत थी जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक अनुभव को आयोजित करने वाले मतभेदों को पहचान कर आधुनिकता के अभिसरण सिद्धांत को विस्थापित कर दे।

इस स्थिति की स्वीकृति मुख्यधारा के समाजशास्त्र में भानुमति का पिटारा साबित हुई। परिणामस्वरूप इस विषय में वेबेरियन, मार्क्सवादी, संरचनात्मक और उत्तर-संरचनावादी भिन्न विचारों वाले अनेक परिप्रेक्ष्य उभर कर आये तथा इन परिप्रेक्ष्यों को ग्लोबल नॉर्थ के बाहर विकसित हुए स्वदेशी और/या दक्षिणी सिद्धांतों के साथ जोड़ दिया। इन नए और नवीन दृष्टिकोणों की उपस्थिति ने विषय के दायरे और पहुँच को विस्तार दिया, इसे अध्ययन और विचार के एक पृथक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। वर्तमान में वैश्विक आधुनिकता के रूप में परिभाषित बौद्धिक क्षेत्र, आधुनिकता के वास्तविक सिद्धांतों के बारे में एक बड़ी संख्या में दार्शनिक, ज्ञानमीमांसीय और पद्धतिशास्त्रीय विचार-विमर्श करता है, जिसने

समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को एक बार फिर बहस करने के लिए खोल दिया। इस संक्षिप्त टिप्पणी में, मैं उन तीनों परिप्रेक्ष्यों के समुच्चय की रूपरेखा प्रस्तुत कर रही हूँ जो 1980 के उत्तरार्ध और 1990 के प्रारंभ में उभरे थे। इनमें बहु-आधुनिकताओं, देशज/स्थानीय, दक्षिणी सिद्धांतों और वि-उपनिवेशवाद के दृष्टिकोण सम्मिलित हैं।

> बहु-आधुनिकतावादी दृष्टिकोण

बहु-आधुनिकता के सिद्धांत के कई प्रकार हैं और इसमें अनेक विचारकों को शामिल किया जा सकता है। इस अवधारणा को शमुएल आइसेनस्टेड ने प्रस्तुत किया था, जो इस स्थिति को अनेक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं और जिन्होंने सभ्यतामूलक अध्ययनों के साथ आधुनिकता को जोड़ा है; हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में उन विचारकों को भी शामिल किया गया है जो आधुनिकता को सभ्यता के रूप में वर्णित करने से बचते हैं। निम्नलिखित पक्ष इस परिप्रेक्ष्य के विचारकों को एक साथ जोड़ते हैं : (अ) यहाँ कोई एक नहीं अपितु बहु-आधुनिकताएं हैं, अर्थात् आधुनिकता एक-कारकीय नहीं अपितु बहु-कारकीय है, (ब) हालांकि आधुनिकता की संस्थागत अभिव्यक्ति समान हो सकती है, इसके मतभेद प्रत्येक समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित है और, (स) इन मतभेदों को समझने के लिए शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार बहु-आधुनिक बुद्धिजीवी सर्वप्रथम यूरोपीय विचारों और पदों से प्रभावित होकर आधुनिकता के विभिन्न यूरोपीय अनुभवों के अलग-अलग दृष्टिकोणों से ऐतिहासिक और दार्शनिक प्रश्न पूछते हैं। फिर यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इन भिन्नताओं के आधार पर समग्र विश्व की भिन्नताओं का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है। दूसरा, विचारक आधुनिकता की परिधि की तुलना में इसके केंद्र के घटकों को जानने की कोशिश करते हैं। आइसेनस्टेड ने तर्क दिया कि आधुनिकता का केन्द्रीय पक्ष मानव एजेंसी है। वह इस एजेंसी को स्वायत्त, तार्किक, रचनात्मक और स्वतंत्र/मुक्त मानते हैं। तीसरा, यदि मानव एजेंसी का मूल तार्किकता है, तो यह मूल दुनिया भर में अलग-अलग कैसे दिखाई देता है? आइसेनस्टेड का तर्क है कि इस मूल अर्थात् तर्कसंगत मानव एजेंसी की उत्पत्ति अक्षीय

“पश्चिमी विज्ञान की वैज्ञानिक रीतियों को बदलना आवश्यक है क्योंकि ये लोगों को अध्ययन की वस्तु बना देती हैं”

सभ्यताओं की विशिष्ट धार्मिकताओं से हुई है। हालांकि ऐसा ईसाई-यूरोपीय अक्षीय सभ्यता में हुआ था कि आधुनिकता के लक्षण/गुण पहले उभरे और बाद में फैल गए। इस पश्चिमी मॉडल को अपने मूल स्वरूप और पैटर्न में स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि प्रत्येक अक्षीय सभ्यता से ग्रहण विशेषताओं से सम्बद्ध होने के कारण इसके सांस्कृतिक गुणों में चयन, पुनःव्याख्या और सुधार किया गया था। परिणामस्वरूप, नई मूल/केंद्रीय विशेषताएं उभरीं जिनसे आधुनिकता के बाद के प्रारूपों का निर्माण हुआ। अतः संस्थानिकरण के केंद्रीय पक्षों जैसे व्यावसायिक और औद्योगिक संरचनाओं या शिक्षा और शहर की संरचनाओं के सन्दर्भ में समग्र विश्व में हमेशा रूपांतरण होगा, संस्थागत गतिशीलता और संबंधित समस्याओं के तरीकों में मतभेद होंगे क्योंकि एजेंसी और संरचना एक दूसरे के साथ सम्बद्ध होते हैं अथवा अंतःक्रिया करते हैं।

यह तर्क दिया गया कि बहु-आधुनिकता की मान्यताओं ने समकालीन सामाजिक सिद्धांत में सांस्कृतिक मोड़ उत्पन्न किया। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि आधुनिकता की इस चर्चा में भौतिक प्रक्रियाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, हालांकि, यह मान्यता ऐतिहासिकता की चर्चा करती है, कि उपनिवेशवाद, आधुनिकता के संगठन, इसकी शोषण प्रक्रिया और ज्ञान प्रणालियों विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों के साथ इसके संबंधों का कोई संदर्भ नहीं है। इन मुद्दों को समझने के लिए नीचे कुछ परिप्रेक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है।

> स्थानीय और दक्षिणी सिद्धांत

स्थानीय सिद्धांत इस मान्यता के साथ शुरू होते हैं कि समाज विज्ञानों को अपने विषयों/क्षेत्रों में ज्ञान संबंधी चिंतन परम्पराओं को तैयार करने के लिए स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। वे रायविन कॉनेल के तर्क को स्वीकार करते हैं कि मेट्रोपोल और परिधि के बीच असमान शक्ति समाज विज्ञानों को संगठित/संचालित करती है और इससे उत्तरी सिद्धांतों और उनके दृष्टिकोणों, परिप्रेक्ष्यों और समस्याओं का सार्वभौमिकरण हुआ है। दक्षिणी सिद्धांत के अंतर्गत दो अवधारणाएं इस प्रक्रिया का आकलन करती हैं। पहली, 'बहिर्मुखता' जिसे पॉलिन हंटोंडजी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिन्होंने इसे बहिर्मुखी (बाह्य-उन्मुख) समाज विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। दूसरी अवधारणा सैयद फरीद अलाटास द्वारा प्रस्तुत की गई 'अकादमिक निर्भरता'। बाद वाली अवधारणा का अर्थ है कि शेष दुनिया पर पश्चिमी ज्ञान को थोप दिया गया है। इस प्रकार यह गैर-प्रासंगिक और गैर-उपयोगी बना रहता है। अतः यह विचारक 'देशज/स्थानीय' कथाओं/संस्कृतियों के भीतर से वैकल्पिक समाजशास्त्र की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता के लिए चर्चा करते हैं।

स्थानीय सिद्धांत तर्क देते हैं कि अगर पश्चिम में समाजविज्ञान अपनी दार्शनिक विचारधाराओं/प्रणालियों के साथ सम्बद्धता के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो अन्य संस्कृतियों और दार्शनिक प्रणालियों में भी ऐसा करना संभव है। यह पश्चिम की ज्ञान सम्बन्धी चिंतन परम्परा/शक्ति को स्वयं की (स्थानीय/देशज) ज्ञान सम्बन्धी

चिंतन परम्परा से विस्थापित करना चाहता है। इनका मानना है कि यह ऐसे सिद्धांतों/अमूर्तताओं को निर्मित कर सकते हैं जो देशज/स्थानीय इतिहास और सामाजिक जीवन के प्रति संवेदनशील हैं और जो पश्चिमी/उत्तरी क्षेत्र के समाजशास्त्र द्वारा तैयार किए गए 'सार्वभौमिक समाजशास्त्र' के दायरे के बाहर समाजशास्त्र निर्मित करने के "वैकल्पिक" तरीकों को तैयार करने में मदद करते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य के भीतर तीन महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की चर्चा की जाती है। पहली प्रवृत्ति की व्याख्या नाइजीरियाई समाजशास्त्री अकिवोवो अकिन्सोला द्वारा की गई। उन्होंने पुष्टि की कि अपने लोगों की कहानियों, मिथकों और कहावतों के साथ-साथ 'शुद्ध अफ्रीकी ज्ञान के नियम' के साथ मिलकर समाजशास्त्र की रचना की जा सकती है। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नाइजीरिया की योरुबा जनजाति की कविता को केंद्र बनाकर एक सामाजिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि इस कविता के सिद्धांतों से पता चलता है कि समस्त सामाजिक जीवन की इकाई व्यक्ति है और क्योंकि व्यक्ति को 'शारीरिक रूप से अन्य व्यक्तियों की सहभागिता की आवश्यकता होती है', आम तौर पर व्यक्ति के अस्तित्व के लिए सामान्य वस्तुओं पर आधारित सामुदायिक जीवन महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में विभिन्न पद्धतियों और ज्ञान सम्बन्धी चिंतन परम्पराओं पर प्रश्न पूछे गए, जैसे एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माण के लिए लोक संस्कृति का उपयोग, इसके अनुवाद और व्याख्या से सम्बंधित 'सत्य' और क्या इसके तत्वों की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जाँच की जा सकती है।

दूसरी प्रवृत्ति ने देशज/स्थानीय अध्ययनों में अंतिम प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की - वैज्ञानिक पद्धति से जाँच करने में सक्षम होने के नाते - यह सुझाव देकर कि पश्चिमी विज्ञान ही दुनिया में एकमात्र विषय नहीं है जो वैज्ञानिक पद्धति से सम्बद्ध है। एक स्वायत्त समाज विज्ञान के लिए यह तर्क देना कि यह प्रासंगिक और महत्वपूर्ण दोनों है, सैयद फरीद अलाटास ने यह पूछकर देशज/स्थानीय सिद्धांत की समस्याओं को रेखांकित किया कि क्या विभिन्न संस्कृतियों और उनके महाद्वीपों का उपयोग नए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। उनका तर्क है कि देशज/स्थानीय ज्ञान प्रणालियों, जैसे कि इस्लाम, में वैज्ञानिक आलोचना का पक्ष है जो अनुभवजन्य कारकों के आधार पर जाँच कर सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इन सिद्धांतों का प्रयोग समाजशास्त्र करने के तरीकों को निर्मित करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। वह यहाँ यह सवाल उठाते हैं कि इस्लाम किस प्रकार इस्लामिक समाजशास्त्र या इस्लामिक भौतिकविज्ञान के बिना नए ज्ञान को निर्मित करने के लिए आध्यात्मिक और ज्ञान आधारित चिंतन परम्परा को आधार प्रदान करता है? इस तरह के हस्तक्षेप का अर्थ विज्ञान को त्यागना नहीं है, विशेषरूप से आलोचनात्मक एवं मूल्यांकनात्मक चिंतन से सम्बद्ध पक्षों को, बल्कि इसके क्षेत्र को व्यापक करना और गैर-पश्चिमी संस्कृति से आलोचना के नवीन विचारों को सम्मिलित करना है।

तीसरी प्रवृत्ति लिंडा तुहीवाई स्मिथ के स्थानीय/देशज कार्य से

उत्पन्न हुई जिन्होंने पश्चिमी विज्ञान पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया। वह तर्क देती हैं कि अपनी वैज्ञानिक परम्पराओं को विस्थापित करना जरूरी है क्योंकि ये विषय को मूल्यांकन की वस्तु बना देती हैं। पश्चिमी विज्ञान आंतरिक ज्ञान के साथ स्वयं को शामिल किये बिना विश्व के क्षेत्रों और लोगों पर 'सत्य' थोपता है। वह विज्ञान के पद्धतिशास्त्र को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता का सुझाव देती हैं और एक ऐसे विज्ञान की स्थापना का तर्क देती हैं जो व्यक्तियों, समुदाय, और जिन लोगों का अध्ययन/मूल्यांकन किया जा रहा है, के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील हो। वह शोधकर्ताओं को वस्तुपरक शोध प्रक्रियाओं की शक्ति को स्थिर करने और पददलितों/स्थानीय लोगों की आवाज़ को एकीकृत करने के तरीकों पर काम करने के लिए कहती हैं।

ये तीनों प्रवृत्तियाँ दक्षिण में अकादमिक परंपराओं की जाँच-पड़ताल करती हैं। वि-औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य ने एक अत्यधिक क्रांतिकारी स्थिति को उत्पन्न किया है जो मार्क्स के निर्देशों का अनुकरण करती है कि समाज विज्ञानों को दुनिया को बदलने की जरूरत है न कि केवल उसे प्रतिबिंबित करने की।

> वि-औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य

वि-औपनिवेशिक सिद्धांत/परिप्रेक्ष्य –जिसे उपनिवेशवादी/आधुनिकता केन्द्रित अनुसंधान कार्यक्रम भी कहा जाता है—लेटिन अमेरिकी क्षेत्र में संचालित एक बौद्धिक आंदोलन है। यह निर्भरता सिद्धांतों, उदारवादी/मुक्ति धर्मशास्त्र, और लेटिन अमेरिकी अनुभवों का प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक आंदोलन सिद्धांतों के संयुक्त परिप्रेक्ष्यों से प्रभावित था। इसका विषय-क्षेत्र व्यापक है : यह तर्क देता है कि आधुनिकता के यूरोपीय सिद्धांतों को समझने के लिए ज्ञान सम्बन्धी चिंतन परम्परा और पद्धतिशास्त्रीय आलोचना को निर्मित करना आवश्यक है ताकि नई और नवीन ज्ञान सम्बन्धी चिंतन परम्पराओं को व्यक्त किया जा सके। यह नई धारणाओं के निर्माण के माध्यम से समाज विज्ञानों में सुधार के लिए तर्क देता है जो 'विचारों की बहु सीमाओं' के लिए आधुनिकता की जांच का विस्तार कर सकता है।

यह इस सुझाव के साथ शुरू होता है कि समकालीन आधुनिकता सिद्धांतों और समाजशास्त्र में प्रमुख त्रुटि सैद्धांतिक भाषा से औपनिवेशिक अनुभवों का विलोप होना है। यह तर्क देता है कि इस अदृश्यता ने आधुनिकता के समकालीन सिद्धांतों को नृजातिकेन्द्रित बनाया है। इसे नृजातिकेन्द्रवाद का नाम दिया जाता है और इसे यूरोपीयकेन्द्रितावाद की संज्ञा दी जाती है। वि-औपनिवेशवादियों के लिए यूरोकेन्द्रितता एक ज्ञानमीमांसा है जो समाज विज्ञान की सभी शाखाओं से सम्बद्ध है, विशेष रूप से इतिहास और समाजशास्त्र के विषयों में स्पष्टतः देखा जा सकता है। यह स्थिति तीनों श्रेणियों को एकसाथ बांधती हैं: अनिबल क्विजानो द्वारा प्रस्तुत 'शक्ति की औपनिवेशिकता', एनरिक डसेल की अवधारणा 'आंतरिकता/बाह्यता' और वाल्टर मिग्नोलो द्वारा प्रस्तुत 'औपनिवेशिक भिन्नता' को। तीनों एक दूसरे को अतिव्याप्त करती हैं या कहे कि एक दूसरे से अत्यधिक सम्बद्ध है।

क्विजानो के अनुसार, शक्ति की औपनिवेशिकता दो यूरोकेन्द्रितता मिथकों पर आधारित है : उद्विकासवाद और द्वैतवाद। एक तरफ, उद्विकासवाद इतिहास को एक रेखीय विकास के रूप में

प्रस्तुत करता है, जो कि आदिम से आधुनिक तक का विवरण प्रस्तुत करता है। यह रेखीय प्रारूप यूरोपीय आधुनिकता के प्रारंभिक दौर में विकसित हुआ और विश्व के गैर-यूरोपीय इतिहासों की व्याख्या करने में प्रयुक्त किया जाने लगा। द्वैतवाद यूरोकेन्द्रितता द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक और उपकरण और मिथक है जिसके द्वारा यूरोपियन इतिहास और समाज को गैर-यूरोपीय लोगों से अलग करने के प्रयास किये जाते हैं। इस प्रकार द्वैतवाद के माध्यम से यूरोकेन्द्रितता विपरीत और युग्म अवधारणाओं के रूप में अन्य के ज्ञान को निर्मित करता है। इस युग्म अवधारणा में पदानुक्रम सम्बद्ध होता है : यह यूरोपीय इतिहास और समाज को श्रेष्ठ मानता है (यह मानते हुए कि यूरोप ने सबसे पहले आधुनिकता को निर्मित किया) और शेष को निम्न/हीन मानता है।

शक्ति की औपनिवेशिकता का तर्क है कि यूरोकेन्द्रितता (अ) भूमि विनियमन, श्रम का शोषण, प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के नियंत्रण, (ब) सेना, पुलिस, और राजनीतिक शक्ति की संस्थाओं के माध्यम से सत्ता के नियंत्रण, (स) परिवार और शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जेंडर/लैंगिकता और यौनिकता के नियंत्रण, और (द) ज्ञानमीमांसा/ज्ञान प्रणालियों के विस्तार के माध्यम से विषयपरकता और ज्ञान के नियंत्रण को उचित ठहराने के लिए सिद्धांतों का निर्माण करता है।

औपनिवेशिक भिन्नता की वाल्टर मिग्नोलो की अवधारणा (औपनिवेशिकता से आधुनिकता का विभाजन और ज्ञान में आगे के विभाजन और भिन्नता उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग) 'शक्ति की औपनिवेशिकता' द्वारा स्थापित समस्याओं से पूर्ण है और एक ज्ञानमीमांसीय उपकरण के रूप में इसका विस्तार करती है जो यूरोपीय लोगों को बौद्धिक और राजनीतिक स्पेस में विशेषाधिकार प्रदान करती है। मिग्नोलो सुझाव देते हैं कि यह अवधारणा औपनिवेशिक विश्व और उसके लोगों, उनकी कल्पनाओं और उनके ज्ञान की अधीनस्थता के उद्देश्य को समझने में मदद करती है।

एनरिक डसेल क्विजानो के उद्विकासवाद के मिथक को पुनःआकार देते हुए तर्क देते हैं कि समकालीन इतिहास को क्षेत्रीय यूरोपीय इतिहास से बाहर निकाले गए आंतरिकता के सिद्धांत के रूप में डिजाइन किया गया है ताकि यह सार्वभौमिक और रेखीय दोनों मिथकों को निर्मित कर सके। वह सुझाव देते हैं कि बाह्यता के सिद्धांत के रूप में आधुनिकता के लिए एक ऐसे शोध कार्यक्रम की आवश्यकता है जो वि-औपनिवेशीकृत दृष्टिकोण से यूरोप के बाहर के विश्व को समझने का एक तरीका प्रस्तुत कर सके। समाज विज्ञान में मौजूदा समकालीन दार्शनिक, सामाजिक, और ऐतिहासिक धारणाओं/मान्यताओं को फिर से तैयार करने और गैर-औपनिवेशिक आवाजों के आधार पर एक विकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इनका लक्ष्य बेहद महत्वाकांक्षी है : यह लक्ष्य है समाज विज्ञान की चिंतन परम्परा को पुनर्गठित करना क्योंकि यह अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गठित किया गया था और समाज विज्ञानों की नींव को पुनः तैयार करने के लिए विषयों, विशेषज्ञताओं और प्रश्नों को फिर से तैयार करने के लिए नए शोध एजेंडे तैयार करना। ■

सभी पत्राचार सुजाता पटेल को <patel.sujata09@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> (कहां) हम मायने रखते हैं? पोलिश समाजशास्त्र पर पार्श्व दृष्टि

मार्टा बुकोल्क, बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी और वारसो विश्वविद्यालय, पोलैंड के द्वारा



लियोन पेत्राज्जकी एवं फ्लोरियन जैनिनी
पोलिश समाजशास्त्र की दो प्रमुख हस्ती।

पोलैंड में समाजशास्त्र का इतिहास शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय अनुवर्तन और स्थानीय सलंगनता के बीच तनाव से चिन्हित था। तनाव में बातचीत मुश्किल है, क्योंकि यह इसकी अनुशासनात्मक पहचान की नींव पर गहराई से छूता है और शोध, सैद्धांतिकरण, संस्थानीकरण और जीवनात्मक रणनीतियों में अनुवादित होता है।

तनाव की सततता आंशिक रूप से इस तथ्य की वजह से है कि पोलैंड में समाजशास्त्र अनिवार्य रूप से विदेश से आयतित था। हालांकि अठाहरवीं और उन्नीसवीं सदी (खुद देश इस अवधि के सर्वोत्तम भाग में किसी रूप में मौजूद नहीं था) के उत्तरार्ध में पूर्व पोलिश प्रदेशों में बहुत सा मौलिक सामाजिक विचार था, यह

आमतौर पर निजी विज्ञान था। जब बहुत से देशों में एक ही समय पर समाजशास्त्र का संस्थानीकरण शुरू हुआ, नया विज्ञान जल्दी से कुछ विशिष्ट रेखाओं के पास विकसित होना शुरू हो गया। यह ज्ञान के परिसंचरण और पारस्परिक उलझनों से चिन्हित थे जिन्हें प्रायः राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय परंपराओं की तरह जाना जाता है। सामाजिक विज्ञानों का पूर्वप्रभावी राष्ट्रीयकरण *लिओन पेद्राज्जकी* या *लुडविक गंपलोविक* जैसे लेखकों के योगदानों के आकलन को मुश्किल बना देता है। उनकी अत्यधिक मौलिक अवधारणायें उनके परिवेश के स्थानीय संज्ञानात्मक और राजनीतिक हितों की अंतःक्रिया के अनुरूप थी, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में उनकी सहभागिता को भी प्रतिबिंबित करती थी। दूसरी ओर, कुल मिलाकर सामाजिक विज्ञानों के विकास पर केंद्रीय

और पूर्वी यूरोप के विद्वानों का प्रभाव अनुपातहीन रूप से बिल्कुल बड़ा था क्योंकि 1918 से पहले साम्राज्यवादी यूरोप में वैज्ञानिक नेटवर्कों की पहुंच में बाधाएँ अपेक्षाकृत कम थीं।

स्थानिक और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय दोनों में निहित हितों का यह दोहरा अनुभव पश्चिम में शिक्षित प्रारंभिक पोलिश अकादमिक समाजशास्त्रीयों में भी बहुत था, विशेषतः *फ्लोरियन जैनिनी* और *स्टीफन जारनोवस्की*, जिनकी गतिविधियाँ पुर्नसृजित पोलिश राष्ट्र-राज्य में विकसित हुयी। तब तक, पश्चिमी समाजशास्त्र सार्वभौमिक हो चुका था: एक नया विज्ञान, नयी सोचने की शैली, कैरियर की नई राह, नया बौद्धिक फैशन, और नीति-निर्माण में एक सराहनीय साथी। इस नवीनता के लिये लालच देने के एक भाग का एक स्पष्ट

अतिरिक्त प्रोत्साहन था जो इसे अवशोषित कर पश्चिम के साथ एक संचार माध्यम बनाये रख रहा था। पोलिश संस्कृति में पूरी उन्नीसवीं सदी में संबद्धता के लिये एक खोज को एक कहानी के रूप में कहा जा सकता है जो स्थानीय सीमाओं से आगे निकल जायेगी। एक समाजशास्त्री बनना इस लक्ष्य को पूरा करने का एक तरीका था।

जबकि 1920 और 1930 के दशकों में पोलिश अकादमिक समाजशास्त्रीयों की पहली पीढ़ी ने पश्चिमी समाजशास्त्र को स्टॉक-इन-ट्रेड की तरह स्वीकार कर लिया, उनके उत्तराधिकारियों के लिये अब यह इतनी सामान्य बात नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध और स्टालिनवाद के अंधेरे समय में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संपर्क कट गया था और स्थानीयकरण और हाशियाकरण की उलट संबद्धता और अनुवर्तन की समस्याओं ने स्वयं को बहुत तीखे रूप से प्रस्तुत किया। जब 1950 के दशक में, पोलिश समाजशास्त्र फिर से खुला, संबद्धता की रणनीति को परिष्कृत किया जाना था। सौभाग्य से, यह पता चला कि पश्चिम के लिये समाजवाद के तहत पोलिश समाज आकर्षक था, और दो दुनियाओं को जोड़ना समाजशास्त्रीयों के लिये एक मिशन बन गया था – सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच अत्यधिक महानगरीयता और पश्चिम-उन्मुखता – जिन्होंने पूर्वी भाग के अन्य देशों में रहने वाले लोगों की तुलना में स्वतंत्रता का बहुत आनंद लिया। तीन दशकों से भी अधिक के लिये, संबद्ध होने का सबसे अच्छा तरीका सिद्धांत (सोवियत मानकों से दूर घर में बना पोलिश मार्क्सवाद के शक्तिशाली प्रभाव के साथ) में उदार बनना और अनुसंधान में स्थानीय रूप से उन्मुख होना था। पश्चिम बेदंगी अंग्रेजी, अजीब अकादमिक लेखन, सैद्धांतिक गठन में अंतर, और अक्सर अधिक अपरिष्कृत पद्धतिशास्त्र को आसानी से माफ कर देगा, क्योंकि वह समय यह जंगली पूर्व के आश्चर्यजनक रूप से सभ्य अजनबियों के लिये बहुत स्वागत करने वाला था। यदि बीसवीं सदी में कोई समय होता जो एडवर्ड

सेड के अर्थ में पोलिश समाजशास्त्र पूर्वोक्त था, यह संभवतः तब था। दूसरी ओर, कुछ समाजशास्त्री, केवल उल्लेख करने के लिये *स्टनिसलॉ ऑसोवस्की* ने एक समय में दो दुनियाओं से संबद्ध होने के कौशल का अभ्यास करने में कामयाब रहे।

यह प्रवृत्ति – जहां पोलिश समाजशास्त्री होने के कारण एक व्यक्ति अपने आप सार्वभौमिक वैद्यता और अंतर्राष्ट्रीय अनुवर्तन का दावा कर सकता था – ने 1980 के दशक में अपनी पराकाष्ठा देखी। यह इसलिये था क्योंकि पोलिश इलाके, 'सोलिडरानोस्क' के हॉलमार्क के साथ, बहुत स्पष्ट रूप से वैश्विक तौर पर महत्वपूर्ण थे। यह सैद्धांतिक रूप से प्रेरणादायी और आनुभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण भी था। परंतु नवीनता का प्रभाव जल्दी ही खत्म हो गया। सौभाग्य से, दस वर्षों से भी कम में, अंतर्राष्ट्रीय अनुवर्तन का दावा करने का एक नया मौका व्यवस्थित परिवर्तन के साथ आया: 1989 के बाद, हर किसी की रूचि इसमें थी, जबकि पोलैंड अन्य उत्तर-समाजवादी देशों का सिर्फ एक साथी यात्री था, ना कि इसके स्वयं के अधिकार में एक प्रकार का समाज।

बोलने के तरीके में, पोलिश समाजशास्त्र को देश में हाल के लोकतांत्रिक पतन के लिये आभारी होना चाहिये। 2015 के साल ने पोलिश परिवर्तन में मुरझाती रूचि को पुनर्जीवित किया। विदेश में, हमें पूछा जाता है कि 1989 के बाद क्या गलत हुआ, और इस अनिवार्य रूप से स्थानीय प्रश्न का जवाब देते हुये, हम फिर से लोकतंत्र के संकट, और कानून के शासन, सांस्कृतिक युद्धों, और आंदोलन-विरोधी लोकलुभावनवाद पर सामान्य बहस में योगदान देने में सक्षम हो जाते हैं। हमारा इलाका एक बार पुनः सभी के लिए कारगर है।

परंतु आइये मान लेते हैं कि लोकतंत्र-विरोधी प्रतिक्रिया को संभाला जा सकता है और राजनीतिक स्थिरता को बहाल किया जा सकता है, और यह कि

पोलिश समाज उस चरण में फिर से प्रवेश करता है जहां यह 2007 के बाद पंहुच गया लगता था : नीरस स्थिरीकरण। हम फिर किस काम में लगे हैं? पोलिश समाजशास्त्र अब तक काफी हद तक एक स्वघोषित असामान्य समाज, वास्तविक और काल्पनिक विचलनों दोनों में एक स्वप्रेरित शोधकर्ता का विज्ञान था। हमें पोलिश अपवादिता पर पोषित किया गया, परंतु एक चीज की हमें अपने समाज के लिये सच में आशा करनी चाहिये वो यह है कि हमें अपवाद बनना अंततः बंद कर देना चाहिये। हालांकि, इसका मतलब यह होगा कि हमें सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण बनने की एक सौ साल पुरानी अनिवार्यता से निबटने के अन्य रास्ते ढूँढने होंगे।

चुनौती तुच्छ नहीं है। उन्नीसवीं सदी के बुद्धिजीवियों की नैतिक दुविधाओं में निहित अंतर्राष्ट्रीय अनुवर्तन के पुराने दवाब ने उच्च शिक्षा और विज्ञानों के नवउदारवादी प्रबंधन से अप्रत्याशित समर्थन प्राप्त किया है, जिसमें वर्तमान राष्ट्रीय रूढ़िवादी सरकार ने अपने उदारवादी पूर्ववर्तियों से सुचारु रूप से पदभार ले लिया। मेरी पुस्तक *पोलैंड में समाजशास्त्र: जारी रहेगा?* (2016) में, मैंने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवर्तन और स्थानीय सलग्नता के बीच तनाव का सामना करना ही पोलिश समाजशास्त्र के सामने जीवित रहने और महत्व का बने रहने का एकमात्र तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवर्तन के काल्पनिक पुरस्कार के आकर्षण का प्रतिरोध, उस उद्देश्य के लिये साधन की तरह महत्वपूर्ण है जैसे कि यह सरल अहसास कि हमारा स्वयं का समाज हमारे लिये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह दूसरों के लिये अद्वितीय है। ■

1. लेखक पोलिश राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के सहयोग के लिये आभार व्यक्त करते हैं।

सभी पत्राचार मार्टा बुकोल्क को <mbucholc@uni-bonn.de> पर प्रेषित करें।

> जर्मनी और पोलैंड में युवा अनिश्चित श्रमिक

जेन जारज़ास्ती, और जूलियसज गार्डावस्की, वॉरसॉ स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स, पोलैंड
एडम मरोजाविकी, रॉकलॉ विश्वविद्यालय, पोलैंड और श्रम आंदोलनों पर आईएसए शोध समिति के सदस्य (आर.सी. 44)
और वेरा ट्रैपमन्न, लीडस विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा



इस बात के बहुत सारे सबूत हैं कि यूरोप की युवा पीढ़ी अपने जीवन में अस्थायी और अनैच्छिक अंशकालिक रोजगार, गिरते ट्रेड यूनियनों के घनत्व, और मुश्किल विद्यालय से कार्य परिवर्तन से उपजती अधिकाधिक अनिश्चितता का अनुभव करती है। प्रीवर्क परियोजना दो यूरोपीय देशों, जर्मनी और पोलैंड पर केंद्रित है। जर्मनी, समेकित बाजार अर्थव्यवस्था (सीएमई, जैसा हॉल और सॉक्सिस इसे कहते हैं) पारंपरिक रूप से श्रमिकों की सुरक्षा, संस्थागत तरीके से सुनिश्चित करने लिये जानी जाती है, का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी, 2000 के श्रम बाजार सुधारों ने यहां भी एजेंसी काम के विस्तार, अस्थायी काम में बढ़ोतरी, श्रम बाजार दोहरीकरण, वेतन ठहराव, और ट्रेड

यूनियनों से सौदेबाजी में योगदान दिया। पोलैंड में, उदारवादी बाजार अर्थव्यवस्था (एलएमई) के करीब होने के कारण, रोजगार अनिश्चितता की हाल की लहरें श्रम बाजार लचीलेपन के उद्देश्य से किये गये कानून सुधारों से उपजी।

दोनों देशों में, युवा लोग श्रम बाजार में वंचित हैं, जिसमें अस्थायी रोजगार का उच्च स्तर (पोलैंड में), गरीबी की बढ़ता जोखिम और गरीबी में काम (जर्मनी में), और दोनों देशों में आर्थिक अपवर्जन का अधिक जोखिम शामिल है। हम मानते हैं कि युवा अनिश्चितता को अनिश्चित रोजगार; निर्वाह मजदूरी, सामाजिक सन्निहितता और पूर्ण सामाजिक अधिकार के नुकसान; और मान्यता और सामाजिक एकीकरण के

नुकसान से पैदा हुई अनिश्चितता की व्यक्तिपरक भावना के मामले में देखा जा सकता है। हालांकि, इन नकारात्मक घटनाओं के बावजूद, अनिश्चितता के खिलाफ युवाओं का सामूहिक आंदोलन सीमित है और जीवन से उनकी समग्र संतुष्टि काफी अधिक बनी हुई है। यह प्रश्न उठता है: बढ़ती हुई अनिश्चित काम करने की परिस्थितियों, सामाजिक चेतना और युवाओं की जीवन रणनीतियों के मध्य क्या संबंध है? क्या पोलैंड और जर्मनी में अनिश्चितता को युवाओं द्वारा एक समस्या की तरह लिया जाता है? या वे इसे एक प्रतिमान की तरह देखते हैं, अपने कामकाजी माहौल के एक अपेक्षित हिस्से के रूप में जिससे एक व्यक्ति को अनुकूलन की आवश्यकता है?

ग्रीवर्क दो स्तरों पर उत्तर दूढ़ता है: (1) पोलैंड और जर्मनी में बहुत बड़े (प्रत्येक देश से 1000 के नमूने पर) 18 से 30 आयु के लोगों के यादृच्छिक प्रतिदर्शों पर सीएटीआई सर्वेक्षणों के माध्यम से अनिश्चित श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक चेतना के विभिन्न आयामों पर अस्थिर कार्य और रहने की स्थितियों के प्रभावों के अध्ययन के द्वारा; और (2) युवाओं की जीवन रणनीतियों/कॅरियर प्रतिमानों और बढ़ते अनिश्चित रोजगार और सामूहिक आंदोलनों (और वि-आंदोलनों) के प्रकारों के मध्य संबंध के अध्ययन के द्वारा। ऐसा वे पोलैंड (60) और जर्मनी (60) में युवा अनिश्चित श्रमिकों जो 18 से 35 वर्ष की आयु के, गैर मानक रोजगार, बेरोजगार या वीडिटी (व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण) के अनिश्चित स्वरूपों में हैं के 120 भी अधिक जीवनी वर्णन साक्षात्कारों के माध्यम से करते हैं।

यह अध्ययन अभी चल रहा है परंतु कुछ अस्थायी अवलोकन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। संख्यात्मक शोध अनिश्चितता के व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालता है: 48.8 प्रतिशत पोलैंड के कामकाजी युवाओं और जर्मनी के 31 प्रतिशत कामकाजी युवाओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने अनिश्चित परिस्थितियों में काम किया है, जिसे उन्होंने कम आयु पाने और अल्पकालिक अनुबंधों के रूप में परिभाषित किया। फिर भी, दोनों देशों के युवाओं की आर्थिक चेतना में भिन्नता थी।

हमारी उम्मीदों के विपरीत, पोलैंड और जर्मनी के युवाओं के अनिश्चित प्रस्थिति का अर्थव्यवस्था के आदर्श दृष्टिकोण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। हमने सोचा कि गैर-स्थायी अनुबंध होने का अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप के लिये और समानतावाद के लिये मजबूत समर्थन के रूप में प्रभाव पड़ेगा। हमारे शोध में इस्तेमाल सूचक में 15 चर शामिल हैं। पोलैंड में, सिर्फ पांच चरों ने स्थायी अनुबंध वाले व्यक्तियों और अस्थायी अनुबंध वाले व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं में सांख्यिकीय अंतर दिखाया। इसके अलावा, गैर-स्थायी अनुबंधों वाले कर्मचारियों ने स्थायी अनुबंध वाले लोगों की तुलना में कुछ आयामों में अधिक उदार अभिवृत्ति दिखायी। जर्मनी में, अंतर स्पष्ट हैं। गैर-स्थायी अनुबंधों वाले लोग इटाटिस्ट सिद्धांतों के लिये थोड़े कम समर्थन में होते

हैं (33.8 प्रतिशत बनाम 24.8 प्रतिशत), जबकि सामाजिक समानतावाद की ओर अक्सर थोड़ा झुकाव रखते हैं (क्रमशः 69.1 प्रतिशत बनाम 65 प्रतिशत)। पोलैंड के युवा लोगों के आर्थिक विचार 'घरेलू पूंजीवाद' (पोलिश कंपनियों और राज्य विनियमित अर्थव्यवस्था के लिये पंसद) के लिये मजबूत समर्थन के साथ अपेक्षाकृत दृढ़ अत्यधिक उदार झुकाव का एक संयोजन है। 12.3 प्रतिशत जर्मन लोगों के तुलना में 53.4 प्रतिशत पोलिश साक्षात्कार देने वालों ने अनिवार्य वृद्धावस्था पेंशन के बजाय स्वैच्छिक को पसंद किया। कार्य पर सहनिर्धारण के लिए समर्थन, कर नीति द्वारा आय अंतर का मुआवजा, और यूरोप में श्रमिकों की मुक्त आवाजाही के साथ (66.6 प्रतिशत पोलैंड की तुलना में 88.7 प्रतिशत जर्मन साक्षात्कारदाताओं के द्वारा समर्थित) युवा जर्मन लोगों की आर्थिक चेतना समेकित बाजार अर्थव्यवस्था (सीएमई) के करीब है। कुछ चित्तग्राही असंगतताओं के बावजूद युवा पोलैंड के विचार उदार बाजार अर्थव्यवस्था (एलएमई) के करीब हैं।

गुणात्मक शोध हमें काम से संबंधित अनुभवों को जीवनी रूप के खाके में और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हमने कार्य से संबंधित जीवन रणनीतियों के छः विभिन्न प्रकारों का पुर्ननिर्माण किया है, जो अनिश्चितता से निपटने के रूपों से विभिन्न प्रकार से जुड़े हुए हैं। 'श्रमिकों' – स्थिर और पूर्वकथनीय रोजगार के लिये इच्छुक अनिश्चित नीले कॉलर श्रमिकों के लिये – व्यवसायिक लचीलापन मानक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, परंतु जीवन के अन्य, गैर कार्य संबंधिक क्षेत्रों में स्थिरता की खोज करने के माध्यम से और साथ-साथ अपनी आकांक्षाओं को सीमित करके अनुकूलित और सामना कर लेते हैं। 'व्यवसायिक' आमतौर पर सफेद कॉलर श्रमिक जो उच्च आय और अच्छे कॅरियर संभावनाओं वाली एक स्थिर, पूर्णकालिक नौकरी चाहते हैं, या तो अनिश्चितता को श्रम बाजार में परिवर्तन के लिये आवश्यक अनुभव के रूप में वैद्यता दे देते हैं या मुख्यतः वृद्ध आयु समूहों में, व्यक्ति के जीवन परियोजना को अवरुद्ध करने के लिये आलोचना करते हैं। अक्सर एनजीओ, रचनात्मक व्यवसाय और सांस्कृतिक क्षेत्र में परियोजना आधारित कार्य करते हुये, एक अलग दृष्टिकोण 'रचनात्मकों' द्वारा प्रदर्शित होता है, जो लचीलेपन को

कार्पोरेट और फैक्ट्री नौकरियों की दिनचर्या से स्वतंत्रता के आवश्यक मूल्य के रूप में देखते हैं। विभिन्न उद्यमशील परियोजनाओं के साथ प्रयोग करने वाले 'ब्रिकोलरस्' के लिये, अनिश्चितता को नियोक्ताओं, परिवार या राज्य सहायता से स्वतंत्रता की आवश्यक कीमत के रूप देखा गया है। अंत में, यहां 'अवरुद्ध' प्रकार है, अनिश्चितता के लिये आलोचनात्मक, परंतु मनोवैज्ञानिक समस्याओं और/या सुरक्षा के लिये जीवनी भुगतान करना नामंजूर करने के कारण सक्रियता से इसका विरोध नहीं करते हैं, और 'वापस लिया गया' प्रकार जो नियमित रोजगार की दुनिया से सूचनार्थियों की दूरी की विशेषता रखता है, जिसने जीवनी महत्ता खो दी है या कभी हासिल ही नहीं की।

संख्यात्मक और गुणात्मक अन्वेषण तदनुसार साफ करते हैं कि दोनों देशों के युवा लोग अनिश्चितता महसूस करते हैं परंतु आमतौर पर अपनी अनिश्चितता की आलोचना या उसको चुनौती नहीं देते हैं। अधिकांश युवा लोग अनिश्चितता के आदी हो गये लगते हैं, या तो अपनी जीवन चरण को देखते हुये या अपने निवेश के कारण जो उन्हें अंततः फायदा देगा, इसको अस्थायी रूप से देखते हैं। आलोचना कमजोर है और शायद ही कभी राजनीतिक या यूनियन आंदोलन की ओर ले जाती है। दूसरे शब्दों में, हम अनिश्चितता के चल रहे 'सामान्यीकरण' को देख रहे हैं, जो कई युवाओं द्वारा अर्ध-प्राकृतिक स्थिति की तरह माना जाता है। ■

1. यह लेख पोलैंड के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा वित्त पोषित ग्रीवर्क परियोजना "पोलैंड और जर्मनी में युवा अनिश्चित श्रमिक: रहने और कार्य करने की स्थितियों, सामाजिक चेतना और नागरिक जुड़ाव पर एक तुलनात्मक समाजशास्त्रीय अध्ययन" के तहत तैयार किया गया था। शोध टीम में जर्मनी के वेरा ट्रैपमन्न, ज्यूल मैरी लोरेंजन, एलेक्जेंड्रा सीहोस, और डेनिस न्यूमन्न शामिल हैं। पोलिश टीम में जूलियसज गार्डवस्की, एडम मरोजाविकी, जेन जारजैस्टी, एलेक्जेंड्रा झेबिना रोजविकज, जैसेक ब्रस्की, मैटयूज कैंरोलैक, अगाता क्रसोवस्का शामिल हैं।

सभी पत्राचार एडम मरोजाविकी (संवादी लेखक) को <adam.mrozowski@uwr.edu.pl> पर, जेन जारजैस्टी को <jczarz@sgh.waw.pl> पर, जूलियसज गार्डवस्की को <jgarda@sgh.waw.pl> पर, वेरा ट्रैपमन्न को <V.Trappmann@leeds.ac.uk> पर प्रेषित करें।

> लोग दक्षिणपंथी दलों को मत क्यों देते हैं?

कतारज्याना देबस्का, सारा हरसिजंस्का, जुस्तयना कोसिंस्का एवं कमिल ट्रेप्का,
वारसो विश्वविद्यालय, पोलैंड द्वारा

लोकप्रिय समर्थन के बावजूद पीआईएस सरकार ने व्यापक प्रतिरोधों को उकसाया।
पिलकर/प्लेटफोर्मा ओबीवातेत्सका आरपी।
कुछ अधिकार सुरक्षित।

जैसा अर्ली होचस्चिल्ड ने 2016 में वैश्विक संवाद में समझाया, इस लेख के शीर्षक में पूछे गये प्रश्न के उत्तर समाजशास्त्रियों को न सिर्फ आर्थिक प्रक्रियाओं और उभरती सामाजिक भावनाओं में बल्कि इन दलों के समर्थकों की जीवनियों में भी खोजने की आवश्यकता होगी। इसी तरह का अंतर्ज्ञान हमारी शोध टीम (जिसमें लेखकों के अलावा प्रमुख शोधकर्ता के रूप में प्रोफेसर मासीज गदुला और स्टेनिसला चंकोस्की, माजा गलोवाका, जोफिया सिकोरस्का एवं मिकलोज रिस्का सम्मिलित थे) जिसने 2015 से पोलैंड में सत्ताधारी पार्टी लॉ एण्ड जस्टिस (पीआईएस) के बढ़ते समर्थन के कारणों का अन्वेषण किया, को भी आया। लॉ एण्ड जस्टिस को सामाजिक रूप से रूढ़िवादी पार्टी समझा जाता है : मूल्यों और आर्थिक आयामों के संदर्भ में रूढ़िवादी। यद्यपि इस यूरोस्केप्टिक और राष्ट्रीय सरकार ने यूरोपीय संघ और पोलिश समाज के अधिक हिस्सों, दोनों की काफी आलोचना का सामना किया है, इसका समर्थन निरन्तर बढ़ रहा है : 2017 के अंत में हुए चुनावों में यह 50 प्रतिशत पहुंच गया।

> हमारे अध्ययन का परिचय

हमारा अध्ययन मध्य पोलैंड के एक काउंटी शहर में किया गया था जिसे हमने मियास्तको (पोलिश में छोटा शहर) का नाम दिया। सत्तारूढ़ दल को 2015 में देशभर में मियास्तको में देशभर में प्राप्त 37.6 प्रतिशत मतों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। हमारी रिपोर्ट इस तरह प्रकाशित हुई : 'मियास्तको में अच्छा परिवर्तन : एक छोटे शहर के परिपेक्ष्य से पोलिश राजनीति में नव-सत्तावाद'। पीआईएस नेताओं ने



2015 के राष्ट्रपति अभियान के प्रारम्भ से ही 'अच्छे परिवर्तन' की धारणा को काम में लिया है।

पीआईएस समर्थकों के राजनैतिक संकल्पों का पता लगाने के लिए हमने मियास्तको निवासी 30 उत्तरदाताओं में से प्रत्येक के साथ दो साक्षात्कार आयोजित किये : पहला साक्षात्कार जीवन संबंधी था और दूसरा गर्भपात या कल्याण राज्य नीतियों जैसे मुद्दों पर उनके विचारों से संबंधित था। हमारी पद्धति पियरे बोर्द्यू के वर्ग भेद के सिद्धान्त और मासीज गदुला और प्रिज्मिस्ता सदुला द्वारा उसके पोलिश रूपांतरण पर आधारित थी। हमने अपने उत्तरदाताओं को दो समूहों में विभाजित किया : श्रमिक वर्ग एवं मध्यम वर्ग। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमने तथाकथित 'परिवर्तन में हारे', 1989 के बाद के पूंजीवादी परिवर्तनों के तहत खराब प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए एक सम्बोध, व्यक्तियों के साक्षात्कार नहीं लिए।

> दो अत्यधिक विवादास्पद विषय : गर्भपात एवं शरणार्थी

श्रमिक वर्ग के साक्षात्कारदाताओं ने आमतौर पर गर्भपात पर पूर्ण प्रतिबंध का विरोध किया। बड़ी उम्र की श्रमिक महिलाओं ने मौजूदा गर्भपात विरोधी कानून के उदारीकरण का पक्ष लिया। मध्यम वर्ग की महिलाओं ने आम तौर पर महिलाओं के

लिए चुनने की स्वतन्त्रता की आवश्यकता के लिए तर्क दिये और एक रूग्ण बच्चे के लालन-पालन के बोझ पर बल दिया। हमारे कुछ साक्षात्कारदाताओं के गर्भपात-विरोधी नियमों के संभावित उदारीकरण के प्रति उल्लेखनीय खुलेपन के बावजूद, आमतौर पर गर्भपात के खिलाफ एक मजबूत आवाज दिखाई दी।

हमारे अधिकांश साक्षात्कारदाता पोलैंड में शरणार्थियों को स्वीकार करने के खिलाफ थे। श्रमिक वर्ग के साक्षात्कारदाता तर्क देते हैं कि शरणार्थी काम नहीं करना चाहेंगे और सामाजिक लाभों की अपेक्षा करेंगे। उन्होंने सामाजिक देखभाल की पोलिश प्रणाली तथा उनके द्वारा प्राप्त किये जा सकने वाले लाभों के परिणामस्वरूप होने वाले अन्याय के खतरों को उजागर किया। उन्होंने शरणार्थियों की स्थिति को युद्ध से जोड़ा और आमतौर पर स्वीकारा कि उन्हें मदद मिलनी चाहिए लेकिन वे उनकी पालिश सीमा में मदद करने के खिलाफ थे। सिर्फ दो ने कहा कि शरणार्थियों को पोलिश समाज में स्वीकार करने से किसी को नुकसान नहीं होगा — पूर्व सरकार द्वारा कम संख्या को स्वीकार करने के प्रस्ताव के कारण।

मध्यम वर्ग के साक्षात्कारदाताओं ने दावा किया कि अक्सर प्रवेशक अलग संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और पोलिश एवं

यूरोपीय संस्कृति के नियमों को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं होते हैं। युद्ध से बचने वालों के साथ एकजुटता और पोलिश समाज के साथ युद्ध और राजनैतिक अस्थिरता के उनके समान अनुभव को बहुत विरले ही वर्णित किया गया। मध्यम-वर्ग के साक्षात्कारदाताओं के अनुसार, शरणार्थियों को जहां हैं वहीं रहना चाहिए, जहां उनकी अपनी जगह हो। कुछ के लिए, यूरोप का विचार अपवर्जन द्वारा परिभाषित था, यूरोप की शुद्धता की रक्षा करने के लिए आवश्यक है कि शरणार्थियों, अपनी धार्मिकता और प्रजातीय पृष्ठभूमि से पहचाने जाने वालों को बाहर छोड़ देना चाहिए। हमारी मध्यम वर्ग की महिला साक्षात्कारदाता द्वारा प्रस्तावित एक समाधान में सीमाओं में व्यवस्था और उसे खाली रखने का भाव दिखाई देता है : यदि शरणार्थियों को पोलैंड में रहना आवश्यक है, तो उन्हें पोलिश समाज से विलग रखना होगा।

> विधि-शासन की लोकतांत्रिक संस्थाओं का विनाश

दिसम्बर 2015 में, सरकार ने संवैधानिक ट्रिब्यूनल, जिसका क्षेत्राधिकार यह देखना है कि कानून पोलिश संविधान के अनुसार है या नहीं, के कार्य को बाधित करना शुरू किया। पिछली सरकार ने विधायी चुनाव से सिर्फ एक माह पूर्व सितम्बर 2015 में संवैधानिक ट्रिब्यूनल के पांच न्यायाधीशों का निर्वाचन किया था। तत्कालीन संसदीय बहुमत वाली, रूढ़िवादी उदार नागरिक मंच और किसान पार्टी के गठबंधन को तीन न्यायाधीशों के चुनाव करने का अधिकार था लेकिन उन्होंने पांच चुन लिये। इस तथ्य के बावजूद कि ट्रिब्यूनल ने तीन न्यायाधीशों (कानूनी रूप से निर्वाचित) के चुनाव को कायम रखा और दो न्यायाधीशों (अवैध रूप से निर्वाचित) के चुनावों को खारिज कर दिया, नई पीआईएस वर्चस्व वाली संसद ने पांच नये न्यायाधीशों को नामित किया और ट्रिब्यूनल के फैसलों के प्रकाशन पर रोक लगा दी। राष्ट्रपति आंद्रेज दुदा द्वारा नव निर्वाचित न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण ने न केवल एक संवैधानिक संकट को बल्कि वारसों और अन्य मुख्य पोलिश शहरों में सड़क प्रदर्शनों को प्रेरित किया। क्या संवैधानिक ट्रिब्यूनल से सम्बन्धित सरकार के उपाय वैध थे या नहीं, प्रश्न का उत्तर वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि कट्टरपंथी आधार पर बंटा हुआ था : पीआईएस समर्थक अपनी कार्यवाही के पक्ष में थे और दावा कर रहे थे कि इसने कथित तौर पर नागरिक मंच-वर्चस्व वाले

ट्रिब्यूनल की 'बहुलता' को बहाल किया, उनके विरोधियों के लिए ये उपाय लोकतंत्र पर हमला थे और यह सरकार पर किसी भी संवैधानिक नियन्त्रण को निलंबित करने का सफल प्रयास था।

> वीआईएस सामाजिक नीति : "500+ परिवार" कार्यक्रम

"500+ परिवार" कार्यक्रम को अप्रैल 2016 में पीआईएस सरकार की सामाजिक नीति के एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया था। निश्चित रूप से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक उपायों में से एक है। यह एक सार्वभौमिक बाल लाभ कार्यक्रम है; प्रत्येक परिवार के दूसरे और तीसरे बच्चे के लिए 500 ज़्लाटिस (लगभग 120 यूरो) प्राप्त होते हैं (निर्धन परिवारों को पहले बच्चे के लिए भी यह राशि प्राप्त हो सकती है)। इसका क्रियान्वयन कम्प्यूनिस्ट-पश्चात के पोलैंड में उल्लेखनीय परिवर्तन को इंगित करता है : 1989 से यह प्रथम बार है कि पोलिश राज्य ने बड़े पैमाने पर मध्यम और श्रमिक वर्ग दोनों को लाभान्वित करने वाला पुनर्वितरण प्रयास को लागू किया है।

अधिकांश प्रतिभागियों ने बाल लाभ के क्रियान्वयन का समर्थन किया, एकमात्र अपवाद उदारवादी विपक्ष के कुछ मध्यम वर्ग अनुयायी थे जिन्होंने इसे 'वोट खरीदने' का एक तरीका माना। लाभों के पक्ष में मध्यम वर्ग के साक्षात्कारदाताओं का बहुमत था जो लाभों को प्रारम्भ करने को देश की नई ताकत के प्रतीक के रूप में देखते हैं। बाल लाभों का भुगतान करने को एक अतिव्यय के रूप में नहीं बल्कि इसे पश्चिम के सुविकसित देशों के एक 'सामान्य' उपाय के रूप में और यह संकेत कि पोलैंड भी उनसे जुड़ रहा है, के रूप में देखा गया। श्रमिक वर्ग भी बाल-लाभों के पक्ष में थे, यद्यपि उनके एक विशिष्ट भाग ने इस प्रस्ताव के लिए भी समर्थन व्यक्त किया कि स्थानीय अधिकारियों को कुछ प्राप्तकर्ताओं के लाभ व्यय को नियंत्रित करना चाहिए।

> पीआईएस समर्थन के कारण बहुस्तरीय हैं

लॉ एण्ड जस्टिस अपने पुनर्वितरण कार्यक्रम को जीवन्त बनाकर शासन के एक नये मॉडल का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे शोध ने पाया कि पीआईएस के समर्थक जनमत में माने जाने से कहीं अधिक भिन्न हैं। इस लेख में ये सामाजिक अन्तर क्या हैं और किन कारकों को हम दक्षिणपंथी दलों के उदय के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं

का पता लगाने का प्रयास करते हैं।

हमारे शोध ने दर्शाया कि सिर्फ निर्धन के लिए वित्तीय सहायता ने ही पीआईएस के लिए समर्थन का ट्रिगर नहीं किया है। इसके बजाय, यह इसलिए सफल है क्योंकि इसके कार्य सभी वर्गों की विभिन्न जरूरतों और मूल्यों को अपील करते हैं। श्रमिक वर्ग की गरिमा और मान्यता/पहचान की जरूरत का उत्तर पीआईएस राजनेता सार्वजनिक लागत पर 'कुलीन वर्ग' के असीमित खपत की आलोचना कर के देते हैं। वे मध्यम वर्ग की सम्प्रभुता और व्यवस्था की इच्छा के विन्यास के बारे में भी कहते हैं। हमारे अध्ययन ने एक बहुत रोचक पैटर्न का खुलासा किया : राजनैतिक अभिमत और घोषणाएं हमेशा साक्षात्कारदाताओं के निजी अनुभवों से अतिच्छादित नहीं होती हैं।

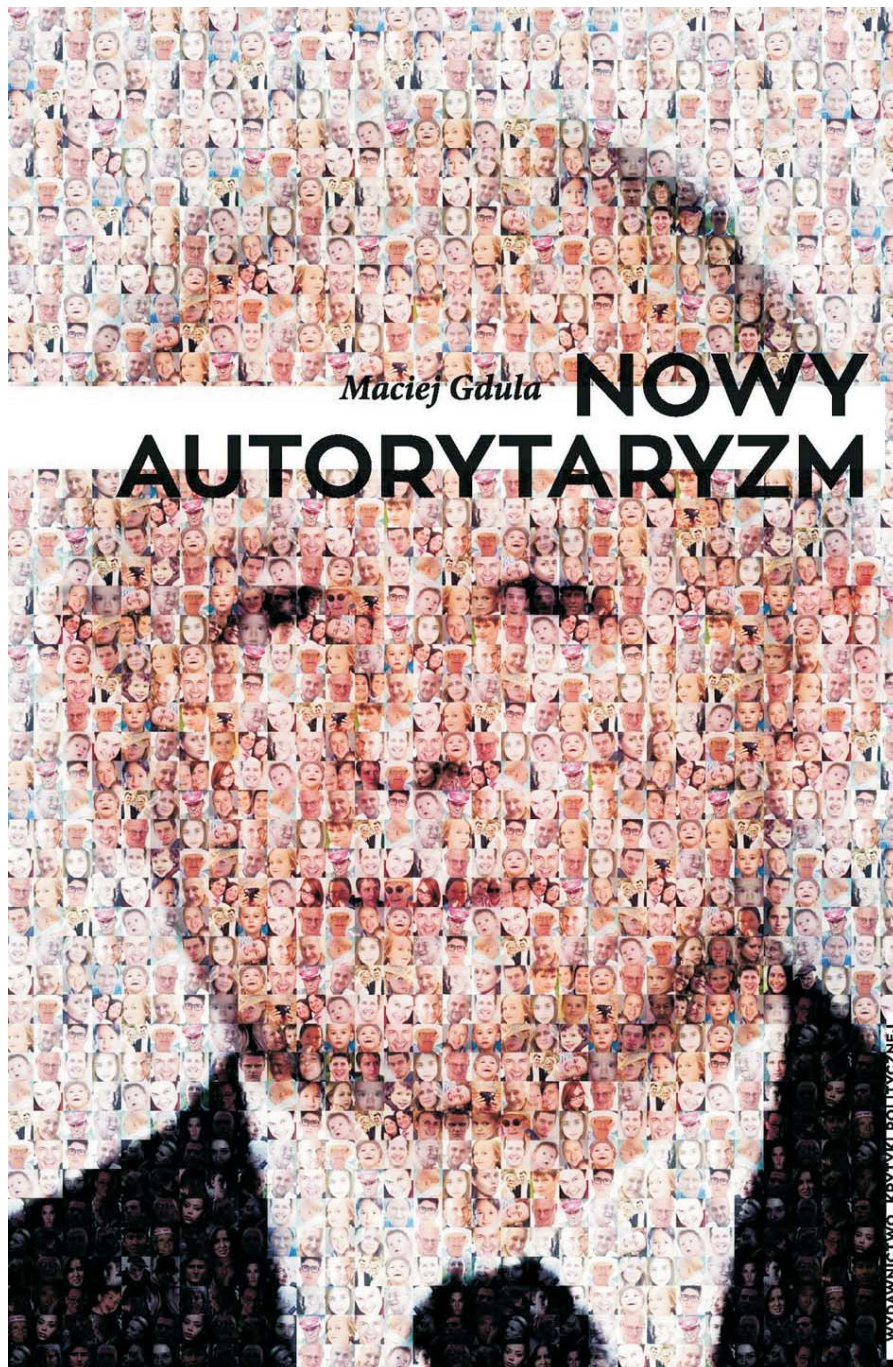
उसी समय, पीआईएस ने लोकतांत्रिक संस्थाओं (जैसे संवैधानिक ट्रिब्यूनल) को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया है, यह सभी लोकतंत्र और 'अच्छे परिवर्तन' के नाम पर हो रहा है। शोध ने अनावरण किया कि पीआईएस के अनुयायी स्वयं को 'लोकतांत्रिक' मानते हैं, लेकिन इसके उदार स्वरूप को खारिज करते हैं जो अनिवार्य रूप से आत्म सीमित है। मासीज गदुला इस नये प्रघटना को 'नव-सत्तावाद' शब्द से संबोधित करते हैं। गदुला के अनुसार हम एक नई प्रघटना का अवलोकन करते हैं : यह 'नव-सत्तावाद' जो सार्वजनिक क्षेत्र के कट्टरपंथी परिवर्तन (इंटरनेट के प्रभुत्व में न कि पूर्व में समाचारपत्रों द्वारा) और मतदाता और सत्तारूढ़ दल के नेता के मध्य एक विशिष्ट संबंध के लक्षणों से परिपूर्ण है।

हमारे शोध के परिणाम पुष्टि करते हैं कि दक्षिणपंथी दलों की सफलता की वर्तमान व्याख्याएं अब खत्म हो गई हैं। निष्कर्षों ने भारी सार्वजनिक ध्यान आकृष्ट किया है और एक व्यापक सार्वजनिक बहस जिसमें दोनों वाम और दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी जो पोलिश समाज के विभाजनों पर चर्चा में संलग्न हैं, को छोड़ा है। ■

सभी पत्राचार कतारज्याना देबस्का को <k.debska@is.uw.edu.pl>, सारा हर्स्जिंस्का को <sara.herczynska@gmail.com>, जुस्तयना कोसिंस्का को <j.koscinska@is.uw.edu.pl>, एवं कामिल ट्रेप्का को <k.trepka@is.uw.edu.pl> पर प्रेषित करें।

> नवीन सार्वजनिक क्षेत्र में समाजशास्त्र के लिए संभावनाएं

मासीज ग्डूला, वारसॉ विश्वविद्यालय, पोलैंड द्वारा



ग्डूला का नव सत्तावाद लोक समाजशास्त्र का अच्छा उदाहरण है।

नवम्बर 2017 में, उन चुनावों को, जिन्होंने लॉ और जस्टिस (पीआईएस) पार्टी को अपनी सरकार बनाने की अनुमति दी, को दो वर्ष हो गये हैं। यद्यपि इन दो वर्षों में उदार लोकतंत्र के कई नियमों का उल्लंघन हुआ, 40 फीसदी से अधिक मतदाताओं ने इस सरकार का समर्थन किया। इस समय पर मेरी रिपोर्ट 'मियास्तको में अच्छा परिवर्तन : एक छोटे शहर के परिपेक्ष्य से पोलिश राजनीति में नव-सत्तावाद' आई।

मध्य पोलैंड के एक छोटे शहर—मियास्तको में किये गये शोध पर आधारित इस रिपोर्ट ने एक गर्म चर्चा को भड़काया जिसमें पत्रकारों, राजनेताओं और वैज्ञानिकों ने कई हफ्तों तक भाग लिया। इसकी कुछ संकल्पनाएं और विवेचना राजनीति और समाज पर चल रही बहसों में लगातार संदर्भ का केन्द्र बन गई हैं। हालांकि रिपोर्ट की सफलता का जश्न मनाने के बजाय मैं इसकी संभावनाओं की सामाजिक स्थितियों के बारे में सोचना चाहूंगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र में समाजशास्त्र की उपस्थिति के लिए रणनीति पर पुनर्विचार करने और सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्णन ही नहीं बल्कि उन्हें प्रभावित करने की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यद्यपि मैं प्रमुख रूप से पोलिश संदर्भ में बात करता हूँ, यह पोलैंड में होने वाली प्रक्रियाओं के लिए अनूठा नहीं है।

> एक नया सार्वजनिक क्षेत्र

सार्वजनिक बहस पर पड़ने वाले प्रभाव को बढ़ाने हेतु समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर चिंतन करने के लिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले हालिया परिवर्तनों को ध्यान में रखना होगा। संक्षेप में, इनमें प्रेस के प्रभुत्व से इंटरनेट के प्राधान्य पर बदलाव सम्मिलित हैं। पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र — कम से कम राजनीति के सम्बन्ध में — प्रेस के इर्द-गिर्द आयोजित होता था, और 'सांस्कृतिक मध्यस्थ' — पत्रकार, विशेषज्ञ और राजनेता सार्वजनिक बहस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इंटरनेट के विस्तार ने आर्थिक और प्रतीकात्मक शक्ति दोनों रूप से मुद्रित प्रेस पर प्रहार किया। पोलैंड में यह प्रक्रिया तीव्र और नाटकीय थी। उदाहरण के लिए, सबसे बड़ा सामाचार पत्र गजेटा वाइबोर्जा ने 2005 और 2017 के मध्य अपने 75 फीसदी पाठकों को खो दिया।

इंटरनेट प्रभुत्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र में, सामग्री निर्माण का अधिक फैलाव है। यह बड़े वेबकास्ट्स, छोटी विशेषीकृत वेबसाइटों के साथ-साथ यू-ट्यूबरस जैसे एकल निर्माता जो अक्सर विशाल दर्शकों को जुटाते हैं, के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इन निर्माताओं के मध्य सामाजिक ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक तेज होती जा रही है जिसमें प्रतिक्रिया में त्वरिता, अधिक संघर्ष, लोकापवाद और नैतिकता पर जोर दिया जा रहा है।

> मध्यस्थों और समाजशास्त्र की कमजोरी

सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश में अवरोधों का कमजोर पड़ना, झूठी सूचनाओं और उन विमर्शों के प्रसार जो जानबूझ कर जवाबदेही को तोड़ता है, में परिवर्तित होता है जिससे 'पोस्ट-ट्रूथ' की अवधारणा का उदय होता है। सामाजिक ध्यान के लिए क्रूर प्रतिस्पर्धा सामग्री संकलन और जटिल पाठ्य सामग्री के उत्पादन की लंबी प्रक्रियाओं वाली पत्रकारिता को बाहर धकेल रही है। भिन्न मीडिया के अस्तित्व को सुरक्षित रखने का तरीका पहचान-संबंधित दर्शकों का सृजन करना है जो नैतिक श्रेष्ठता और भागीदारी की भावना से माध्यम से जुड़े हो और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा में इतनी भागीदारी न करते हों। जैसे एक सभ्यता के संघर्ष में।

सार्वजनिक मुद्दों पर राजनीति और चर्चा भी इन स्थितियों के साथ अनुकूलन करती है और राजनेता अतिवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हुए फोटो खींचने योग्य बयान देते हुए 'मीडिया लड़ाका' बन जाते हैं।

दर्शक त्वरित, आक्रामक और नैतिक संचार में भाग लेते हैं लेकिन महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों से सम्बन्धित ज्ञान के लिए जो उनका शोध के परिणामों के साथ सामना करता है के लिए अभी भी जगह है। उत्पादकों के मध्य तीव्र प्रतिस्पर्धा का अर्थ है कि सार्वजनिक बहस को निर्जलित किया जाता है और यह तेज टिप्पणी के दायरे में चलती है। पारंपरिक पत्रकारिता का समय और धन खत्म हो रहा है। इस स्थिति में यथार्थ की एक नई व्याख्या प्रस्तुत करने वाले समाजशास्त्रीय ज्ञान को बड़ी रुचि और प्रतिक्रिया से देखा जाता है और यह सार्वजनिक बहस की दिशा को प्रभावित करता है।

> वह समाजशास्त्र जो महत्वपूर्ण है

फिर ऐसे ज्ञान के सृजन के क्या नियम हैं? मियास्तको की रिपोर्ट और उसके स्वागत के आधार पर मैं कुछ सिद्धान्तों को प्रस्तुत करने का जोखिम उठाऊंगा।

सर्वप्रथम, जिस क्षण टेक्सट प्रकट होता है, महत्वपूर्ण है। पोलैंड में, पीआईएस के समर्थन के स्रोतों पर रिपोर्ट उस समय प्रकट हुई जब पूर्व में काम ली गई व्याख्याएं बहुत कम विश्वसनीय हो गई थीं। उदाहरण के लिए, आम विचार यह था कि जहां पीआईएस ने कुलीन वर्ग के साथ हिसाब तय करने का वादा किया था, तथापि इसने नये भ्रष्ट प्रवृत्ति वाले कुलन वर्ग उत्पन्न किये। फलस्वरूप अपने आदर्शों के साथ विश्वासघात करने के कारण इसके समर्थन में कमी आनी चाहिए थी। इस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ और पीआईएस को अभी भी 40 फीसदी आबादी का समर्थन प्राप्त है। रिपोर्ट ने इस प्रघटना को नव-सत्तावाद की धारणा से समझाया जो अन्य मुद्दों के साथ अपने कुलीन वर्ग को नियंत्रित करने एवं राजनैतिक परिवर्तन की दिशा की रक्षा करने में नेता की भूमिका को सम्बोधित करती है।

अध्ययन के प्रभावी होने के लिए, अविरत प्रक्रियाओं के साथ संकालन

महत्वपूर्ण है। निस्सन्देह, यह पूर्ण रूप से समाजशास्त्रियों पर निर्भर नहीं है लेकिन हम उत्पादन की गति के प्रश्न को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसे पारंपरिक अकादमिक उत्पादन से कहीं अधिक तेज होना होगा ताकि यह व्यापक दर्शकों के लिए प्रासंगिक मुद्दों से जुड़ सके। पीआईएस समर्थकों पर शोध को गहन करने के लिए, कई स्थानों पर अतिरिक्त शोध करना, साक्षात्कारों की संख्या में वृद्धि करना और उनकी गहन व्याख्या करना उपयुक्त होगा। समस्या यह है कि इन प्रयासों के परिणाम संभवतः उदाहरण के लिए अगले चुनावों के बाद, दिखाई दे सकते हैं जब वे केवल ऐतिहासिक होंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सहज ज्ञान के साथ संबंध है। अकादमिक विमर्श अधिक जटिल हो रहे हैं और शोध समस्याएं एवं उनके निष्कर्ष इस तरह निर्मित और प्रस्तुत किये जा रहे हैं कि वे एक शिक्षित पाठक के लिए भी चुनौतीपूर्ण हैं। सामाजिक प्रभाव को उत्पन्न करने वाले ज्ञान की रचना करते समय हमें व्यापक रूप से प्रसारित निर्णयों—चाहे हम या शायद विशेष रूप से तब जब हम उनसे असहमत हों, का उल्लेख करना चाहिए। उन्हें अपरिपक्वता, अज्ञानता, मानसिक सीमाओं इत्यादि के सबूत के रूप में अस्वीकार नहीं करना महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, बल्कि उन्हें सत्यापन के अधीन निर्णयों के रूप में देखना चाहिए।

मियास्तकों में हमारे शोध के मामले में, पीआईएस समर्थकों के संबंध में कई लोकप्रिय निर्णय थे। इनमें से एक यह विश्वास था कि पीआईएस समर्थक प्रमुखतः वे लोग हैं जो अपवर्जित हैं या कम से कम जिनमें गहरे नुकसान की भावना है। इसकी जीवनी साक्षात्कारों द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी, क्योंकि उत्तरदाताओं की बड़ी संख्या ने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता के संदर्भ में अपने जीवन के बारे में बात की। एक और धारणा जिस पर हमने ध्यान दिया वह यह मान्यता थी कि पीआईएस के लिए समर्थन फैमिली 500+ प्रोग्राम (पहले के बाद प्रत्येक शिशु के लिए लगभग 120 यूरो का मासिक लाभ) के तहत मिलने वाले धन के प्रति कृतज्ञता पर आधारित है। पीआईएस को मत देने वाले उत्तरदाताओं ने इस प्रोग्राम को निजी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले के रूप में परिभाषित नहीं किया

बल्कि इसे राज्य की एकजुटता के सबूत और एक ऐसे संकेत के रूप में व्याख्या की कि पोलैंड अंततः परिवारों को आसरा देने वाली व्यापक नीति बनाने वाले विकसित देशों में सम्मिलित हो रहा है।

तीसरा, समाजशास्त्रीय ज्ञान को सार्वजनिक विमर्श में जटिलता, जिसका अभी अभाव है, को दाखिल करना चाहिए। लोगों को सरलीकरण पसंद है लेकिन हर समय नहीं। यदि उनके अनुभवों और अभिमतों के साथ जुड़ने वाला ज्ञान है और जो उन्हें गहनता देता है या उनके साथ सम्बद्ध होता है तो वह उनकी रुचि का होगा। उदाहरण के लिए, मियास्तकों की रिपोर्ट पढ़ने वाले लोगों की निम्न और मध्यमवर्गीय पीआईएस समर्थकों के प्रतिनिधियों द्वारा सूत्रबद्ध कुलीन वर्ग की विभिन्न आलोचनाओं में रुचि थी। प्रथम के लिए, आलोचना कुलीन वर्ग के अलगाव और सामान्य लोगों से इसकी दूरी को इंगित करने पर आधारित थी। परवर्ती यानि कि मध्यम वर्ग के लिए, कुलीन वर्ग ने भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर शासन करने का जनादेश खो दिया था। काफी अर्से बाद यह पहला अवसर था जब पोलिश सार्वजनिक क्षेत्र में वर्ग-विविधता का विषय प्रस्तुत हुआ।

स्टिरिओटाइप्स के विपरीत, लोग जटिलता में रुचि रखते हैं और सामग्री की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह वैज्ञानिक

जटिलता के प्रदर्शन से कहीं अधिक होना चाहिए। संदेश को सरल बनाना, जिसमें सामाजिक ध्यान के लिए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा पैदा करने के उद्देश्य से ज्ञान को लोकप्रिय बनाना सम्मिलित है, भी समाजशास्त्रियों के लिए कोई मार्ग नहीं है। इसके बजाय, जटिलता को सामाजिक विमर्श में उत्तेजना और टकराव पैदा करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।

> समाजशास्त्र की भूमिका

हम ऐसे समाजशास्त्र से क्या प्राप्त कर सकते हैं जो सामाजिक प्रतिध्वनि वाला ज्ञान उत्पन्न करता है? यह जानते हुए कि ऐसा कोई उत्तर नहीं है जो सभी समाजशास्त्रियों को संतुष्ट करेगा मैं उन विकल्पों को सूचीबद्ध करूंगा जो मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

इस प्रकार के समाजशास्त्र के लिए संचार के मौजूदा स्वरूपों को संतुलित करने का एक अवसर है जिनमें अनुष्ठानिक संघर्षों में समाप्त होने की प्रवृत्ति है, जिसमें संदेश का क्रूरकरण और सरलीकरण सर्वोच्च है। हम इस स्थिति के लिए पत्रकारों और राजनेताओं को दोष नहीं दे सकते हैं। वे विशिष्ट स्थितियों में कार्य करते हैं जिनमें वे आसानी से सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं। हालांकि, ऐसा कोई कारण नहीं है कि समाजशास्त्रियों द्वारा ऐसे ज्ञान को प्रदान कर, जो हमारे सार्वजनिक

संचार में व्याप्त नकारात्मक प्रवृत्तियों में संतुलन पैदा करे, इन नियमों में छँटनी नहीं की जा सकती है।

समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण कार्य उन लोगों को आवाज प्रदान करना है जिनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत कम स्थान है। मेरे लिए, लोकप्रिय वर्गों के लिए स्थान बनाना और उनके परिपेक्ष्यों और अनुभवों को दर्शाना विशेषरूप से महत्वपूर्ण है।

तीसरा प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अन्य कर्त्ताओं के साथ समाजशास्त्र स्वयं को किस प्रकार स्थित करता है। मेरी राय में, इसे पत्रकारों और राजनेताओं के विरोधी के रूप में देखना सबसे निकट है। समाजशास्त्र अपनी संवेदनशीलता और प्रदत्त ज्ञान के साथ-साथ सामाजिक ध्यान के लिए प्रतिद्वंद्विता से स्वायत्तता और राजनैतिक संघर्षों के दबावों से दूरी के कारण भिन्न है। इस तरह का समाजशास्त्र सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य प्रतिभागियों पर सामाजिक यथार्थ को परिभाषित करने की उनकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाकर प्रतिभार पैदा कर सकता है। ■

सभी पत्राचार मासीज ग्डुला को
<gdujam@is.uw.edu.pl> पर प्रेषित करें।